प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड
Technology Development Board

२१ वां वार्षिक प्रतिवेदन
Twenty First Annual Report

वार्षिक प्रतिवेदन | Annual Report
२०१६-१७ | 2016-17

भारत सरकार
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
खण्ड–क, विश्वकर्मा भवन
शहीद जीत सिंह मार्ग,
नई दिल्ली–110016

सत्यमेव जयते

Government of India
Department of Science and Technology
Wing - A, Vishwakarma Bhawan,
Shaheed Jeet Singh Marg,
New Delhi - 110016

विषय–वस्तु

	विषय	पृष्ठ सं.
✧	बोर्ड के सदस्य	108
✧	टीडीबी – वर्ष एक दृष्टि में	113
✧	पूर्वावलोकन	121
✧	परियोजनाएं एवं उत्पाद	133
✧	प्रोन्नति संबंधी गतिविधियां	149
✧	अनुसंधान एवं विकास उपकर	165
✧	प्रशासन	169
✧	वर्ष 2016–17 का लेखा विवरण	173
✧	वर्ष 2016–17 के लिए पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट	201

Contents

	Particulars	Page No.
✧	Board Members	108
✧	TDB - Year at a glance	113
✧	Overview	121
✧	Projects and Products	133
✧	Promotional Activities	149
✧	Research & Development Cess	165
✧	Administration	169
✧	Accounts Statement for the year 2016-17	173
✧	Separate Audit Report for the year 2016-17	201

From Secretary's Desk

The year 2016-17 has been a very productive year for TDB! TDB continues its pathway of outreaching and encouraging established & new companies, Startups for funding to upscale and commercialize their products in various sectors. Many new personnel joined bringing in fresh ideas and energy. TDB received close to seventy-five project proposals, out of which fifty were shortlisted and fourteen agreements signed. TDB committed Rs. 275.77 crore against the project cost of Rs. 958.37 crore, maintaining the trend of generating co-investment thrice of TDB's investment. TDB enhanced its capacity of fund-utilization to double that of earlier years with no backlog in on-going projects. The Board met four times during the year and helped in speedy and effective decision-making. The project processing time has been reduced to 2-6 months and TDB officials are providing technical and financial mentoring to each applicant. TDB proactively made efforts to generate projects in critical areas and has been very successful in the area of Medical Devices. An interesting feature in TDB's funding during the year has been its capacity and decision in providing bigger loans in areas of critical national needs wherein indigenous scientific efforts have produced prototypes. TDB provided soft loan of Rs. 109.00 crore in a project costing Rs. 385.00 crore to TATA Power SED group for large scale manufacturing of Defence Products out of technologies licensed from DRDO labs. TDB supplemented funds to the efforts of M/s Biological E, Hyderabad towards fulfilling the national and international need of providing "Pneumococcal Vaccine" to India's National Immunization programme; and to WHO. The Dispute Resolution Committee met eight times and worked in conjunction with the One Time Settlement committee of the Board leading to enhanced recoveries.

TDB participated in many national and international events, exhibitions and held outreach workshops. On the sidelines of the visit of the Hon'ble Prime Minister to African countries, TDB with FICCI demonstrated its technologies in social development space for adoption, technology transfer and up-scaling in Kenya. An agreement was signed with the Economic Development Board of Andhra Pradesh on funding Medical Devices projects in "Medical cluster at Vizag". TDB renewed its agreement with WWF on Green Technologies. TDB also renewed its agreement with the Bpifrance, erstwhile OSEO, France, a public Sector Bank with CEFIPRA as the Management Body.

The INVENT programme initiated with DFID in 2015-16 has started showing results with twenty incubatees lodged in four incubators. The Millennium Alliance platform, a social enterprise conglomerate of TDB, FICCI, USAID, DFID, ICCO Foundation and the World Bank has by far funded 90 enterprises in four rounds. The Global Innovation & Technology Alliance, GITA, a Section 8 company of TDB, in partnership with CII, continues to manage Technology Development, Acquisition, Customization and Deployment activities of many Government and non-Governmental organizations. During the year, GITA forged a new alliance with the DRDO in their Technology Development Fund while expanding its domain with DST, DIPP, MSME and DHI.

TDB conferred the National Awards to many technology commercialization organizations. Hon'ble President of India accorded the awards in two categories. The Board has now decided to introduce a new "Startup Award" from the next year.

The year 2016-17 has been an effective year for TDB on all four fronts i.e. Technical, Legal, Finance and Administration. Being a unique techno-commercial body of the Government, it continues exploring spaces into Cyber security, Electric Mobility, Defence products and Green Energy through networking and collaborative spirit while entering into yet another challenging year!

Dr. Bindu Dey
Secretary, TDB

Vision & Mission

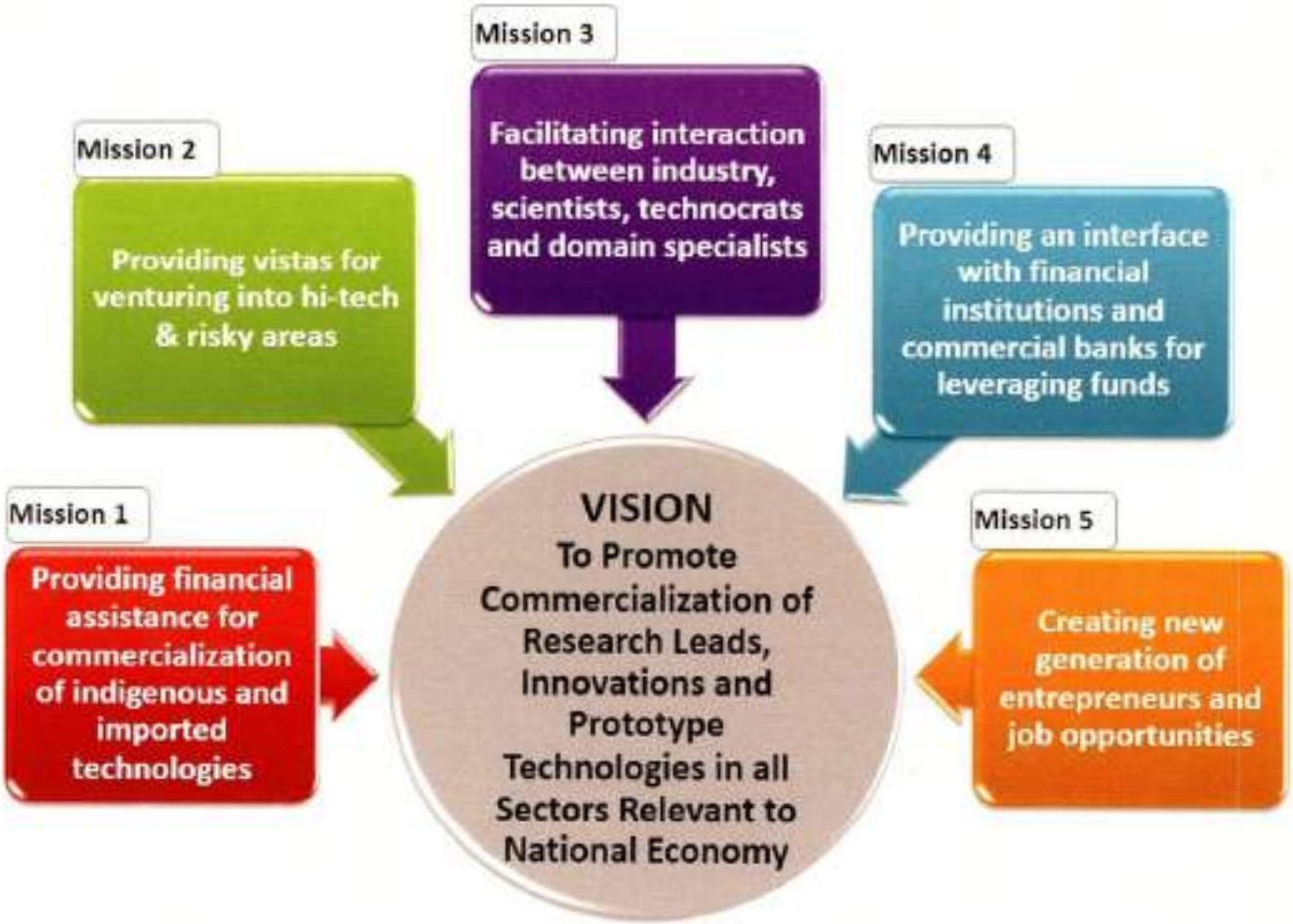

Objectives & Sectors Suppported

Objectives

Sectors Supported

प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड का गठन
(31 मार्च, 2017)

1.	**प्रो. आशुतोष शर्मा** सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	पदेन अध्यक्ष
2.	**डा. गिरीश साहनी** सचिव, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग	पदेन सदस्य
3.	**डा. एस. किस्टोफर** सचिव, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग	पदेन सदस्य
4.	**श्री अशोक लवासा** सचिव, व्यय विभाग	पदेन सदस्य
5.	**श्री रमेश अभिषेक** सचिव, औद्योगिक नीति एवं प्रोन्नयन विभाग	पदेन सदस्य
6.	**श्री अमरजीत सिन्हा** सचिव, ग्रामीण विकास विभाग	पदेन सदस्य
7.	**श्री एस. पी. शुक्ला** अध्यक्ष, महिन्द्रा एयरोस्पेश, मुम्बई	सदस्य
8.	**डा. अजय रंका** एम. डी., जाईडेक्स इंडस्ट्रीज, वडोदरा	सदस्य
9.	**श्री जी. श्रीरामाकृष्णा** भूतपूर्व–सीजीएम एसबीआई, सिकन्दराबाद	सदस्य
10.	**श्री प्रदीप गोयल** अध्यक्ष, प्रदीप मेटल्स लिमिटेड, नवी मुम्बई	सदस्य
11.	**डा. बिन्दु डे** सचिव, प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड	पदेन सदस्य (सदस्य सचिव)

बोर्ड के सदस्यों की फोटोग्राफ
(31 मार्च, 2017)

प्रो. आशुतोष शर्मा
अध्यक्ष एवं सचिव, डीएसटी

डॉ. गिरीश साहनी

डॉ. एस क्रिस्टोफर

श्री अशोक लवासा

श्री रमेश अभिषेक

श्री अमरजीत सिन्हा

श्री एस. पी. शुक्ला

डॉ. अजय रंका

श्री जी. श्रीरामाकृष्णा

श्री प्रदीप गोयल

डा. बिन्दु डे

श्री अशोक लवासा ने 2 मई, 2016 से सचिव, व्यय विभाग का कार्यभार श्री रतन पी. वतल के स्थान पर संभाला, श्री अमरजीत सिन्हा ने 1 अगस्त, 2016 से सचिव, ग्रामीण विकास विभाग का कार्यभार श्री जे. एस. माथुर के स्थान पर संभाला।

टीडीबी – वर्ष एक दृष्टि में

वर्ष 2016–17 प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड के लिए बहुत उत्पादक रहा क्योंकि विभिन्न औद्योगिक संगठनों के साथ वित्तीय सहायता के लिए 14 करार किया गया। इन करारों के माध्यम से टीडीबी ने 958.37 करोड़ रू. की कुल परियोजना लागत में से 275.77 करोड़ की प्रतिबद्धता की। टीडीबी की सहायता में रक्षा, चिकित्सकीय उपकरण, स्वास्थ्य, अभियांत्रिकी और सूचना प्रौद्योगिकी आदि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं।

वर्ष 2016–17 में प्राप्त आवेदन

वर्ष 2016–17 के दौरान टीडीबी ने विभिन्न औद्योगिक संस्थानों से 2788.20 करोड़ रू. की कुल परियोजना लागत में से 1128.31 करोड़ रू. की वित्तीय सहायता के लिए कुल 71 आवेदन प्राप्त किया। इनमें से लगभग 50 प्रस्तावों को वित्तीय सहायता के लिए अग्रिम कार्रवाई हेतु उचित पाया गया। जहां, 14 प्रस्तावों में करार पर हस्ताक्षर किया गया, अन्य प्रसंस्करण के विभिन्न चरण में हैं।

71 आवेदनों का राज्यवार वितरण निम्नलिखित है:–

(करोड़ रु. में)

क्र.सं0	राज्य / संघ शासित प्रदेश	आवेदनों की संख्या	कुल लागत	टीडीबी से मांगी गई सहायता
1	आंध्र प्रदेश	11	696.39	201.88
2	कर्नाटक	19	340.44	157.01
3	हरियाणा	4	32.75	15.26
4	मध्य प्रदेश	1	39.80	19.90
5	केरल	1	3.92	1.00
6	महाराष्ट्र	7	782.79	377.64
7	तमिलनाडु	6	106.51	46.97
8	तेलंगाना	1	11.49	3.00
9	पंजाब	2	50.37	8.82
10	गुजरात	5	497.96	161.71
11	उत्तर प्रदेश	3	22.60	11.12
12	गोवा	1	0.00	0.00
13	पश्चिम बंगाल	1	7.06	4.00
14	दिल्ली	7	194.82	118.5
15	झारखंड	1	1.30	0.50
16	अन्य	1	0.00	1.00
	कुल	71	2788.20	1128.31

कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे दक्षिणी राज्य टीडीबी से वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करने में सबसे आगे हैं।

क्षेत्र–वार प्राप्त आवेदनों का वितरण नीचे दिया गया है:

(करोड़ रु. में)

क.सं0	सेक्टर	आवेदनों की संख्या	कुल लागत	टीडीबी से मांगी गई सहायता
1	कृषि	15	537.67	310.52
2	टेक्सटाईल	1	5.25	2.09
3	इंजीनियरिंग	5	289.74	123.17
4	रक्षा	1	385.00	109.00
5	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा	28	1269.20	479.72
6	सूचना प्रौद्योगिकी	2	11.60	6.00
7	दूरसंचार	7	100.92	56.84
8	इलेक्ट्रॉनिक्स	1	9.60	4.00
9	केमिकल	4	40.42	16.51
10	नैनो विज्ञान	3	12.76	2.61
11	ऊर्जा एवं अपशिष्ट उपयोग	1	33.19	15.00
12	अन्य	3	92.85	2.85
	कुल	71	2788.20	1128.31

प्राइवेट लिमिटेड एवं पब्लिक लिमिटेड कंपनियों इत्यादि से प्राप्त आवेदनों को नीचे की तालिका में देखा जा सकता है:

(करोड़ रु. में)

श्रेणी	आवेदनों की संख्या	अनुमानित कुल लागत	टीडीबी से मांगी गई सहायता
प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियॉ	44	1450.22	558.32
पब्लिक लिमिटेड कम्पनियॉ	17	1280.37	532.68
अन्य	10	57.61	37.31
कुल	71	2788.20	1128.31

नए उत्पाद एवं सेवाएं

वर्ष के दौरान, टीडीबी ने नवोन्मेषी प्रौद्योगिकीयों के विकास एवं वाणिज्यीकरण हेतु निम्नलिखित परियोजनाओं को सहायता प्रदान करने के लिए 14 नये करारों पर हस्ताक्षर किए :

- मैसर्स एम्पेरे विहाईकल्स प्राईवेट लिमिटेड, कोयम्बटूर द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों के जरूरी भाग जैसे कि मोटर, चार्जर, कन्ट्रोलर, डीसी–डीसी कन्वर्टर का स्वदेशी विकास एवं वाणिज्यीकरण
- मैसर्स पेनेसिया मेडिकल टेक्नोलॉजी प्राईवेट लिमिटेड, बैंगलोर द्वारा स्वदेशी मेडिकल लाईनेक के उत्पादन लाईन की स्थापना एवं वाणिज्यीकरण
- मैसर्स सहजानन्द लेजर टेक्नोलॉजी लिमिटेड, गांधीनगर द्वारा फाईवर लेजर सिस्टम का वाणिज्यीकरण
- मैसर्स सोनोडाईन टेक्नोलॉजीज प्राईवेट लिमिटेड, कोलकाता द्वारा आवासीय एवं व्यवसायिक ऑडियो सेगमेंट्स के लिए विशेष डिजिटल ऑडियो हार्डवेयर समाधान
- मैसर्स बायोलॉजिकल ई लिमिटेड, हैदराबाद द्वारा न्यूमोकोकल वेक्सीन के लिए मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी
- मैसर्स सेन्विता बायोटेक्नोलॉजीज प्राईवेट लिमिटेड, हैदराबाद द्वारा पशु चिकित्सा में प्रयोग के लिए पैर–एवं–मुंह की बिमारियों (एफएमडी) वैक्सीन का विकास एवं वाणिज्यीकरण
- मैसर्स टाटा पावर कम्पनी लिमिटेड – स्ट्रेटजिक इंजीनियरिंग डिवीजन (टाटा पावर–एसईडी), बैंगलोर द्वारा वेमागल इंडिस्ट्रियल क्षेत्र, कोलर डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका के 50 एकड़ जमीन पर डिफेंस मैन्युफेक्चरिंग फैसिलिटी की स्थापना
- मैसर्स सॉफ्टटेक इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड, पूणे द्वारा रूल बड्डी उत्पाद (पहले "आर्थीटीएक्स") का विकास एवं वाणिज्यीकरण
- मैसर्स टर्मिनस सर्किट्स प्राईवेट लिमिटेड, बैंगलोर द्वारा हाई स्पीड सिरियल लिंक उत्पादों का वाणिज्यीकरण
- मैसर्स रेनालिक्स हेल्थ सिस्ट्म्स प्राईवेट लिमिटेड, बैंगलोर द्वारा ग्रामीण सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए एक सस्ते कनेक्टेड हेमोडायलिसिस मशीन का विकास
- मैसर्स इनर्गोस टेक्नोलॉजिज प्राईवेट लिमिटेड, मुंबई द्वारा उर्जा की आदतों का बदलाव
- मैसर्स आयटोम इलेक्ट्रिक इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, कोयम्बटूर द्वारा पोर्टेबल एक्स–रे मशीन का विकास एवं वाणिज्यीकरण
- मैसर्स डायबेटोमिक्स मेडिकल प्राईवेट लिमिटेड, हैदराबाद द्वारा मधुमेह की निगरानी के लिए नया, अभिनव, प्वाइंट ऑफ केयर नैदानिक परीक्षण का विकास एवं वाणिज्यीकरण
- मैसर्स सिस्टमेंटिक्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, बैंगलोर द्वारा औद्योगिक रोबोट्स का डिजाईन, विकास एवं उत्पादन

संवितरण

वर्ष 2016–17 के दौरान, चालू एवं नई परियोजनाओं और स्कीमों के लिए 110.68 करोड़ रु. की राशि का संवितरण किया गया। इस राशि में ऋण के रुप में 99.80 करोड़ रु., इक्विटी में निवेश के रूप में 0.47 करोड़ रू., अनुदान के रूप में 5.80 करोड़ रू. और वीसीएफ में निवेश के लिए 4.61 करोड़ रु. शामिल हैं।

पूरी की गई परियोजनाएं

टीडीबी द्वारा सहायता प्राप्त किसी भी कम्पनी ने वर्ष 2016–17 के दौरान अपनी परियोजना को पूर्ण घोषित नही किया।

ऋण चुकौती का निपटान

इस वर्ष, टीडीबी से सहायता प्राप्त निम्नलिखित कम्पनियों ने अपनी ऋण राशि का भुगतान किया और करार के अनुसार अपनी ऋण लेखाओं का निपटान किया:

- मैसर्स रोटोफिल्ट इंजीनियर्स लिमिटेड, अहमदाबाद
- मैसर्स सेमिक्स रिसर्च मैटेरियल प्राईवेट लिमिटेड, बरेली (यूपी)
- मैसर्स सहजानन्द लेजर टेक्नोलॉजी लिमिटेड, गांधीनगर, गुजरात
- मैसर्स उर्मी सिस्ट्म्स प्राईवेट लिमिटेड, हैदराबाद
- मैसर्स वेरिक्स टेक्नोलॉजिज प्राईवेट लिमिटेड, चेन्नई
- मैसर्स जेन टेक्नोलॉजिज लिमिटेड, हैदराबाद
- मैसर्स रविन्द्रनाथ जीई मेडिकल एसासिएट्स प्राईवेट लिमिटेड, हैदराबाद
- मैसर्स एंजल्स हेल्थ प्राईवेट लिमिटेड, नवी मुम्बई
- मैसर्स सेन्जाईम लिमिटेड, हैदराबाद
- मैसर्स सॉफ्टटेक इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड, पूणे

प्रौद्योगिकी दिवस

प्रौद्योगिकी दिवस 2016 का आयोजन 11 मई, 2016 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में "स्टार्टअप इंडिया के लिए प्रौद्योगिकी समर्थक" की थीम के साथ किया गया। भारत के माननीय राष्ट्रपति, श्री प्रणव मुखर्जी इस अवसर पर मुख्य अतिथि थे और डॉ. हर्षवर्धन, माननीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री ने समारोह की अध्यक्षता की।

इस अवसर पर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली (आईआईटीडी) के स्मीता रिसर्च लैब और अन्तराष्ट्रीय रिसर्च सेंटर फॉर पॉवर मेटालर्जी एवं न्यू मैटेरियल (एआरसीआई), हैदराबाद के सहयोग से विकसित एन9 शुद्ध सिल्वर के स्वदेशी विकास एवं वाणिज्यीकरण के राष्ट्रीय पुरस्कार मैसर्स रेसिल केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड, बेंगलोर को दिया गया। निम्न को एसएसआई इकाई पुरस्कार भी दिया गया:

1. मैसर्स आयटोम इलेक्ट्रिक इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, कोयम्बटूर को लागत प्रभावी हस्त आयोजित बैटरी संचालित पोर्टेबल एक्स–रे मशीन के वाणिज्यीकरण के लिए।
2. मैसर्स तेजस नेटवर्क्स लिमिटेड, बैंगलोर को टीजे1400 – पैकेट ट्रांसमिशन नोड – अभिनव, उच्च क्षमता, फाइबर ऑप्टिक नेटवर्किंग उत्पादों के वाणिज्यीकरण के लिए।

डॉ॰ हर्षवर्धन, माननीय मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा मैसर्स एक्वाएग्री प्रोसेसिंग प्राईवेट लिमिटेड द्वारा समुद्री शैवाल से विकसित उत्पाद को 11 मई, 2016 को प्रौद्योगिकी दिवस–2016 के दौरान विज्ञान भवन में वाणिज्यीक प्रमोचन किया गया। हालांकि, यह परियोजना वर्ष 2015–16 के दौरान पूर्ण हो चुकी थी।

टीडीबी समर्थित कम्पनियों ने एक प्रदर्शनी के माध्यम से अपनी उपलब्धियों का प्रदर्शन किया।

स्थापना दिवस

1 सितम्बर, 2016 को टीडीबी ने अपना 20वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर, 1 एवं 2 सितम्बर, 2016 "तकनीकी और अभिनव के माध्यम से वाणिज्यीकरण" के विषय पर दो दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। विषय के रूप में निम्नलिखित छः क्षेत्रों को चुना गया था: i) रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण की जटिलताएं, ii) साईबर सुरक्षा (आईटी), iii) रोबोटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स को दैनिक जीवन में एकीकृत करना, iv) नैनोविज्ञान एवं नैनोतकनीक: अतीत से वर्तमान, v) स्वच्छ एवं ग्रीन ऊर्जा: क्या हम मुद्दों पर गंभीर हैं, vi) स्वास्थ्य क्षेत्र में औद्योगिक हलचल। संगोष्ठी का समापन सत्र प्रौद्योगिकी नीति संरेखण पर था। सभी सत्र के लिए वक्ताओं को आध्यात्मिक और औद्योगिक क्षेत्र से आमंत्रित किया गया था। व्याख्यान के अलावा, इंडस्ट्रीज, डीआरडीओ, आर एंड डी संस्थान, नीति आयोग, फिक्की और सीआईआई के प्रतिनिधियों के बीच पैनल डिस्कसन भी हुआ।

सकारात्मक–सकिय भूमिका

प्रस्तावों के लिए "कॉल जारी करना" –बोर्ड ने निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों में "प्रस्ताव के लिए कॉल" जारी किया:

1. **जैवचिकित्सा उपकरणों एवं इन्स्ट्रूमेंटेशन** – टीडीबी ने इमेजिंग सामग्री सहित बायोमेडिकल डिवाईसेस एवं उपकरणों के स्वदेशी डिजाईन और निर्माण के लिए प्रस्ताव के लिए कॉल जारी किया।

2. **वायरलेस कम्यूनिकेशन तकनीक** – टीडीबी ने संचार सेवाओं में सुधार सहित सेलफोन कनेक्टिविटी में सुधार के लिए वायरलेस तकनीक में अभिनव और अग्रसरण तकनीक के लिए कई तकनीकी समाधानों के स्वदेशी विकास और व्यवसायीकरण के लिए इस उद्योग में महत्वपूर्ण खिलाड़ियों को शामिल करने के लिए प्रस्ताव का कॉल प्रकाशित किया।

3. **इनोवेटिव टेक्नोलॉजी फॉर फार्म स्टबल** – टीडीबी ने स्टबल के जलने से होने वाले हानिकारण आदतों और पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए एक अलग तरह के विचार के लिए इस क्षेत्र में काम कर रहे औद्योगिक इकाईयों को आमंत्रित करने के लिए एग्रो–वेस्ट मैनेजमेंट और प्रेवेंसन ऑफ स्टबल बर्निंग के लिए इनोवेटिव टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूसन के लिए प्रस्ताव के लिए कॉल जारी किया।

4. **नैनोसाइंस और नैनोटेक्नोलॉजी** – टीडीबी ने नैनो मिशन फेज–II के तहत "नैनो एप्लीकेशन और टेक्नोलॉजी विकास प्रोग्राम" के तहत नए उत्पाद, प्रक्रियाओं, डिजाईनों और प्रोटोटाईप के विकास और वाणिज्यीकरण के लिए प्रस्ताव का कॉल जारी किया।

5. **राष्ट्रीय पुरस्कार–2017 के लिए कॉल**– टीडीबी ने तीन श्रेणियों के तहत पुरस्कारों की घोषणा की: i) स्वदेशी तकनीक के विकास एवं वाणिज्यीकरण करने वाले औद्योगिक इकाईयों के लिए, ii) स्वदेशी तकनीक पर आधारित प्रौद्योगिकी उत्पाद का सफलतापूर्वक वाणिज्यीकरण करने वाले एमएसएमई, वाणिज्यीकरण की क्षमता वाले आशाजनक नई तकनीकी के लिए राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी स्टार्ट–अप पुरस्कार।

उद्यम पूंजी निधि (वीसीएफ) में भागीदारी– टीडीबी ने प्रौद्योगिकीय रुप से नवोन्मो व्यवहार्य उद्यमों को सहायता प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी केन्द्रित वीसीएफ के साथ नेटवर्किंग करना जारी रखा। 31 मार्च, 2017, टीडीबी ने 11 वीसीएफएस में 285.00 करोड़ रू. का निवेश किया तथा इनमें से पांच वीसीएफ में निवेश पर आय शुरु हो चुका है। निधि प्रबंधक, कुल निधि और टीडीबी की भागीदारी का विवरण नीचे दिया गया है:

(करोड़ रू. में)

क्रम सं	निधि का नाम	कुल निधि	टीडीबी की भागीदारी
1)	यूटीआई–इंडिया यूनिट वेंचर स्कीम (आईटीवीयूएस)	103.00	25.00
2)	बायोटेक्नोलॉजी वेंचर फंड	100.00	30.00
3)	यूटीआई–एसेंट इंडिया फंड–II	300.00	75.00
4)	वेंचर इस्ट टिनेट फंड–II	60.00	15.00
5)	एसएमई टेक्नोलॉजी वेंचर फंड	250.00	15.00
6)	एसएमई टेक फंड आरवीसीएफ– II	150.00	15.00
7)	इंडियन फंड फॉर सस्टेनेबल इनर्जी	75.00	10.00
8)	इंडिया अपर्चुनिटी फंड	1000.00	25.00
9)	सीफ इंडिया एग्रीबिजनेस फंड	125.00	25.00
10)	मल्टी सेक्टर सीड कैपिटल फंड	100.00	25. 00
11)	आईवीकैप वेंचर्स ट्रस्ट – फंड 1	200.00	25.00
	कुल	**2463.00**	**285.00**

इन्क्यूबेटर्स में शुरूआतकर्ताओं के लिए सीड सहायता योजना – वर्ष 2016–17 के दौरान 12 एवं 13 मई, 2016 को टीडीबी द्वारा अनुदान सहायता प्राप्त टीबीआईएस और एसटीईपीएस की समीक्षा की गई। सभी टीबीआईएस और एसटीईपीएस को समीक्षा समिति के सामने प्रस्तुतीकरण के लिए आमंत्रित किया गया। समिति ने यह पाया कि टीडीबी द्वारा शुरू किए गए सीड सहायता प्रणाली कि परिणामस्वरूप टीबीआईएस के पास शुरूआतकर्ताओं के मूल्यांकन, सलाह और निगरानी की एक मजबूत प्रणाली स्थापित हो गई है और टीबीआईएस एक जीवंत पारिस्थितिक तंत्र स्थापित करके उनकी स्थिरता भी सुनिश्चित कर सकें।

विदेशी संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन – टीडीबी ने दिनांक 10 मई, 2016 को नवीकृत टीडीबी–बीपीआईफ्रांस सहयोग, जिसमें सेफिप्रा एक प्रबंधन बॉडी है, के तहत एयरोनॉटिक्स, ऑटोमोटिव एवं जैवप्रौद्योगिकी के क्षेत्र की परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के उद्देश्य से "प्रस्ताव के लिए कॉल" जारी किया। "प्रस्ताव के लिए कॉल" के तहत ऑटोमोटिव का एक, एयरोनॉटिक्स के दो और स्वास्थ्य जैवप्रौद्योगिकी का एक मिलाकर कुल चार परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुए।

डब्ल्यूडब्ल्यूएफ–भारत के साथ क्लाईमेट सॉल्वर पार्टनर के लिए समझौता ज्ञापन – वर्ष 2016–17 के दौरान, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ–भारत के आग्रह पर, टीडीबी के करार की वैधता 21.05.2019 तक बढ़ा दिया है। क्लाईमेट सॉल्वर, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ के नवोन्मेषी कम कार्बन तकनीक के विकास एवं व्यापक उपयोग का मबजूती देने वाले वैश्विक पहल का एक हिस्सा है। क्लाईमेट सॉल्वर का उद्देश्य उनकी क्षमता का प्रदर्शन करना, उनके पहुंच का विस्तार करना और नवाचार के समग्र मूल के साथ जलवायु परिवर्तन का तत्काल और व्यवहारिक समाधान है।

इंवेंट प्रोग्राम – वर्ष 2016–17 के दौरान, इनोवेटिव वेंचर्स एंड टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपमेंप (इंवेंट) कार्यक्रम में प्रगति दर्ज की गई। कार्यक्रम को निम्न आय वर्ग के लिए सामाजिक और आर्थिक प्रभाव वाले तकनीकी और प्रक्रिया उन्मुख समावेशी नवाचार समाधान के लिए एक मंच बनाने के लिए तैयार किया गया।

मैसर्स विलग्रो इनोवेशन फाउंडेशन (वीआईएफ) मुख्य इन्क्यूबेटर के तौर पर कार्य कर रहा है तथा चार इन्क्यूबेटर्स को सहायता प्रदान कर रहा है। स्टार्ट–अप, ओसिस, जयपुर में 27–28 मार्च, 2017 के दौरान इंवेंट प्रोग्राम के पहले अर्ध–वार्षिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इंवेंट टीम और टीडीबी और डीएफआईडी के प्रतिनिधियों के साथ चार इन्क्यूबेटर्स और दस इन्क्यूबेटीज उपस्थित हुए। इन्क्यूबेटर्स और इन्क्यूबेटीज के द्वारा प्रोग्राम की प्रगति पर प्रस्तुति भी की गई। इसके अलावा, 28 मार्च, 2017 को विलग्रो द्वारा स्टार्ट–अप ओसिस, जयपुर में इंवेंट इन्क्यूबेटर्स के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन की योजना भी की गयी।

ग्लोबल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी अलायंस (जीआईटीए) – गीता ने वर्ष के दौरान कई समझौतों पर हस्ताक्षर किये, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी विकास कोष (टीडीएफ) योजना के तहत गतिविधियों के लिए डीआरडीओ के साथ हस्ताक्षरित करार था।

मिलेनियम अलायंस (एमए) – एमए ने वर्ष 2016–17 के दौरान अपने पहले तीन दौर के चयन प्रकिया को पूरा किया एवं कार्यक्रम के तहत सहायता के लिए सामाजिक महत्व के लगभग 60 परियोजनाओं का चयन किया।

प्रदर्शनियां / सेमिनार – टीडीबी से उपलब्ध सहायता के बारे में उद्योग, उद्यमियों और अनुसंधान एवं विकास संस्थानों में जागरूकता पैदा करने के लिए, टीडीबी ने अन्य संगठनों के साथ मिलकर विभिन्न गतिविधियों जैसे प्रदर्शनियों / इंटरैक्टिव मीटिंग इत्यादि में भाग लिया।

पूर्वावलोकन

प्रस्तावना

भारत सरकार द्वारा प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड अधिनियम, 1995 के प्रावधनों के अंतर्गत सितम्बर, 1996 में स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास एवं वाणिज्यिक अनुप्रयोग का प्रयास अथवा व्यापक घरेलू अनुप्रयोग हेतु आयातित प्रौद्योगिकी को अपनानें को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड का गठन किया गया।

इस अधिनियम में टीडीबी द्वारा संचालित प्रौद्योगिकी विकास तथा अनुप्रयोग के लिए फंड सृजन का प्रावधान है। इस फंड द्वारा सरकार से अनुसंधान एवं विकास उपकर अधिनियम, 1986 यथा संशोधित 1995 के प्रावधानों के तहत औद्योगिक इकाइयों से एकत्रित अनुसंधान एवं विकास उपकर में से भारत सरकार से अनुदान प्राप्त किया जाता है। फंड की राशि के निवेश से प्राप्त आय और फंड द्वारा दिए गए अनुदानों की वसूली को फंड में जमा कर दिया जाता है। वित्त अधिनियम, 1999 द्वारा आयकर संबंधी उद्देश्यों के लिए फंड को दिए गए अनुदानों में पूर्ण कटौती करने हेतु सक्षम बनाया गया।

वर्ष 1996–97 से 2016–17 की अवधि के दौरान आर एंड डी उपकर से सरकार द्वारा कुल 7974.32 करोड़ रु. एकत्र किए गए। इसमें से टीडीबी को 20 वर्षों की अवधि में 609.47 करोड़ रु. की संचित राशि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के गैर–योजना व्यय में से अनुदान सहायता के रूप में उपलब्ध कराया गया।

टीडीबी का दायित्व स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास एवं वाणिज्यिक अनुप्रयोग का प्रयास करना अथवा व्यापक घरेलु अनुप्रयोग हेतु आयातित प्रौद्योगिकी को अपनानें वाली औद्योगिक इकाईयों तथा एजेंसियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है।

वित्तीय सहायता का तरीका

टीडीबी को अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों सें वित्तीय सहायता हेतु आवेदन वर्ष भर प्राप्त होते रहते हैं। टीडीबी द्वारा वित्तीय सहायता ऋण या इक्विटी के रुप में तथा आपवादिक मामलों में अनुदान के रुप में उपलब्ध है।

ऋण सहायता अनुमोदित परियोजना लागत के 50 प्रतिशत तक दी जाती है और इस पर प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत साधारण ब्याज लिया जाता है। ऋण अवधि के दौरान टीडीबी की सहायता से उत्पादित उत्पाद की बिक्री पर रॉयल्टी भी देय है। टीडीबी आवेदक से कोई भी प्रशासनिक, संसाधन या प्रतिबद्धता शुल्क नहीं लेता है। ऋण राशि का भुगतान ऋण करार के तहत उद्धृत नियम एवं शर्तों एवं माइलस्टोन के अनुपालन के आधार पर किश्तों में किया जाता है। कुछ मामलों में, सहायता प्राप्त औद्योगिक इकाई के निदेशक मंडल में टीडीबी द्वारा नामित निदेशक भी शामिल होते हैं। परियोजना की कार्यान्वयन अवधि सामान्य तौर पर तीन वर्ष से अधिक नहीं होती। ऋण एवं ब्याज को कोलेटरल एवं गारंटी के माध्यम से सुरक्षित किया जायेगा। सामान्यतया ऋण एवं ब्याज का पुनःभुगतान की शुरूआत परियोजना के सफलतापूर्वक पूरा हो जाने के एक वर्ष के बाद होता है और इसका भुगतान साढ़े चार साल में किया जाता है। पहली किस्त के पुनःभुगतान तक जमा ब्याज के भुगतान को तीन वर्षों में वितरित किया जाता है और जो कि पुनःभुगतान के दूसरे वर्ष के शुरू होकर पुनःभुगतान के चौथे वर्ष के साथ पूरा हो जाता है।

टीडीबी किसी औद्योगिक कंपनी (कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन) में इसके आरंभ होने, चलाने और / अथवा टीडीबी द्वारा अपेक्षाओं के यथा मूल्यांकित किये गये जरुरतों के अनुसार और संवृद्धि स्तरों पर ऋण – इक्विटी अनुपात को ध्यान में रखते हुए इक्विटी पूंजी के रुप में अंशदान कर सकता है।

इक्विटी अंशदान टीडीबी के पूरे बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाता है। यह स्वीकृत परियोजना लागत का 25 प्रतिशत तक होता है बशर्ते यह प्रोत्साहकों द्वारा चुकता पूंजी से अधिक न हो। औद्योगिक कंपनी को टीडीबी द्वारा अंशदान की धनराशि के समतुल्य अपने शेयर प्रमाण पत्र टीडीबी को जारी करने होंगे। अंशदान पूर्व स्थितियों में यह शामिल होगा कि प्रोत्साहकों का अंशदान होना चाहिए और अपने हिस्से की शेयर पूंजी को पूर्ण रुप से चुकता किया जाना चाहिए। प्रोत्साहकों को टीडीबी के अंशदान के बराबर अपने शेयर टीडीबी को गिरवी रखना चाहिए। टीडीबी को ऐसी कंपनियों के निदेशक मंडल में नामित निदेशक (को) को रखने का अधिकार है। टीडीबी का यह विवेकाधिकार है कि वह (इक्विटी पूंजी) विनियमनों में निर्धारित प्रकिया के अनुसार परियोजना पूरी हो जाने के तीन वर्षों के पश्चात् अथवा अंशदान की तिथि से पांच वर्षों के पश्चात् कंपनी में अपनी शेयर होल्डिंगस को समाप्त कर सकती है। तथापि, शेयरों को वापस खरीदने का पहला विकल्प संस्थापकों के पास होगा।

टीडीबी औद्योगिक कंपनियों के विद्यमान ऋण अथवा इक्विटी के प्रतिस्थापन पर विचार नहीं करता जिन्होंने इस प्रकार का ऋण अन्य संस्थानों से लिया है।

टीडीबी स्वदेशी रुप से प्रौद्योगिकी को विकसित करने में शामिल औद्योगिक कंपनियों और आर एण्ड डी संस्थानों को अनुदान के रुप में भी वित्तीय सहायता मुहैया कराता है। अनुदानों की स्वीकृति का निर्णय टीडीबी बोर्ड द्वारा किया जाता है और इसे राष्ट्रीय महत्व के विशेष मामलों में ही मुहैया किया जाता है।

31 मार्च, 2017 तक, टीडीबी द्वारा (1996 में इसके अस्तित्व में आने के बाद से) 7219.80 करोड़ रु. की कुल परियोजना लागत युक्त कुल 330 करारों पर हस्ताक्षर किया है जिसमें से टीडीबी की बचनवद्धता 1771.61 करोड़ रु. की है जिसमें से टीडीबी ने सरकार द्वारा दिए गए फंड और आंतरिक प्राप्तियों में से 1408.24 करोड़ रु. का संवितरण किया है।

टीडीबी द्वारा 31 मार्च, 2017 तक दी गई वित्तीय सहायता के तरीकों को निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

(करोड़ रु. में)

साधन	टीडीबी द्वारा स्वीकृत	टीडीबी द्वारा वितरीत
ऋण	1304.54	983.44
इक्विटी	33.06	34.66
अनुदान	149.01	143.73
वेन्चर फंड	285.00	246.41
कुल	**1771.61**	**1408.24**

करारों का क्षेत्रवार कवरेज

टीडीबी की वित्तीय सहायता ने अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्षेत्रों को कवर कर लिया है। निम्नलिखित तालिका में टीडीबी द्वारा 1996–97 में इसके गठन से 31 मार्च, 2017 तक क्षेत्रवार स्वीकृत की गई परियोजनाओं को दिखाया गया है:–

(करोड़ रु. में)

क्रम सं.	सेक्टर	करारों की संख्या	कुल लागत	टीडीबी द्वारा स्वीकृत
1	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा	84	1747.21	491.40
2	इंजीनियरिंग	66	664.40	239. 23
3	सूचना प्रौद्योगिकी	42	374.07	146.01
4	केमिकल	23	206.07	71.99
5	कृषि	21	141.55	47.40
6	दूरसंचार	12	99.88	37.85
7	सड़क यातायात	10	527.04	81.20
8	ऊर्जा और अपशिष्ट उपयोगिता	8	132.36	55.98
9	इलेक्ट्रोनिक्स	4	52.56	17.75
10	हवाई यातायात	1	131.38	64.90
11	रक्षा एवं नागर विमानन	9	517.45	165.05
12	अन्य			
	(क) वेन्चर फंड	11	2463.00	285.00
	(ख) एसटीईपी – टीबीआई	35	35.00	35.00
	(ग) सीआईआई	1	0.83	0.50
	(घ) मिलेनियम अलायंस	1	112.00	25.00
	(ङ) ग्लोबल इनोवेशन एंड टेक्नॉलोजी अलायंस (जीआईटीए)	1	15.00	7.35
	(च) इवेंट प्रोग्राम	1	-	-
	कुल	**330**	**7219.80**	**1771.61**

इसमें अन्य क्षेत्रों की तुलना में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा एवं इंजीनियरिंग क्षेत्रों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। टीडीबी द्वारा दी गई सहायता विस्तृत रुप से नए वेन्चरों और विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में बाजार संचालित और प्रौद्योगिकी उन्मुखी है।

वर्ष 1996–2017 के दौरान करारों का राज्यवार वितरण

वर्ष 1996–2017 के दौरान हस्ताक्षर किए गए करारों (कम्पनी के रजिस्टर्ड कार्यालय के आधार पर) का राज्यवार वितरण :

(करोड़ रु. में)

क्रम सं.	राज्य, केन्द्र शासित	करारों की संख्या	कुल लागत	टीडीबी द्वारा स्वीकृत की गई ऋण, अनुदान / इक्विटी
1	आन्ध्र प्रदेश	85	1673.57	539.44
2	कर्नाटक	41	920.58	322.84
3	महाराष्ट्र	41	763.5	145.9
4	तमिलनाडु	36	309.24	95.78
5	दिल्ली	19	230.8	74.65
6	गुजरात	13	147.88	45.52
7	पश्चिम बंगाल	9	121.58	51.26
8	उत्तर प्रदेश	7	52.03	33.88
9	मध्य प्रदेश	6	154.23	41.5
10	हरियाणा	6	44.15	18.00
11	पंजाब	5	52.20	14.46
12	चंडीगढ़	4	43.75	16.5
13	केरल	3	19.03	7.15
14	हिमाचल प्रदेश	1	6.24	1.90
15	जम्मू एवं कश्मीर	1	5.65	2.38
16	मणिपुर	1	7.94	2.70
17	पांडीचेरी	1	5.83	1.90
18	राजस्थान	1	35.77	3.00
19	अन्य सहित			
	वेन्चर फंड	11	2463.00	285.00
	एसटीईपी – टीबीआई	35	35.00	35.00
	सीआईआई	1	0.83	0.50
	मिलेनियम अलायंस	1	112.00	25.00
	ग्लोबल इनोवेशन एंड टेक्नॉलोजी अलायंस (जीआईटीए)	1	15.00	7.35
	इवेंट प्रोग्राम	1	–	–
	कुल योग	**330**	**7219.80**	**1771.61**

अपने उद्देश्य के अनुसार टीडीबी की सहायता अखिल भारतीय आधार पर दिया गया है। हालांकि, उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि भारत के दक्षिणी राज्यों में स्थित कंपनीयों ने टीडीबी की वित्तीय सहायता का अधिकतम लाभ उठाया है क्योंकि वे टीडीबी में सहायता के लिए आवेदन करने में सक्रिय रहें हैं।

परियोजना प्रस्तावों को संशोधित करना

टीडीबी से ऋण सहायता की अपेक्षा रखने वाली औद्योगिक इकाई को एक निर्धारित प्रपत्र में आवेदन जमा करना होता है। प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड की वित्तीय सहायता के लिए निर्धारित और अन्य विवरण मांग के आधार पर उपलब्ध 'परियोजना वित्तपोशण निर्देशिका' में उपलब्ध है। संबंधित उद्योग अथवा उद्यमी / प्रोत्साहक आवेदन का प्रपत्र टीडीबी की वेबसाईट www.tdb.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं एवं http://e-techcom.tdb.gov.in पर ऑनलाईन आवेदन भी कर सकते हैं। टीडीबी वर्ष भर आवेदन प्राप्त करता है।

आवेदनों की प्रारंभिक जांच

प्रारंभिक जांच समिति (आईएससी) वित्तीय सहायता के लिए प्राप्त आवेदनों को उसके पूर्णता, परियोजना का उद्देश्य एवं प्रौद्योगिकी की स्थिति आदि की दृष्टि से जांच करती है। इस तरह की जांच में आवेदक और तकनीकी प्रदाता द्वारा एक विधिवत गठित तकनीकी–सह–वित्तीय आईएससी के सामने औपचारिक प्रस्तुतिकरण शामिल है। आकलन और स्पष्टता के लिए अतिरिक्त जानकारी / विवरण या दूसरी प्रस्तुति भी आवश्यक हो सकती है। यदि आवेदन टीडीबी की वित्तीय सहायता के लिए निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं करती है, तो आईएससी आगे की प्रकिया के लिए इसकी सिफारिश नहीं करने के लिखित कारणों के साथ आवेदन को अस्वीकार कर सकती है।

परियोजना मूल्यांकन समिति (पीईसी)

आईएससी की सिफारिशों के आधार पर आवेदनों को परियोजना मूल्यांकन समिति (पीईसी) को भेजा जाता है। प्रत्येक परियोजना के लिए उसकी प्रकृति और उत्पादन को ध्यान में रखते हुए पीईसी का गठन किया जाता है और परियोजना के स्वतंत्र मूल्यांकन के लिए टीडीबी के बाहर से संबंधित क्षेत्रों (विज्ञान, तकनीकी एवं वित्तीय) के विशेषज्ञों को इस समिति में शामिल किया जाता है।

विशेषज्ञ (सेवारत अथवा सेवानिवृत्त) सरकारी विभागों, आर एंड डी संगठनों, शैक्षिक संस्थानों, उद्योग संघों, वित्तीय संस्थानों और व्यावसायिक बैंकों के हो सकते हैं। आवेदन को प्रौद्योगिकी प्रदानकर्त्ता सहित वैज्ञानिकी, तकनीक, मार्केटिंग, वाणिज्यिक तथा वित्तीय प्रस्तुतीकरण की विस्तृत जानकारी देने एवं परियोजना एवं कम्पनी से जुड़े मुद्दों पर जानकारी देने का पूरा अवसर दिया जाता है।

उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति (एचएलईसी)

लंबित एवं आगामी परियोजना प्रस्तावों के मूल्यांकन में तेजी लाने के कम में, अध्यक्ष, टीडीबी ने (वर्ष 2011–12 से) इन परियोजना प्रस्तावों के स्वतंत्र मूल्यांकन के लिए एक नामचीन व्यक्तित्त्व की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति (एचएलइसी), जिसमें कि टीडीबी के बाहर के उस क्षेत्र के ख्याति प्राप्त विशेषज्ञ (वैज्ञानिक, तकनीक, शिक्षा, मार्केटिंग एव वित्तीय) शामिल है, का गठन किया।

बोर्ड ने 18 फरवरी, 2012 को आयोजित अपनी 49वीं बैठक में उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिती (एचएलईसी) द्वारा परियोजना प्रस्तावों के मूल्यांकन की नई प्रकिया पर काफी विचार विमर्श किया। बोर्ड ने प्रस्तावों पर कार्य करने के समय लागत को घटाने के लिए उठाए गए कदमों की सराहना व अनुमोदन किया।

मूल्यांकन मानदण्ड

आवेदनों को वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय, वाणिज्यिक एवं वित्तीय प्राथमिकता के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है। मूल्यांकन प्रकिया में निम्नलिखित शामिल है :–

- प्रस्ताव के विषयों का अनूठा एवं नवीनात्मक होना
- सुदृढ़ता, वैज्ञानिक गुणवत्ता और प्रौद्योगिकीय प्राथमिकता
- वृहत रुप से लागू करने के लिए और वाणिज्यीकरण से लाभप्रद संभावना
- प्रस्तावित प्रयास की पर्याप्तता
- प्रस्तावित कार्यवाही नेटवर्क में आर एंड डी संस्थानों की क्षमता
- आंतरिक प्राप्ति सहित एंटरप्राइज की संगठनात्मक एवं वाणिज्यिक योग्यता
- प्रस्तावित लागत और वित्त पोषण के तरीके की औचित्यपूर्णता
- मापयोग्य उद्देश्य, लक्ष्य और निर्धरित लक्ष्य
- उद्यमी का पिछला रिकॉर्ड

गोपनीयता एवं पारदर्शिता

टीडीबी में यह मान्यता है कि गोपनीयता को बनाए रखना महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रत्येक प्रस्ताव एक वाणिज्यिक प्रस्ताव है जिसमें एक नया उत्पादन अथवा प्रकिया शामिल है। अगर आवेदक द्वारा यह बताया जाता है कि परियोजना प्रस्ताव में उद्धृत कुछ जानकारी को गोपनीय रखा जाये, तो इसे परियोजना मूल्यांकन समिति एवं उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति के विशेषज्ञों को परिचालित नही किया जाता है। पीईसी या एचएलईसी प्रकिया में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों का खुलासा न करने की आवेदकों की आशंकाओं की संवेदनशीलता को ध्यान में रखा जाता है।

आवेदकों के साथ पूर्ण रुप से विचार विमर्श करने के पश्चात् पीईसी / एचएलईसी के विशेषज्ञों द्वारा टिप्पणियों और सिफारिशों को अंतिम रुप दिया जाता है। एचएलईसी से मंजूर हुए सभी प्रस्तावों को प्रौद्योगिकी – आर्थिक व्यवहार्यता / यथोचित परिश्रम के माध्यम से मूल्यांकन के लिए भेजा जाता है। तथापि यदि परियोजना में टीडीबी की सहायता 10.00 करोड़ रू से अधिक हो या कुल परियाजना लागत 30.00 करोड़ रू. के अधिक हो तो केवल उसी स्थिति में पीईसी द्वारा यथोचित परिश्रम के लिए मामलों की सिफारिश की जाती है। पीईसी अथवा एचएलईसी की सिफारिशें अनुमोदनार्थ बोर्ड को भेजी जाती है। यदि परियोजना प्रस्ताव की पीईसी / एचएलईसी द्वारा सिफारिश नहीं की जाती तक आवेदन को टीडीबी द्वारा बंद कर दिया जाता है और आवेदक को सूचित कर दिया जाता है।

वित्तीय सहायता का अनुमोदन

पीईसी द्वारा अनुशंसित उन सभी परियोजनाओं को जिनमें या तो परियोजना लागत 30 करोड़ रू. से अधिक हो या टीडीबी के मांगी गई सहायता 10.00 करोड़ रू से अधिक हों, को टीडीबी के साथ सूचिगत एवं अनुमोदित परिसम्पत्ति प्रबंधक द्वारा ड्यू–डिलिजेंस से गुजरना होता है। एचएलईसी द्वारा अनुशंसित परियोजनाओं को अनिवार्य रूप से टीडीबी के साथ सूचिगत एवं अनुमोदित परिसम्पत्ति प्रबंधक द्वारा ड्यू–डिलिजेंस से गुजरना होता है। पीईसी या एचएलईसी की अनुशंसा, ड्यू–डिलिजेंस रिपोर्ट (जहां लागू हो) के साथ बोर्ड के सामने अनुमोदन के लिए रखा जाता है।

पीईसी या एचएलईसी द्वारा अनुशंसित नही होने वाले परियोजना प्रस्तावों को आवेदक को सूचित करने के बाद बंद कर दिया जाता है।

उपरोक्त मूल्यांकन स्तरों को पूरा करने के बाद, 2.50 करोड़ रू. के परियोजना प्रस्तावों को अध्यक्ष, टीडीबी द्वारा अनुमोदित किया जाता है, 2.50 करोड़ रू. से 10.00 करोड़ रू. के बीच के परियोजना प्रस्तावों को बोर्ड की उप–समिति के द्वारा अनुमोदित किया जाता है और 10.00 करोड़ रू. से अधिक के परियोजना प्रस्तावों को बोर्ड के द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

अनुविक्षण एवं समीक्षा

टीडीबी अनुमोदित सहायता लाभअर्जकों को किस्तों में उपलब्ध कराता है जो कि जोखिम सम्बंधित लक्ष्यों पर आधारित होता है। दूसरी और अगली किश्तों को प्रत्येक अनुमोदित परियोजना के लिए गठित की गई परियोजना अनुविक्षण समिति (पीएमसी) की सिफारिशों के आधार पर जारी किया जाता है। परियोजना अनुविक्षण समिति मे उन वैज्ञानिक / तकनीकि एंव वित्तीय विशेषज्ञों को शामिल किया जाता है जो कि परियोजना मूल्यांकन के समय पीईसी / एचएलईसी के सदस्य थे।

सकारात्मक – सकिय भूमिका

औद्योगिक इकाईयों और अन्य एजेंसियों से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों का जबाव देने के अलावे प्रौद्योगिकी विकास एवं वाणिज्यीकरण के लिए व्यापक समर्थन सुनिश्चित करने के लिए टीडीबी एक सकिय भूमिका निभाता है। टीडीबी ने दायित्व के निर्वहन के लिए उपरोक्त पहल के माध्यम से स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास और वाणिज्यीकरण को प्रोत्साहित किया है।

(क) वेंचर कैपिटल फंड (वीसीएफ) में भागीदारी

टीडीबी ने एसएमई / प्रारंभिक चरण के उपकमों के माध्यम से तकनीकी नवाचार के लिए व्यवहारिक उद्यमों को समर्थन करने के लिए तकनीकी केंद्रित वीसीएफ में भागीदारी की। चयनात्मक आधारपर उच्च–जोखिम और उच्च–वापसी वाले वीसीएफ में टीडीबी की भागीदारी को तकनीकी उन्मुख परियोजनाओं के भौगोलिक और तकनीकी विस्तार के लिए एक उत्कृष्ट उपकरण माना गया है।

बोर्ड ने मार्च, 2010 में अपनी 44वीं बैठक में उद्यम पूंजी निधि हेतु टीडीबी द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता पर विचार और समीक्षा करने तथा टीडीबी द्वारा वीसीएफ को सहायता प्रदान करने में अपनाई जाने वाली कार्य पद्धति पर सुझाव देने के लिए एक समिति का गठन करने का निर्णय लिया। बोर्ड ने मई, 2010 में अपनी 45वीं बैठक के दौरान वीसीएफ में टीडीबी की भागीदारी हेतु व्यापक दिशा–निर्देश को भी अंतिम रुप प्रदान किया।

तक से, 31 मार्च, 2017, टीडीबी ने 11 वीसीएफएस नामतः एपीआईडीसी, यूटीआई–एआईएफ, यूटीआई–आईटीवीयूएस, वेंचर ईस्ट टिनेट फन्ड–II, जीवीएफएल–एसएमई टेक्नोलॉजी वेंचर फंड, आरवीसीएफ–एसएमई टेक फंड आरवीसीएफ–II, सीआईआईई–इंडियन फंड फॉर सस्टेनेबल एनर्जी, सिडबी–इंडिया अपर्चुनिटी फंड, सीफ–सीफ इंडिया एग्रीबिजनेस फंड, ब्लूम वेंचर का – मल्टीसेक्टर सीड कैपिटल फंड एवं आइवीकैप वेंचर का–आइवीकैप वेंचर्स ट्रस्ट फंड–1 में भागीदारी की। इन निधियों से नवोन्मेशी परियोजनाओं में निवेश को विस्तार देने के लक्ष्य के साथ आईटी/आईटीईएस, जैवप्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, दूरभाष, नैनो–टेक्नोलॉजी, क्लीनटेक इनर्जी और एग्रीबिजनेस के क्षेत्र के अभिनव परियोजनाओं के लिए सह–निवेश को लक्षित किया गया है। टीडीबी की कुल प्रतिबद्धता 285.00 करोड़ रू. की है तथा इनमें से पांच वीसीएफ में निवेश पर आय शुरु हो चुका है।

टीडीबी की प्रेरणा एवं भागीदारी ने उद्यम पूंजीपतियों को टीडीबी के मिशन के लिए सहायता के लिए प्रेरित किया। टीडीबी की इस पहल ने प्राईवेट इक्विटी फंड को भारतीय अर्थव्यवस्था के चालक क्षेत्रों वाले तकनीकी आधारित परियोजनाओं को समर्थन देने का विश्वास दिलाया।

(ख) इन्क्यूबेटर्स में शुरूआतकर्ताओं के लिए सीड सहायता स्कीम

वर्ष 2005 में, टीडीबी ने अभिनव तकनीकी उद्यमों के विचारों को विकसित करने और अंत में बाजार तक पहुंच बनाने के लिए, युवा उद्यमियों को प्रारंभिक चरण/स्टार्ट अप वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सीड सहायता योजना की शुरूआत की। प्रस्तावित सहायता का उपयोग प्रौद्योगिकी विकास और वाणिज्यीकरण के एक माध्यम के रूप में कार्य करने के लिए किया गया। योजना की शुरूआत, डीएसटी के राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास बोर्ड (एनएसटीईडीबी) द्वारा प्रशासित इन्क्यूबेटर/टेक्नोलॉजी बिजनेस इन्क्यूबेटर (एसटीईपी/टीबीआई) के शुरूआतकर्ताओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किया गया था।

31 मार्च, 2017 तक टीडीबी ने 35 करोड़ रू. की अनुदान सहायता के साथ 35 (जिनमें दो बार वित्तीय सहायता प्राप्त 4 टीबीआई/एसटीईपी शामिल है) टीबीआईएस और एसटीईपीएस का समर्थन किया। इन इन्क्यूबेटर्स ने दूरसंचार, आईटी, रोबोटिक्स, कृषि, इन्स्ट्रूमेंटेशन, इंजीनियरिंग, पर्यावरण, फार्मा, खाद्य, सौर, वस्त्र और जैव प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों की परियोजनाओं के लिए इन्क्यूबेटीज को सहायता प्रदान की। स्कीम ने अच्छी प्रगति की है और विभिन्न क्षेत्रों में बहुत से उद्यमियों को लाभान्वित किया है। इन्क्यूबेटीज के लिए जारी की गई वित्तीय सहायता विकास, स्तरोन्नयन और संबंधित कार्य की आवश्यकता रखने वाली प्रौद्योगिकीयों के लिए आरंभिक स्तर पर सहायता में मदद किया। इसने इन्क्यूबेटर्स द्वारा इन्क्यूबेसन निधि का सृजन करने में भी सुविधा प्रदान किया।

मार्च, 2016 में आयोजित बोर्ड की 53वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया कि टीडीबी का इस योजना को बंद कर देना चाहिए क्योंकि डीएसटी का एनएसटीईडीबी एक बड़े पैमाने पर सीड सहायता योजना को आगे बढ़ा रहा है। हालांकि, टीडीबी द्वारा पहले से वित्तपोशित टीबीआईएस/एसटीईपीएस अपने इन्क्यूबेशन कोष के माध्यम से इन्क्यूबेट्स में निवेश जारी रख सकते हैं।

वर्ष 2016–17 के दौरान, टीडीबी द्वारा सहायता प्राप्त टीबीआईएस/एसटीईपीएस की समीक्षा की गई। समीक्षा बैठक 12–13 मई, 2016 को आयोजित की गई। सभी टीबीआईएस और एसटीईपीएस को समीक्षा समिति के सामने प्रस्तुतीकरण के लिए आमंत्रित किया गया। समीक्षा समिति ने यह पाया कि टीबीआईएस के पास शुरूआतकर्ताओं के मूल्यांकन, सलाह और निगरानी की एक मजबूत व्यवस्था स्थापित हो गई है और टीबीआईएस ने, शुरूआतकर्ताओं के लिए एक जीवंत पारिस्थितिक तंत्र स्थापित करके उसकी स्थिरता भी सुनिश्चित किया है।

(ग) विदेशी संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन

प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड ने बीपीआईफ्रांस, फ्रांस, पूर्व में आसियो, फ्रांस, के साथ नवीकृत समझौता ज्ञापन दिनांक 10 मई, 2016 जो कि नई दिल्ली में सेफीप्रा के साथ हस्ताक्षरित किया गया। करार के तहत फ्रांस और भारत की कम्पनीयों के बीच सहयोग के द्वारा विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवोन्मेष के क्षेत्र में सर्वोत्तम अभ्यासो के आदान–प्रदान से संबंधित गतिविधियों और तकनीकी एक्सचेंजों को बढ़ाबा देने के लिए समन्वित उपायों की स्थापना की जायेगी। समझौते के पहले चरण में एयरोनॉटिक्स, ऑटोमोटिव एवं बायोटेक्नोलॉजी के प्रस्तावों में निवेश का लक्ष्य रखा गया है।

(घ) डब्ल्यूडब्ल्यूएफ–भारत के साथ क्लाईमेट सॉल्वर पार्टनर के लिए समझौता ज्ञापन

ग्लोबल क्लीनटेक इनोवेशन इंडेक्स 2012 में भारत को दिये गये 12वीं रैंक के मद्देनजर, टीडीबी ने डब्ल्यूडब्ल्यूएफ इंडिया द्वारा शुरू किये गये क्लाईमेट सॉल्वर प्लेटफॉर्म में शामिल होने का फैसला किया।

क्लाईमेट सॉल्वर, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ के नवोन्मेषी कम कार्बन तकनीक के विकास एवं व्यापक उपयोग को मबजूती देने वाले वैश्विक पहल का एक हिस्सा है। यह प्लेटफॉर्म, उद्योग संघों, निवेशकों, सरकार, इन्क्यूबेशन केंद्रों, मीडिया और कम कार्बन टेक्नोलॉजी प्रवर्तकों के बीच एक इंटरफेस प्रदान करेगा। छोटे और मध्यम उद्यमों द्वारा विकसित अभिनव स्वच्छ प्रौद्योगिकीयों के सावधानीपूर्वक स्क्रीनिंग एवं चयन के बाद, क्लाईमेट सॉल्वर का उद्देश्य उनकी क्षमता का प्रदर्शन करना, उनके पहुंच का विस्तार करना और नवाचार के समग्र मूल के साथ जलवायु परिवर्तन का तत्काल और व्यवहारिक समाधान है। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य नवीन स्वच्छ प्रौद्योगिकीयों के उपयोग को बढ़ावा देना और इस प्रकार उत्सर्जन को कम करने और उर्जा के पहुंच को बढ़ाना है। क्लाईमेट सॉल्वर पहली बार डब्ल्यूडब्ल्यूएफ स्वीडन द्वारा 2008 में शुरू किया गया था और इसके तहत अब तक 28 नवोन्मेषी प्रौद्योगिकीयों को पुरस्कृत किया जा चुका है।

भारत में, प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (टीडीबी), के अलावा कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इन्डस्ट्री (सीआईआई), न्यू वेंचर्स इंडिया, सेंटर फॉर इनोवेशन इन्क्यूवेशन एवं एन्ट्रप्रेन्योरशिप (आईआईएम अहमदाबाद), और स्काईक्वेस्ट टेक्नोलॉजिज कन्सल्टिंग प्राईवेट लिमिटेड भी इस प्रोग्राम में शामिल हैं। टीडीबी और डब्ल्यूडब्ल्यूएफ–भारत ने पारस्परिक रूप से करार की वैधता 21.05.2019 तक बढ़ा दिया है।

(ड) सहयोग

- **इन्वेन्ट प्रोग्राम**
  टीडीबी ने अंतरराष्ट्रीय विकास विभाग (डीएफआईडी), यूके के सहयोग से वर्ष 2015–16 में इनोवेटिव वेंचर्स एंड टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपमेंप (इंवेट) कार्यक्रम की शुरूआत की। कार्यक्रम को निम्न आय वर्ग के लिए सामाजिक और आर्थिक प्रभाव वाले तकनीकी और प्रकिया उन्मुख समावेशी नवाचार समाधान के लिए एक मंच बनाने के लिए तैयार किया गया।

  सहायता में भारत के 8 कम आय वाले राज्यों (एलआईएस) (यूपी, एमपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल) में वित्तपोषण, गहन सलाह, ज्ञान और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों, समर्थन सेवाओं और संबंधित नेटवर्किंग शामिल है परन्तु यह केवल यहां तक सीमित नहीं है।

  उद्देश्य:
  - उपर्युक्त 8 एलआईएस में प्रभावी निवेश के लिए व्यवहार्य सामाजिक उद्यमों की एक कड़ी तैयार करना।
  - 8 कम आय वाले राज्यों में 50 निवेश के लिए तैयार सामाजिक उद्यमों मुनाफे वाले उद्यमों को तैयार करना।
  - 8 कम आय वाले राज्यों में 160 उद्यमियों को सहायता प्रदान करना।

  प्रभाव:
  - 8 कम आय वाले राज्यों में उपयुक्त विविध वित्तपोषण के अवसरों के साथ सामाजिक उद्यमों को विकसित करने का एक पारिस्थितिक तंत्र बनेगा।
  - समाजिक बाधा को तोड़ने और अधिक लोगों को सामाजिक उद्यमिता में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी सहायता में वृद्धि।
  - मजबूत पहचार के साथ स्थापित सामाजिक इन्क्यूबेटर।

वर्ष 2015–16 में टीडीबी एवं मैसर्स विलग्रो इनोवेशन फाउंडेशन (वीआईएफ) के बीच हस्ताक्षरित करार के तहत विलग्रो 8 कम आय वाले राज्यों में निवेश के लिए व्यावहार्य सामाजिक उद्यम (लाभ के लिए) पाइपलाईन बनाने के उद्देश्य से इन्क्यूबेसन सहायता प्रदान करने के लिए एक मुख्य इन्क्यूबेटर के तौर पर कार्य करेगा। विलग्रो वर्तमान मे एलआईएस में गरीबों को फायदा पहुंचाने वाले व्यवसायिक रूप से सफल शुरूआती चरण के अभिनव व्यवसायों के समर्थन के लिये चार इन्क्यूबेटर्स जैसे आईआईएस कोलकाता इनोवेशन पार्क (आईआईएमसीआईपी), केआईआईटी टेक्नोलॉजी बिजनेस इन्क्यूबेटर भूवनेश्वर (केआईआईटी–टीबीआई), सिडबी इनोवेशन एंड इन्क्यूवेशन सेन्टर आईआईटी कानपुर (एसआईआईसी आईआईटीके) और स्टार्ट–अप ओसिस (सीआईआईई, आईआईएम अहमदाबाद और आरईईसीओ की एक शुरूआत) को सहायता प्रदान कर रहा है।

• ग्लोबल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी अलायंस (जीआईटीए)

2011 में सीआईआई और टीडीबी के दरम्यान कमशः 51:49 की सहभागिता से ग्लोबल इनोवेषन एंड टेक्नोलॉजी अलायंस (जीआईटीए) के नाम से कम्पनी अधिनियम–2013 की धारा–8 के तहत एक "गैर लाभ" सार्वजनिक उद्यम (पीपीपी) एक संयुक्त उद्यम की स्थापना की।

गीता, भारत सरकार और भारतीय उद्योग/आरएंडडी संस्थानों का एक अभिनव मंच है जिसे सरकारी और गैर–सरकारी संगठनों द्वारा नियोजित तकनीक के अंतराल के माध्यम से नवप्रवर्तनशील प्रौद्योगिकी समाधानों में दुनिया भर में उपलब्ध तकनीको का मूल्यांकन और तकनीकी–रणनीतिक सहयोगात्मक साझेदारी बनाने के लिए धन का प्रबंधन करने के लिए बनाया गया है। गीता औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करती है और प्रौद्योगिकी विकास/अधिग्रहण/अनुकूलन/परियोजन के लिए धन प्रदान करने और औद्योगिक एवं संस्थागत साक्षेदारों को प्रभावी एवं सहयोगी औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के लिए जोड़ती है।

गीता, द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते के तहत विभिन्न देशों के साथ औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में डीएसटी की सहायता करता है। इन देश–विशिष्ट कार्यक्रमों के तहत, भारत का एक उद्योग और किसी अन्य देश का एक उद्योग एक विपणन योग्य उत्पाद विकसित करने के लिए एक संयुक्त अनुसंधान एवं विकास प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है। इस सुविधा के लिए, संबंधित देशों की सरकारे अपने उद्योग के लिए 50% परियोजना लागत तक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। गीता ने इस तरीके से, डीएसटी के भारत–इजराईल, भारत–कनाडा, भारत–स्पेन, भारत–यूके और भारत–कोरिया आदि कार्यक्रमों को लागू किया है। बीते वर्षो में, गीता विभिन्न सरकारी एजेंसियों जैसे भारी उद्योग विभाग, एमएसएमई, डीआरडीओ आदि के साथ विभिन्न राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

• मिलेनियम अलायंस (एमए)

टीडीबी, संयुक्त राज्य अमेरिका की एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (यूएसएआईडी) और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्श एंड इंडस्ट्री (फिक्की) द्वारा इंडिया और नवप्रवर्तन का लाभ विश्व की सबसे नीचे स्तर की जनसंख्या को पहुंचाने के उद्देश्य से वर्ष 2011 में मिलेनियम अलायंस (एमए) की शुरूआत की गई। यह गठबंधन स्वास्थ्य, बुनियादि शिक्षा, जल एवं स्वच्छता, खाद्य सुरक्षा/कृषि और स्वच्छ ऊर्जा जैसे नवीन क्षेत्रों पर ध्यान देने के साथ वैश्विक विकास के लिए नवीन साझेदारी के रूप में बना है। बाद में, अंतरराष्ट्रीय विकास विभाग (डीएफआईडी), आईसीसीओ कोऑपरेशन, आईसीआईसीआई फाउंडेशन फॉर इन्क्लूसिव ग्रोथ, वर्ल्ड बैंक ग्रुप और फेसबुक भी इसमें शामिल हुए। एमए आने वाले विकास की चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत में विकसित और परिक्षण किए जा रहे अभिनव समाधानों को पहचानने और बढ़ाने के लिए भारतीय रचनात्मकता, विषेशज्ञता का उपयोग करने का एक समावेशी मंच है। एमए एक ऐसा मंच है जो विभिन्न सामाजिक आविष्कारों, परोपकारी संगठनों, सामाजिक उद्यम पूंजीपतियों, ऐंजल निवेषकों, सेवा प्रदाताओं, और कॉरपोरेट फाउंडेशन को प्रोत्साहित और इनोवेटरों को वित्तीय और अन्य सहायता प्रदान कराता है।

25 मिलियन अमेरिकी डॉलर का एक फंड 5 वर्ष की अवधि के लिए स्थापित किया गया था, टीडीबी ने 25 करोड़ रू. (5 करोड़ रू. प्रतिवर्ष) का योगदान किया था। प्रोग्राम के तहत, अविष्कारों को सीड वित्तपोषण, अनुदार, उष्मायन, नेटवर्किंग के अवसर व्यवसाय सहायता, ज्ञान विनिमय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है जो कि इक्विटी, ऋण और अन्य पूंजी तक पहुंच की सुविधा प्रदान करती है।

20 से अधिक भारतीय राज्यों और 7 विकासशील देशों में सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान से इस कार्यक्रम ने अब तक 86 सामाजिक उद्यमों को 60 करोड़ रू. की सहायता प्रदान किया है जिससे 6.8 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हुए। परियोजना पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं द्वारा 27,000 से अधिक लोगों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षण दिया गया है। इसके अतिरिक्त, 451 मिलियन डॉलर का बाह्य धन जुटाने के लिए नवप्रवर्तकों ने एमए के साथ अपने सहयोग का फायदा उठाया एवं व्यापक और टिकाऊ परियोजना कार्यान्वन के लिए 90 से अधिक भागीदारी विकसित की।

(च) प्रौद्योगिकी दिवस और राष्ट्रीय पुरस्कार का वितरण

प्रौद्योगिकी दिवस

प्रत्येक वर्ष 11 मई को पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। यह दिन जीवन में विज्ञान के महत्व को दर्शाता है और छात्रों को कैरियर विकल्प के तौर पर विज्ञान को अपनाने के लिए प्रेरित करता है।

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस का आयोजन, 11 मई, 1998 को पोखरन, राजस्थान में ऑपरेशन शक्ति (पोखरन–द्वितीय) के तहत किए गए पांच परमाणु परीक्षणों की सालगिरह का जश्न मनाने के लिए किया जाता है। पोखरन परमाणु परीक्षण के अलावा भारत ने इसी दिन पहले स्वदेशी विमान हंसा–3 का परीक्षण बैंगलोर में किया और त्रिशूल मिशाइल का सफल परीक्षण फाइरिंग भी किया। इन सभी उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है।

यह दिन, भारतीय उद्योग को राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के साथ मजबूत साझेदारी बनाने और अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने और वैश्विक बाजार में प्रवेश पाने के लिए अकादमिक संस्थानों के साथ साझा नेटवर्क बनाने के लिए प्रेरित करता है।

राष्ट्रीय पुरस्कार

इस दिन को एक उत्सव के तौर पर मनाने के लिए प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (टीडीबी) ने राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरूआत की। यह पुरस्कार विभिन्न व्यक्तियों और उद्योगों को स्वदेशी तकनीक के सफल वाणिज्यीकरण में उनकी उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। पुरस्कार के तहत 10 लाख रू. और एक ट्रॉफी प्रदान की जाती है। अगर उत्पाद का निर्माण एवं वाणिज्यीकरण दो अलग–अलग संस्थाओं द्वारा किया गया है तो दोनो ही पुरस्कार प्राप्त करने के लिए योग्य होंगे। 11 मई, 1999 को प्रौद्योगिकी दिवस के दौरान पहली राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया।
स्वदेशी विकसित तकनीक "पुनःसंयोजक डीएनए आधारित हेपेटाइटिस–बी वैक्सीन" के सफलतापूर्वक वाणिज्यीकरण के लिए पहला राष्ट्रीय पुरस्कार, मैसर्स शांता बायोटेक प्राईवेट लिमिटेड, हैदराबाद एवं उसके आर एंड डी इकाई को मई, 1999 में माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी बाजपयी द्वारा दिया गया था।

वर्ष 2016–17 के दौरान, टीडीबी ने एक सक्रिय पहल की और निम्नलिखित तीन श्रेणियों के तहत पुरस्कारों की घोषणा की जिसको वर्ष 2017–18 से लागू किया जायेगा:

- स्वदेशी तकनीक के सफल विकास एवं वाणिज्यीकरण करने वाले औद्योगिक इकाई को 25.00 लाख रू. और एक ट्रॉफी का एक पुरस्कार, अगर उत्पाद का निर्माण एवं वाणिज्यीकरण अलग–अलग हैं तो दोनो ही पुरस्कार प्राप्त करने के लिए योग्य होंगे।
- प्रौद्योगिकी आधारित स्वदेशी तकनीक के सफल वाणिज्यीकरण करने वाले एमएसएमई के लिए 15.00 लाख रू. और ट्रॉफी का तीन पुरस्कार।
- वाणिज्यीकरण की क्षमता वाली नई तकनीक के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी स्टार्ट–अप पुरस्कार के तहत 15.00 लाख रू. और एक ट्रॉफी के रूप में टीडीबी ने एक नये पुरस्कार की शुरूआत की।

एसएसआई इकाई पुरस्कार

टीडीबी ने अगस्त, 2000 में उन एसएसआई इकाईयों के लिए 2 लाख रू. के नकद पुरस्कार की घोषणा की जिसने स्वदेशी तकनीक पर आधारित उत्पाद का सफलतापूर्वक वाणिज्यीकरण किया है। एसएसआई इकाई का पहला पुरस्कार 11 मई, 2001 को दिया गया। बाद में, वर्ष 2011 में पुरस्कार की संख्या और मात्रा बढ़ाकर क्रमशः 3 लाख रू. और 5 लाख रू. कर दिया गया। 2016 में, इस पुरस्कार का नाम बदलकर 'एमएसएमई पुरस्कार' कर दिया गया और पुरस्कार राशि को बढ़ाकर 15 लाख रू. कर दिया गया।

(छ) विवाद समाधान समिति (डीआरसी)

टीडीबी की स्थापना के बाद से लगभग 60 मामलों को या तो तकनीकी की विफलता या वाणिज्यीकरण विफलता के कारण स्ट्रेस्ड घोषित कर दिया गया है। बैंकों और अन्या वित्तीय संस्थानों के विपरीत, टीडीबी ऋण वसूली ट्रिब्यूनल (डीआरटी) जैसे तंत्र का सहारा नहीं ले सकता है, और इसके बजाय परिसम्पत्ति प्रबंधकों, मध्यस्थों और अन्य कानूनी प्रावधानों का सहारा लिया।

बोर्ड ने अपने कई बैठकों में, खराब कर्ज के मामलों पर चर्चा की और वसूली के लिए उपयुक्त कदम सुझाए। 2002 के टीडीबी के स्थायी आदेशों (एमएसओ) के अनुच्छेद 4.42 में एक समय में निपटारे के लिए प्रावधान किया गया है जिसमें कहा गया है कि:

"टीडीबी को असाधारण मामलों में एक बार निपटारे के लिए नियम तय करने चाहिए और आईडीबीआई जैसे वित्तीय संस्थानों द्वारा अपनाई गई प्रकिया को ध्यान में रखते हुए इस तरह के निपटारे के लिए टीडीबी द्वारा उचित प्रकिया तैयार करना चाहिए। एक बार के निपटारे से लाभान्वित होने वाले किसी भी संस्था को भविष्य में टीडीबी की किसी भी सहायता के लिए अपात्र कर दिया जायेगा।"

इन एनपीए/स्ट्रेस्ड मामलों के कारण, पूर्व–मुकदमेबाजी और मुकदमेबाजी के बढ़ते मामलों की वजह से, टीडीबी ने अध्यक्ष, टीडीबी की मंजूरी से वर्श 2015 में इस तरह के मामलो को निपटाने का लिए "विवाद समाधान समिति (डीआरसी)" के रूप में एक तंत्र की शुरूआत की। डीआरसी का उद्देश्य मुकदमों पर अनावश्यक खर्चे को करना था, खासकर उन मामलो में जहां कंपनी ऋण के पुर्नभुगतान के लिए अपनी देयता पर विवाद नहीं करता अपितु मामले को निपटान या पुनःभुगतान अनुसूची के पुनःनिर्धारण से खत्म करना चाहता है। यह लंबित मामलों को समाप्त करने और पारस्परिक शर्तों पर ऋण और अन्य शुल्कों की अधिकतम वसूली सुनिश्चित करने का एक प्रयास था। डीआरसी, टीडीबी द्वारा पहले से शुरू किए गए कानूनी मामलों में कोई हस्तक्षेप नही करता है।

डीआरसी की सिफारिशों को अध्यक्ष के द्वारा विधिवत रूप से गठित बोर्ड की उप–समिति के सामने मंजूरी के लिए रखा जाता है। इस प्रकिया के माध्यम से बहुत हीं कम अवधि में कई मामलों में महत्वपूर्ण वसूली दर्ज की गई।

(ज) सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का निर्माण

कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और अधिक कनेक्टिविटी बनाने एवं वर्तमान परिदृश्य में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के महत्व को ध्यान में रखते हुए टीडीबी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होने की जरूरत को महशूस किया और अपने अधिकारिक पृष्ठ को निम्नानुसार बनाया:

Linkedin : http://e-techcom.tdb.gov.inhttps://www.linkedin.com/in/technology-development-board

Facebook: https://www.facebook.com/tdbgoi/

Twitter: https://twitter.com/tdbgoi

टीडीबी ने एक मजबूत परियोजना प्रबंधन प्रणाली (पीएमएस) और एनआईसी सर्वर पर अपनी नई आधिकारिक वेबसाइट की शुरूआत www.tdb.gov.in के डोमेन नाम के साथ की। यह वेबसाईट सरकार के सरकारी वेबसाईट बनाने के दिशानिर्देशों (जीआईजीडब्ल्यू) के अनुसार विकसित की जा रही है ताकि टीडीबी और इसकी योजनाओं के बारे में जानकारी सार्वजनिक करने में आसानी हो सके।

आभार

टीडीबी, अपने बोर्ड के सदस्यों का उनके समय, प्रयास, मार्गदर्शन एवं योगदान के लिए आभारी है।

-ह-

स्थान : नई दिल्ली

(प्रो. आशुतोष शर्मा)
अध्यक्ष
प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड

वर्ष 2016–17 के परियोजनाएं एवं उत्पाद

मैसर्स एम्पेरे विहाईकल्स प्राईवेट लिमिटेड, कोयम्बटूर

15 जुलाई, 2016 को करार पर हस्ताक्षर

परियोजना का नाम

इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के महत्वपूर्ण पूर्जो जैसे मोटर, चार्जर, नियंत्रक और डीसी–डीसी कन्वर्टर्स के स्वदेशी विकास एवं वाणिज्यीकरण

क्षेत्र

सड़क परिवहन

परियोजना का उद्देश्य

टीडीबी ने मैसर्स एम्पेरे विहाईकल्स प्राईवेट लिमिटेड, कोयम्बटूर के साथ "इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के महत्वपूर्ण पूर्जो जैसे मोटर, चार्जर, नियंत्रक और डीसी–डीसी कन्वर्टर्स के स्वदेशी विकास एवं वाणिज्यीकरण" की परियोजना के लिए करार पर हस्ताक्षर किया।

यह परियोजना बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहनों के चार प्रमुख पार्ट्स जिसमें कि मोटर, चार्जर, नियंत्रक और डीसी–डीसी कन्वर्टर्स शामिल है के स्वदेशी विकास एवं वाणिज्यीकरण को लक्षित करता है। वर्तमान में उपरोक्त सभी पार्टस विदेशों से आयात किये जाते है। उपकरणों का यह आयात मुद्रा के उतार–चढ़ाव के कारण ऊंची लागत, अप्रत्याशित गुणवत्ता, उच्च मात्रा में स्रोत घटकों की जरूरत के कारण आपूर्ति श्रृंखला में अक्षमताएं पैदा करती हैं। आयातित उत्पाद भारतीय उपयोग के लिए अनुकूलित नहीं होते है जिसके परिणामस्वरूप कम्पोनेंट की विफलता से वाहनों की लागत बढ़ जाती है। एम्पेरे विहाईकल्स निर्माण की प्रतिस्पर्धा को हासिल करने के उद्देश्य से मोटर, चार्जर, नियंत्रक और डीसी–डीसी कन्वर्टर्स के पूर्ण स्वदेशी निर्माण का प्रस्ताव करती है। यह परियोजना इन प्रमुख घटकों के निर्माण की पूर्ण स्वदेशी प्रकिया स्थापित करने के लिए है। इन प्रमुख घटकों की तकनीक को घरेलु अनुसंधान एवं विकास द्वारा विकसित किया गया है। पिछले चार वर्षों में एम्पेरे विहाईकल्स ने स्थानीय तरीके और प्रक्रियाओं का उपयोग कर इन चार प्रमुख घटकों के प्रोटोटाईप बनाने में दक्षता हासिल कर ली है।

एम्पेरे विहाईकल्स प्राईवेट लिमिटेड, कोयम्बटूर पिछले 7 वर्षों से 2 एवं 3 पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास, निर्माण और बेचने के व्यवसाय में है। वे इन प्रमुख घटकों का आयात चीन से करते रहे हैं। उन्होनें आयात पर निर्भरता का कम करने और इससे जुड़े व्यवसायिक जोखिमों को ध्यान में रखते हुए, इन घटकों के भारतीय जरूरतों के अनुसार निर्माण की जरूरत को महसूस किया। एम्पेरे विहाईकल्स का यह प्रयास भारत सरकार के "मेक इन इंडिया" नीति के अनुसार है एवं सराहनीय है।

कुल परियोजना लागत

6.91 करोड़ रु.

टीडीबी की सहायता

2.43 करोड़ रु.

मैसर्स पैनेसिया मेडिकल टेक्नोलॉजीज प्राईवेट लिमिटेड, बैंगलोर

6 अक्टूबर, 2016 को करार पर हस्ताक्षर

परियोजना का नाम

मेडिकल लाईनेक के स्वदेशी निर्माण की सुविधा एवं वाणिज्यीकरण

क्षेत्र

स्वास्थ्य

परियोजना का उद्देश्य

टीडीबी ने मैसर्स पैनेसिया मेडिकल टेक्नोलॉजीज प्राईवेट लिमिटेड, बैंगलोर के साथ "मेडिकल लाईनेक के स्वदेशी निर्माण की सुविधा एवं वाणिज्यीकरण" की परियोजना के लिए करार पर हस्ताक्षर किया।

परियोजना के तहत, पैनेसिया इंटेंसिटी–मॉड्यूलेटेड रेडियेशन थेरेपि (आईएमआरटी), इमेज–गाईडेड रेडियेशन थेरेपि (आईजीआरटी) और वॉल्यूमेंट्रिक मॉड्यूलेटेड आर्क थेरेपि (वीएमएटी) और स्टीरियोटेक्टिक बॉडी रेडियेशन थेरेपी (एसबीआरटी) जैसे उन्नत रेडियोथेरेपि तकनीक के साथ संपूर्ण स्वदेशी 6एमवी मेडिकल लिनियर एक्सिलिरेटर (लाईनेक) बनाने की योजना बनायी है। पैनेसिया ने इस तकनीक का अधिग्रहण समीर एवं डेयटी से किया है। कंपनी भारतीय आबादी को सस्ती कीमत एवं बडी संख्या में ऐसे उन्नत उपचार प्रदान करने के उद्देश्य से विनिर्माण लाईन की स्थापना कर रही है। यह मशीन, भारतीय अस्पतालों के अलावा विकासशील देशों के अस्पतालों में उच्च लागत वाले मशीनों के लिए एक अच्छा विकल्प होगा। इसके अलावा, इस उत्पाद की एशियाई, अफ्रीकी और यूरोपीय देशों के लिए एक अच्छी निर्यात क्षमता है। आईएईए के अनुसार, वर्ष 2020 तक इस मशीन की कुल मांग 4000 मशीनों के ज्यादा होगी। पैनेसिया हर तरह की सुविधा से लैस 6एमवी लाईनेक कम कीमत पर लॉन्च करके विश्व के तीन बड़े मेडिकल लाईनेक निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा करना चाहता है।

पैनेसिया स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में काम करने वाला एक पेशेवर कम्पनी है जो कि रेडियोथैरेपि और रेडियोलॉजी में प्रौद्योगिकी के विकास से कैंसर के निदान और चिकित्सा के लिए नवाचार और नैदानिक समाधानों को बढ़ावा दे रहा है।

कुल परियोजना लागत

19.30 करोड़ रू.

टीडीबी की सहायता

7.40 करोड़ रू.

मैसर्स सहजानन्द लेजर टेक्नोलॉजी प्राईवेट लिमिटेड, गांधीनगर

13 अक्टूबर, 2016 को करार पर हस्ताक्षर

परियोजना का नाम

फाईबर लेजर सिस्टम के वाणिज्यीकरण

क्षेत्र

अभियांत्रिकी

परियोजना का उद्देश्य

टीडीबी ने मैसर्स सहजानन्द लेजर टेक्नोलॉजी प्राईवेट लिमिटेड, गांधीनगर के साथ "फाईबर लेजर सिस्टम के वाणिज्यीकरण" की परियोजना के लिए करार पर हस्ताक्षर किया।

यह परियोजना एक घरेलु उत्पादित मध्यम – उच्च शक्ति 1 μm निरंतर वेव (सीडब्ल्यू) फाईबर लेजर स्त्रोत है। लक्षित बिजली का स्तर उच्च शक्ति फाईबर संयोजनों और इन फाईबर लेजरों के वाणिज्यीकरण को के माध्यम से एकल मोड 500W से बहु-- kW (3kW तक) मल्टीमोड है। कम्पनी ने 500W सिंगल–मोड फाईबर लेजर का विकास कर लिया है और इस परियोजना के तहत वह फाईबर लेजर के घरेलु उत्पादन के लिए क्षमता और आधारित संरचना का निर्माण करना चाहते हैं। यह उत्पादों और विदेशी और घरेलू आपूर्तिकर्ताओं के दाम के बीच का अंतर को कम करेगा जिससे यह केवल लागत ही नही कम करेगा अपितु सरकार, रक्षा अनुसंधान और वाणिज्यीक संस्थान सहित घरेलू उपभोक्ताओं का अच्छी और समयपरक सेवा उपलब्ध करायेगी।

कम्पनी द्वारा आयातित फाईबर लेजरों के साथ, लेजर काटने और वेल्डिंग सिस्टम पहले से ही देश और विदेश में बेचा जा रहा है। इस परियोजना के तहत उत्पादित फाईबर लेजर इन मशीनों में आयातित फाईबर लेजर का स्थान लेगा। इसके अलावा, स्टैंड–अलोन फाईबर लेजरों को देश और विदेशों में भी विपणन किया जा सकता है।

कम्पनी को परिष्कृत लेजर सिस्टम का डिजाइन, विकास, निर्माण और विपणन में दक्षता हासिल है। यह कई विशेष प्रयोजन मशीनरी (एसपीएम) भी बनाती है जो विशिष्ट औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए प्रत्येक ग्राहक की विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार स्वनिर्धारित और कमबद्ध है।

कुल परियोजना लागत

24.53 करोड़ रू.

टीडीबी की सहायता

6.40 करोड़ रू.

मैसर्स सोनोडाईन टेक्नोलॉजीज प्राईवेट लिमिटेड, कोलकाता

7 दिसम्बर, 2016 को करार पर हस्ताक्षर

परियोजना का नाम

आवासीय और व्यावसायिक ऑडियो सेगमेंट के लिए विशेष डिजिटल ऑडियो हार्डवेयर समाधान

क्षेत्र

अभियांत्रिकी

परियोजना का उद्देश्य

टीडीबी ने मैसर्स सोनोडाईन टेक्नोलॉजीज प्राईवेट लिमिटेड, कोलकाता के साथ " आवासीय और व्यावसायिक ऑडियो सेगमेंट के लिए विशेष डिजिटल ऑडियो हार्डवेयर समाधान" की परियोजना के लिए करार पर हस्ताक्षर किया।

परियोजना के हिस्से के रूप में सोनोडाईन इन विशेष ऑडियो उत्पादों को डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र में एकीकृत करेगा। इसमें लैन, यूएसबी, ब्लूटूथ, वाई–फाई और अन्य ऐसे डिजिटल इंटरफेस के साथ एकीकृत करने के लिए नए मॉडल का डिजाईन और निर्माण भी शामिल होगा। इसके अतिरिक्त, इसमें उत्पादन क्षमता में वृद्धि और संयंत्र आधुनिकीकरण होगा। सेज, फाल्टा, बंगाल स्थित सोनोडाईन के मौजूदा जगह से इन उत्पादों का निर्यात किया जायेगा और हावड़ा, बंगाल स्थित एक नयी निर्मित जगह से इसकी बिक्री भारत में भी किया जायेगा।

इसका उद्देश्य, आवासीय और व्यवसायिक क्षेत्र में विश्व स्तर के डिजिटल उत्पादों को शुरू करना और बाद में निर्यात के लिए उत्पादों का बनाने और आयात प्रतिस्थापन प्रदान करने के लिए अंतर्निहित अनुसंधान और विकास तथा विनिर्माण प्रकियाओं का उपयोग और उन्नयन करना है।

कम्पनी जो कि 70 और 80 के दशक से आवासीय ऑडियो (एम्प्लीफायर, स्पीकर) और टीवी के क्षेत्र में अग्रणी रही है अब भारतीय बाजारों और निर्यात के लिए विशेष एम्प्लीफायर, स्पीकर और संबंधित बिजली इलेक्ट्रॉनिक्स बैक–अप का निर्माण कर रही है।

कुल परियोजना लागत

16.24 करोड़ रू.

टीडीबी की सहायता

5.00 करोड़ रू.

मैसर्स बायोलॉजिकल ई लिमिटेड, हैदराबाद

8 दिसम्बर, 2016 को करार पर हस्ताक्षर

परियोजना का नाम

न्यूमोकोकल कन्ज्यूगेट वेक्सीन के निर्माण फैसिलीटी की स्थापना

क्षेत्र

स्वास्थ्य

परियोजना का उद्देश्य

टीडीबी ने मैसर्स बायोलॉजिकल ई लिमिटेड, हैदराबाद के साथ "न्यूमोकोकल कन्ज्यूगेट वेक्सीन के निर्माण फैसिलीटी की स्थापना" की परियोजना के लिए करार पर हस्ताक्षर किया।

प्रस्तावित उत्पाद संयुग्मक वैक्सीन है जिसमें स्ट्रैपटोकोकस निमोनिया के विभिन्न महत्वपूर्ण एटिऑलॉजिकल उपभेदों से पॉलिसेकेराईड रासायनिक रूप से एक कैरियर प्रॉटीन (सीआरएम 197) से जुड़ा हुआ है जो टीकाकरण वाले विषयों में सुरक्षात्मक प्रतिरक्षा प्रकिया को ट्रिगर करने के लिए जाना जाता है। वैक्सीन के प्रत्येक खुराक में कई अलग–अलग पॉलिसेकेराईड होते है जो कि एक कैरियर प्रॉटीन (सीआरएम 197) से तरल के रूप में संयुग्मित होते हैं। यह टीका मुख्य रूप से शिशुओं (5 वर्ष के ऊपर) और वयस्कों (60 वर्ष के ऊपर) के लिए प्रयोग किया जाता है।

वैक्सीन संरचना अद्वितीय है जिसमें स्ट्रैपटोकोकस निमोनिया के 14 सीरोटाइप हैं जो कि बच्चों में श्वसन रोग होने का एक उच्चतम प्रवृति कारण है। कम्पनी का शुरूआत में 25 मिलियन खुराक के उत्पादन का लक्ष्य है जिसको कि बाद में 100 मिलियन प्रतिवर्ष तक बढाया जायेगा। अधिक संख्या में सीरोटाइप शामिल यह श्रेष्ट उत्पाद भारत में सुविधा के साथ जनता को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराया जा सकता है।

1953 में स्थापित कम्पनी, वैक्सीन (पेंटावेलेंट), फार्मा उत्पाद (खांसी, सर्दी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल उत्पादों, न्यूट्रास्यूटिकल इत्यादि) किटिकल केयर (पॉलिवेलेंट स्नेक वेनोम, कॉजूलेट्स प्रतिरोधक) के निर्माण के क्षेत्र में एक सार्वजनिक क्षेत्र की लिमिटेड कम्पनी है।

कुल परियोजना लागत

320.39 करोड़ रू.

टीडीबी की सहायता

100.00 करोड़ रू.

मैसर्स सेन्विता बायोटेक्नोलॉजीज प्राईवेट लिमिटेड, हैदराबाद

9 दिसम्बर, 2016 को करार पर हस्ताक्षर

परियोजना का नाम

पशु चिकित्सा मे उपयोग के लिए फूट–और–माउथ रोग (एफएमडी) वैक्सीन का विकास एवं वाणिज्यीकरण

क्षेत्र

स्वास्थ्य

परियोजना का उद्देश्य

टीडीबी ने मैसर्स सेन्विता बायोटेक्नोलॉजीज प्राईवेट लिमिटेड, हैदराबाद के साथ पशु चिकित्सा मे उपयोग के लिए फूट–और–माउथ रोग (एफएमडी) वैक्सीन का विकास एवं वाणिज्यीकरण'' की परियोजना के लिए करार पर हस्ताक्षर किया।

प्रस्तावित परियोजना में पशु चिकित्सा के उपयोग के लिए एफएमडी वैक्सीन के निर्माण के लिए एकीकृत अत्याधुनिक सुविधा की स्थापना की गई है जो कि डब्ल्यूएचओ सीजीएमपी को पालन करते हुए सुरक्षा मानदंडों का पालन करते है। इसके अलावा, बीएसएल3 के अनुरूप एक आधुनिक और व्यापक पशु परीक्षण इकाई का निर्माण का भी प्रस्ताव है जिसमें किमेटोरेटर, भूमिगत जैव–अपशिष्ट संग्रह और निपटान प्रणाली जैसे अद्वितीय विशेषताएं होंगी।

स्वदेशी तौर पर विकसित तकनीक को लागू करने के अलावा परियोजना, पूरे देश में किसानों को लाईव–स्टॉक की आयु बढ़ाकर और कमाई को बढ़ाकर सामाजिक उद्देश्य को पूरा करेगी जो कि जन स्वास्थय के लिए प्रासंगिक होगा और ''एफएमडी के नियंत्रण'' के राष्ट्रीय कार्यक्रम के सहयोग में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी।

यह मैसर्स विविमेड की एक सहबद्ध कम्पनी है, जो कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, (आईसीएआर), भारत सरकार द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों को लाईसेंस पशु चिकित्सा और मानव टीकों के उत्पादन में शामिल है।

कुल परियोजना लागत

101.18 करोड़ रू.

टीडीबी की सहायता

16.00 करोड़ रू.

मैसर्स टाटा पॉवर कम्पनी लिमिटेड – स्ट्रेटजिक इंजीनियरिंग डिवीजन (टाटा पॉवर एसईडी), बैंगलोर

17 दिसम्बर, 2016 को करार पर हस्ताक्षर

परियोजना का नाम

वेमगल इंडस्ट्रीयल क्षेत्र, कोलर डिस्ट्रक्ट, कर्नाटक के 50 एकड़ जमीन पर रक्षा निर्माण सुविधा

क्षेत्र

रक्षा

परियोजना का उद्देश्य

टीडीबी ने मैसर्स टाटा पॉवर कम्पनी लिमिटेड – स्ट्रेटजिक इंजीनियरिंग डिवीजन (टाटा पॉवर एसईडी), बैंगलोर के साथ " वेमगल इंडस्ट्रीयल क्षेत्र, कोलर डिस्ट्रक्ट, कर्नाटक के 50 एकड़ जमीन पर रक्षा निर्माण सुविधा" की परियोजना के लिए करार पर हस्ताक्षर किया।

परियोजना के तहत, टाटा पावर एसईडी, वेमागल में अधिग्रहित जमीन पर रणनीतिक रक्षा क्षेत्र में दूरसंचार उत्पाद, रणनीतिक इलेक्ट्रॉनिक्स, हवाई जहाज, ऑप्टो– इलेक्ट्रॉनिक्स, ईएसडीएम उत्पादों के लिए बिजली का आपूर्ति के विकास के लिए रक्षा विनिर्माण सुविधा की स्थापना के लिए प्रस्ताव दिया है। इस विनिर्माण सुविधा का उपयोग विभिन्न चालू और आगामी कार्यक्रमों जैसे आईईडब्ल्यूएस–एमटी, टीसीएस, बीएमएस, रॉकेट और मिशाइल लॉचर जैसे पिनाका, आकाश, एमआरएसएएम इत्यादि जैसे उच्च मात्रा और बड़ी प्रणालियों के निर्माण और एकीकरण के लिए नही किया जा सकता। वेमगल में अधिगृहित इस नई विनिर्माण सुविधा का इस्तेमाल परियोजना को लागू करने के लिए किया जायेगा।

टाटा पॉवर एसईडी के पास भारतीय रक्षा क्षेत्र के लिए सिस्टम इंजीनियरिंग की क्षमता में योग्यता हासिल है। उन्होंने वायु रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, कमांड एवं कंट्रोल सिस्टम के क्षेत्र में समाधान प्रदान किए हैं। कम्पनी को रक्षा मंत्रालय के मेक प्रोग्राम के दो बड़े कार्यक्रमों अर्थात् रक्षा मंत्रालय (एमओडी) टेक्निकल कम्यूनिकेशन सिस्टम (टीसीएस) और बैटल फील्ड मैनेजमेंट सिस्टम (बीएमएस) के लिए सक्षम विकास एजेंसी में से एक के रूप में पहचाना गया है।

कुल परियोजना लागत

385.00 करोड़ रू.

टीडीबी की सहायता

109.00 करोड़ रू.

मैसर्स सॉफ्टटेक इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड, पूणे

6 फरवरी, 2017 को करार पर हस्ताक्षर

परियोजना का नाम

"रूलबड्डी उत्पाद (पहले "आर्चीटीएक्स") का विकास और वाणिज्यीकरण

क्षेत्र

सूचना प्रौद्योगिकी

परियोजना का उद्देश्य

टीडीबी ने मैसर्स सॉफ्टटेक इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड, पूणे के साथ "रूलबड्डी उत्पाद (पहले "आर्चीटीएक्स") का विकास और वाणिज्यीकरण" की परियोजना के लिए करार पर हस्ताक्षर किया।

परियोजना का उद्देश्य अपने प्रमुख उत्पाद ऑटो सीडीआर की पहुंच के माध्यम से परियोजना व्यावहार्यता और निर्माण परमिट के लिए सेवाएं प्रदान करने के लिए एक ई–कॉमर्स पोर्टल के रूप में रूलबड्डी का विकास और वाणिज्यीकरण करना है। रूलबड्डी पोर्टल का उद्देश्य प्रोफेशनल डेप्थ और बाईलॉज के निर्माण और योजना अनुमोदन जानकारी के निर्माण के लिए डिजाईन प्रदान करना है। यह पूरी तरह से स्वदेशी विकसित उत्पाद है जिससे एक जगह में मौजूदा परियोजनाओं क्षेत्र में वर्तमान विघटन डिजाईन चरण के दौरान व्यवहार्यता और निर्माण परमिट का पता लगाया जा सकता है। वर्तमान में भारत में इस तरह की सुविधा देने वाला कोई भी ऑनलाईन पॉर्टल उपलब्ध नही है।

रूलबड्डी द्वारा दी जाने वाली वाणिज्यीक सेवाएं आर्किटेक्ट्स, बिल्डर्स, रियल स्टेट डेवलेपरर्स, इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनीयों और निवेशकों को अपनी परियोजना की संभावित और स्वीकृत आवश्यकताओं को पहले हीं अच्छी तरह से समझने में मदद करेगी। रूलबड्डी का उपयोग इन्फ्रास्ट्रक्ख उद्योग में निवेशकों को विभिन्न विभागीय एनओसी कि प्रकिया का समझने में मदद करेगा और इस तरह का एक प्लेटफॉर्म तैयार करेगा जिससे कि कार्यकुशलता बढ़े और स्वीकृति की प्रकिया में समय कम लगे। यह देश की बुनियादी ढ़ांचा विकास की दिशा में विकास को उत्प्रेरित करने में मदद करने के लिए भारत सरकार के योजनाओं के अनुरूप है।

कंपनी आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग एवं कंस्ट्रक्शन क्षेत्र (एईसी क्षेत्र) एंड–टू–एंड समाधान विकसित करने के कारोबार में है। इसमें, पेशेवर उपयोगर्ताओं जैसे संरचनात्मक इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स और सलाहकार, निजी क्षेत्र के कॉर्पोरेट प्रयोक्ता के साथ प्रोपर्टी विकासकर्ता, निवेशकों, रियल स्टेट कम्पनियों, और केंन्द्र/राज्य सरकारों जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपभोक्ता और नगर निगम जैसे स्थानीय स्वसाशित निकाय जैसे सभी तीन उपयोगकर्ता सेंगमेंट शामिल है।

कुल परियोजना लागत

6.15 करोड़ रू.

टीडीबी की सहायता

2.45 करोड़ रू.

मैसर्स टर्मिनस सर्किट्स प्राईवेट लिमिटेड, बैंगलोर

16 मार्च, 2017 को करार पर हस्ताक्षर

परियोजना का नाम

हाई स्पीड सीरियल लिंक उत्पाद के वाणिज्यीकरण'

क्षेत्र

सूचना प्रौद्योगिकी

परियोजना का उद्देश्य

टीडीबी ने मैसर्स टर्मिनस सर्किट्स प्राईवेट लिमिटेड, बैंगलोर के साथ "हाई स्पीड सीरियल लिंक उत्पाद के वाणिज्यीकरण" की परियोजना के लिए करार पर हस्ताक्षर किया।

इस परियोजना के माध्यम से कंपनी का उद्देश्य अपनी आयात का विकल्प और निर्यात उन्मुख विभिन्न सिलिकॉन सिद्ध आईपी की उपलब्धता को बढ़ाकर भारत और दुनिया भर में अपने ग्राहक आधार को बेहतर बनाना है। टर्मिनस सर्किट्स हाई स्पीड सीरियल लिंक उत्पादों के डिजाईन और विकास में क्षेत्र में 7 वर्श से काम कर रहा है। इसके महत्वपूर्ण उत्पाद हैं यूएसबी 3.0/3.1 पीसीआईई जेन 4/3/2/1 और मल्टी–स्टैंडर्ड सरडेस।

घरेलू विकसित अभिनव आर्किटेक्चर उच्च प्रदर्शन और कम विलंबता के साथ बेहतर प्रदर्शन वाले उत्पाद लेकर आते हैं। पीसीआई जेन4, यूएसबी 3.1 और एचएसएस लिंक जैसी उप–प्रणालियां जो क्लाउड कम्प्यूटिंग, मस्तिश्क सिम्यूलेशन, एंटरप्राईज अनुप्रयोगों और लैपटॉप, मोबाईल एप्लीकेशन इत्यादि जैसे उपभोक्ता उत्पादों के अनुप्रयोग के लिए उच्च निष्पादन कम्प्यूटर जैसे उच्च कम्प्यूटिंग सिस्टम में गिने जाते हैं।

कम्पनी की शुरूआत जनवरी, 2010 में की गई थी। इसका मुख्य लक्ष्य उच्च गति इंटरफेस सर्किट और एनालॉग आईपी डिजाइन एवं विकास में है। यह गतिविधि उच्च गेस्टेसन अवधि वाले अत्यधिक कुशल क्षेत्र में है। आईईईई, यूएसबी, पीसीआई–एसआईजी आदि जैसे मानक समूह द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा करते हुए कम्पनी ने सर्किट डिजायन और आर्किटेक्चर के विकास के लिए उच्च गति सीरियल लिंक पूर्ण समाधान विकसित किया है।

कुल परियोजना लागत

20.79 करोड़ रू.

टीडीबी की सहायता

9.70 करोड़ रू.

मैसर्स रेनालिक्स हेल्थ सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड, बैंगलोर

16 मार्च, 2017 को करार पर हस्ताक्षर

परियोजना का नाम

ग्रामीण सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए एक सस्ती हेमोडायलिसिस मशीन का विकास

क्षेत्र

स्वास्थ्य

परियोजना का उद्देश्य

टीडीबी ने मैसर्स रेनालिक्स हेल्थ सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड, बैंगलोर के साथ "ग्रामीण सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए एक सस्ती हेमोडायलिसिस मशीन का विकास" की परियोजना के लिए करार पर हस्ताक्षर किया।

कंपनी का लक्ष्य, हेमोडायलिसिस मशीन, रेनालिफ के माध्यम से गुर्दे की पुरानी बीमारी (सीकेडी) की शीघ्र पहचान के लिए संपूर्ण प्रणाली का निर्माण करना है। रेनालिफ इंटरनेट से कनेक्टेड एक मशीन है और टाईपिकल डायलिसिस केंद्रों में दो तरीके से विन्यस्त किया जा सकता है। पहला एक स्टैंडअलोन डायलिसिस मशीन के रूप में और दूसरा एक केंद्रीयकृत डायलासेट वितरण प्रणाली (सीडीडीएस) में कन्सोल के रूप में। रेनालिफ डायलिसिस मशीन उपयोगकर्ताओं के अनुकूल और सहज ज्ञान युक्त यूजर इंटरफेस है जो कि एंड्रोईड टैबलेट पर उपलब्ध है।

डायलिसिस रोगी का रियल–टाईम डेटा एकत्र किया जा सकता है और इसे दूर स्थित कम्प्यूटर को भेजा जा सकता है जिसे दूरस्थ स्थित नेफ्रोलॉजिस्ट के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। यह कनेक्टिविटी, नेफ्रोलॉजिस्ट को दूरस्थ स्थान से डायलिसिस तकनीशियन को उचित कार्रवाई करने के लिए मार्गदर्शन के लिए सक्षम बनाता है। इसके अलावा, रोगी के इतिहास के आधार पर, आगामी डायलिसिस के लिए अनुस्मारक और दवाएं, सावधानी एवं आहार सिफारिशें रोगी या देखभालकर्ता को भेजा जाता है। रेनालिक्स स्वास्थ्य प्रणालियों के सभी उत्पादों को घरेलु तौर पर विकसित कर रहा है।

कंपनी की स्थापना अक्टूबर, 2012 में सीकेडी के लिए सस्ती विश्वस्तरीय स्वास्थय देखभाल समाधान प्रदान करने के लिए किया गया। यह सीकेडी के इलाज और रोकथाम के लिए कार्यक्रम चला रहा है।

कुल परियोजना लागत

11.99 करोड़ रू.

टीडीबी की सहायता

4.00 करोड़ रू.

मैसर्स इनरगोस टेक्नोलॉजिज प्राईवेट लिमिटेड, मुम्बई

23 मार्च, 2017 को करार पर हस्ताक्षर

परियोजना का नाम

इनर्जी आदतों में बदलाव

क्षेत्र

सूचना प्रौद्योगिकी

परियोजना का उद्देश्य

टीडीबी ने मैसर्स इनरगोस टेक्नोलॉजीज प्राईवेट लिमिटेड, मुम्बई के साथ "ऊर्जा आदतों में बदलाव" की परियोजना के लिए करार पर हस्ताक्षर किया।

परियोजना के तहत, कम्पनी का उद्देश्य उन्नत एनालिटिक्स के विकास के माध्यम से एससससएस मॉडल पर व्यवसायिक एवं वाणिज्यिक कार्यालयों के लिए बिजली के मॉनिटरिंग एवं नियंत्रण के लिए 24x7 उपलब्ध वैश्विक नेटवर्क ऑपरेटिंग सेंटर की स्थापना के लिए, आईओटी डिवाईस का वाणिज्यीकरण करना है। इनरगोस ने, भारत और दुनिया के कई शहरों में स्थित उपकरणों को स्वचालित और मॉनिटर करने के लिए सेल्फ–लर्निंग वाले आईओटी डिवाइस को तैयार और विकसित किया है। इसे ऐक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और कैफे कॉफी डे के विभिन्न कार्यालयों में कार्यान्वित किया गया है। अन्य व्यवसायिम वर्टिकल्स के लिए आगे के विश्लेषण और निर्णय लेने वाले एल्गोरिद्म विकासाधीन हैं।

ऊर्जा और इसके संरक्षण का कुशल उपयोग इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है कि उपभोग स्तर पर बचाई गई ऊर्जा की एक इकाई, क्षमता निर्माण की आवश्यकता को कम कर देता है। इसके अलावा, क्षमता सृजन पर काफी कम निवेश पर ऊर्जा के कुशल उपयोग के माध्यम से इस तरह की बचत प्राप्त की जा सकती है। इसलिए ऊर्जा दक्षता, बिजली का आवश्यकता को पूरा करने के प्रयासों का पूरक होगी।

इनरगोस की स्थापना, रीयल–टाईम प्रभाव को मापने और स्थिरता के अभ्यास के मामले में दक्षता प्राप्त करने के लिए चुनौती के साथ ऊर्जा बचत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आईसीटी प्रौद्योगिकीयों के नवीनतम रूझानों का उपयोग करने के उद्देश्य से किया गया है। यह एक सॉफ्टवेयर और सेवा प्रदाता कंपनी है जो बड़े उपभोक्ताओं या परंपरागत या नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादों के लिए बेव आधारित एम2एम प्रौद्योगिकी समाधान प्रदान करती है।

कुल परियोजना लागत

6.55 करोड़ रू.

टीडीबी की सहायता

2.25 करोड़ रू.

मैसर्स आयटोम इलेक्ट्रिक इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, कोयम्बटूर

28 मार्च, 2017 को करार पर हस्ताक्षर

परियोजना का नाम

पोर्टेबल एक्स–रे मशीन का विकास एवं वाणिज्यीकरण

क्षेत्र

स्वास्थ्य

परियोजना का उद्देश्य

टीडीबी ने मैसर्स आयटोम इलेक्ट्रिक इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, कोयम्बटूर के साथ "पोर्टेबल एक्स–रे मशीन का विकास एवं वाणिज्यीकरण" की परियोजना के लिए करार पर हस्ताक्षर किया।

परियोजना, निम्नलिखित चार प्रकार के एक्स–रे इमेजिंग उपकरणों के विनिर्माण और वाणिज्यीकरण के लिए है:

- पोर्टेबल हस्त चालित एक्स–रे – यह एक बैटरी संचालित कॉम्पैक्ट एक्स–रे मशीन है जिसे हाथ में रखकर संचालित किया जा सकता है। यह उपकरण विशेष रूप से डेन्टल इन्ट्रा–ओरल रेडियोग्राफी के लिए बनाया गया है।
- डेन्टल एक्स–रे के लिए डिजिटल इमेजिंग – उत्पाद 1 के पूरक के लिए कम्पनी डिजिटल एक्स–रे सेंसर पर काम कर रही है इसके उपयोग से एक्स–रे इमेजिंग फिल्म रहित हो सकती है। इस सॉफ्टवेयर को घरेलु तौर पर विकसित किया जाएगा।
- पोर्टेबल सामान्य एक्स–रे – एक बहुउद्देश्य एक्स–रे उपकरण – डिवाईस अत्यधिक मोबाईल / पोर्टेबल, संचालित करने में आसान, विश्वसनीय और बैटरी बैकअप के साथ बिना बिजली के उपयोग के लिए बनाया गया है।
- फ्लोरोस्कोपी के लिए एक्स–रे जेनरेटर – देश के कई सी–आर्म सिस्टम बनाने वालों के उपयोग के लिए यह एक ओईएम उप–घटक उत्पाद होगा।

एक्स–रे जेनरेटर और हाई वोल्ट इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के साथ आयटोम एक पॉवर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी कम्पनी है। कम्पनी ने जीई मेडिकल सिस्टम्स और बीपीएल मेडिकल सिस्टम्स के लिए उत्पादों का विकास किया है। इसके अलावा, उन्होंने विद्युत, मैकेनिकल, उच्च वोल्टेज, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के उन्नत तरीको के साथ एक्स–रे जेनरेशन के लिए स्वदेशी तकनीक का अनुसंधान एवं विकास किया है।

कुल परियोजना लागत

5.36 करोड़ रू.

टीडीबी की सहायता

2.04 करोड़ रू.

मैसर्स डायबेटॉमिक्स मेडिकल प्राईवेट लिमिटेड, हैदराबाद

28 मार्च, 2017 को करार पर हस्ताक्षर

परियोजना का नाम

मधुमेह की निगरानी के लिए अभिनव, प्वाइंट–ऑफ–केयर नैदानिक परीक्षण का विनिर्माण और वाणिज्यीकरण

क्षेत्र

स्वास्थ्य

परियोजना का उद्देश्य

टीडीबी ने मैसर्स डायबेटॉमिक्स मेडिकल प्राईवेट लिमिटेड, हैदराबाद के साथ "मधुमेह की निगरानी के लिए अभिनव, प्वाइंट–ऑफ–केयर नैदानिक परीक्षण का विनिर्माण और वाणिज्यीकरण" की परियोजना के लिए करार पर हस्ताक्षर किया।

यह परियोजना मधुमेह की मॉनिटरिंग के प्वाइंट–ऑफ–केयर परीक्षणों के निर्माण और वाणिज्यीकरण से संबंधित है। कम्पनी ने इसने पार्श्व प्रवाह प्रारूप परीक्षण को अपनाया है जो कि देखभाल के समय बहुत कम उपकरण के साथ प्रदर्शन को सक्षम बनाता है।

- लुमेला, प्री–एक्लम्पसीया और गर्भकालीन मधुमेह के लिए प्वाइंट–ऑफ–केयर टेस्ट "ग्लाइकोसिलेटेड फिब्रोनेक्टिन", एक नवीन जैवमार्कर है जो गर्भावस्था में प्री–एक्लम्पसिया और जीडीएम के विकास के खतरे में गर्भवती महिला को ट्रिज करने में मदद करता है, के स्तर को मापने के लिए फिन्गर प्रिक से खून के एक बूंद का उपयोग करता है।
- इन्सूडेक्स, टाइप–1 मधुमेह वाले रोगियों में ऑटो एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए, एक तेज, प्वाइंट–ऑफ–केयर टेस्ट है। यह परीक्षण पार्श्व प्रवाह प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है और टाइप–1 मधुमेह के साथ जीएडी 65, इसुलिन एंटीबॉडी और आइलेट सेल एंटीबॉडी जैसी सामान्य एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए फिंगर प्रिक नमूना पर आधारित है।

कम्पनी गर्भकालीन मधुमेह (जीडीएम), प्री–एक्लम्पसिया (पीई), टाईप 2 मधुमेह और ऑटोइम्यून मधुमेह की निगरानी के लिए अभिनव, उपन्यास, प्वाइंट–ऑफ–केयर परीक्षण विकसित करने के क्षेत्र में तत्पर है। कपनी के पास कई राष्ट्रीय और वैश्विक पेटेंट्स हैं।

कुल परियोजना लागत

25.77 करोड़ रू.

टीडीबी की सहायता

5.00 करोड़ रू.

मैसर्स सिस्टमेंटिक्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, बैंगलोर

31 मार्च, 2017 को करार पर हस्ताक्षर

परियोजना का नाम

औद्योगिक रोबोट्स का डिजाईन, विकास और निर्माण

क्षेत्र

अभियांत्रिकी

परियोजना का उद्देश्य

टीडीबी ने मैसर्स सिस्टमेंटिक्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, बैंगलोर के साथ "औद्योगिक रोबोट्स का डिजाईन, विकास और निर्माण" की परियोजना के लिए करार पर हस्ताक्षर किया।

कंपनी स्थायी आधार पर मानवशक्ति द्वारा नहीं किये जा सकने वाले कठिन कार्यों के लिए भारतीय उद्योग द्वारा स्वचालन को व्यापक तौर पर अपनाने के लिए प्रेरित करने के लिए औद्योगिक रोबोट्स का निर्माण करने के लिए घरेलु औद्योगिकीयों के आधार पर सुविधाएं स्थापित कर रही है, परन्तु यह उन कार्यों के लिए नहीं है जो मानव निर्णय से लाभान्वित होते हैं और जिसके लिए मानव श्रम कारगर एवं समग्र है। प्रस्तावित उत्पाद कि एक 4–अक्ष रोबोट, व्यक्त 6–अक्ष (ए6ए) रोबोट और उन्नत 6 अक्ष (एच6ए) सहित 6 अक्ष और 1.5 मीटर पहुंच एवं 10 से 20 किलो ग्राम के बीच लोड वाला एक प्लैनर समानान्तर मैनिपूलेटर (पीपीएम) है।

सिस्टमैंटिक्स, औद्योगिक रोबोटिक्स के क्षेत्र में काम करता है जो कि एक ऐसा बाजार है जो भारत और दुनिया भर में काफी बढ रहा है। यह कम लागत और अधिक सामर्थ्य वाले रोबोटिक्स के अधिक उपयोग के बाजार की आवश्यकता को परिभाषित करता है। इसका प्रस्तावित मूल्य लक्षित बाजार के साथ प्रतिध्वनित होता है, और इसका विजन और मिशन भारत सरकार के "मेक इन इंडिया" पहल के अनुरूप है। इलेट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर में नवीन धारणा का उपयोग करते हुए यह घरेलु तौर पर विकसित एक अभिनव, पेटेंटेड तकनीक है जिससे कि लागत कम हो जाती है और अधिक कुशलता प्राप्त होती है।

कुल परियोजना लागत

8.20 करोड़ रू.

टीडीबी की सहायता

4.10 करोड़ रू.

प्रोन्नति संबंधी गतिविधियां

प्रौद्योगिकी दिवस और राष्ट्रीय पुरस्कार 2016 (11 मई, 2016)

प्रौद्योगिकी दिवस 2016 का आयोजन 11 मई, 2016 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में "स्टार्टअप इंडिया के लिए प्रौद्योगिकी समर्थक" के थीम के साथ किया गया। भारत के माननीय राष्ट्रपति, श्री प्रणव मुखर्जी इस अवसर पर मुख्य अतिथि थे। डॉ. हर्षवर्धन, माननीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री ने मुख्य अतिथि के रूप में समारोह की अध्यक्षता की। प्रो. आशुतोष शर्मा, सचिव, डीएसटी एवं अध्यक्ष, टीडीबी ने स्वागत भाषण दिया और कार्यक्रम के विषय को उद्धृत किया।

समारोह को सम्बोधित करते हुए माननीय राष्ट्रपति ने कहा कि यह हमारे राष्ट्र के समर्पित वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों के अथक प्रयास और मिशिनरी उत्साह है जिसने भारत का एक प्रौद्योगिकी शक्ति के रूप में उभरने का मार्ग प्रशस्त किया। अब हम, हमारे लाखों देशवासियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य के साथ एक तकनीकी क्रांति के लिए काम कर रहें हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस वैज्ञानिक जांच और तकनीकी उत्कृष्टता के लिए हमारी खोज का प्रतीक और एक एकीकृत वैज्ञानिक, सामाजिक और औद्योगिक दृष्टिकोण में उस खोज का अनुवाद का प्रतीक है। यह न केवल हमारे तकनीकी नवाचारों को दर्शाता है बल्कि बड़े पैमाने पर लोगों के लिए श्रमसाध्य शोध के सफल वाणिज्यीकरण को दर्शाता है।

माननीय राष्ट्रपति ने देश की उपलब्धि पर प्रकाश डाला और कहा कि भारत धीरे–धीरे वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में अग्रणी देशों में उच्च स्थान पाने की ओर बढ़ रहा है। यह अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में विश्व के शीर्ष पांच देशों में शामिल है। इसरो के पोलर सेटेलाईट लॉच विहाईकल ने हाल ही में अपने 35वें उड़ान में 1425 किलो के उपग्रह को उसकी कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया। उन्होनें भारत के तमाम अंतरिक्ष वैज्ञानिक समुदाय को इस अनोखे उपलब्धि के लिए बधाई दिया। उन्हेंने जोर देकर कहा कि हमें यहां रूकना नहीं चाहिए क्योंकि यह उपलब्धि हमें मौजूदा प्रौद्योगिकीयों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगी। विज्ञान की शिक्षा और अनुसंधान में होने वाले बदलाव के साथ, केवल प्रतिस्पर्धी वैश्विक बाजार में तकनीकी बढ़त हासिल करने वाले देश ही सफल होंगे। राष्ट्रपति ने कहा कि नवीनता, स्थिरता का प्रतिरोधक है। हमारे देश के युवा विचारों और उद्यमों से भरे हुए हैं। वे आम आदमी की रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए तकनीक का इस्तेमाल कर रहें हैं।

स्वदेशी प्रौद्योगिकी के सफलतापूर्वक वाणिज्यीकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार–2016

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली (आईआईटीडी) के स्मिता रिसर्च लैब और अन्तराष्ट्रीय रिसर्च सेंटर फॉर पॉवर मेटालर्जी एवं न्यू मैटेरियल (एआरसीआई), हैदराबाद के सहयोग से विकसित एन9 शुद्ध सिल्वर के स्वदेशी विकास एवं वाणिज्यीकरण के राष्ट्रीय पुरस्कार मैसर्स रेसिल केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड, बेंगलोर को दिया गया।

मैसर्स रेसिल केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड, बैंगलोर को राष्ट्रीय पुरस्कार

एन9 शुद्ध सिल्वर अंतराष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणित चांदी आधारित एक रोगाणुरोधक है जिसका इस्तेमाल कपड़ा और अन्य सबस्ट्रेट्स पर प्रभावी ढ़ंग से किया जा सकता है। यह निकास, पैडिंग, स्प्रेइंग, मोल्डिंग और कोटिंग प्रकियाओं के माध्यम से लागू करने में आसान होने के अलावा त्वचा और पर्यावरण के लिए सुरक्षित है। एक रोगाणुरोधी के रूप में यह न केवल ईलाज की सहत को स्वच्छ रखता है बल्कि वस्त्रों को गंध मुक्त और ताजा रखने का एक सुरक्षित और प्राकृतिक तरीका भी प्रदान करता है।

भारत के राष्ट्रपति द्वारा ट्रॉफी एवं 10.00 लाख रू. का नकद पुरस्कार प्रदान किया गया।

स्वदेशी प्रौद्योगिकी आधारित उत्पाद के वाणिज्यीकरण के लिए एसएसआई यूनिट–2016 पुरस्कार

माननीय राष्ट्रपति ने स्वदेशी प्रौद्योगिकी आधारित उत्पाद के सफल वाणिज्यीकरण के लिए एसएसआई यूनिट–2016 पुरस्कार भी प्रदान किया। पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रत्येक को एक ट्रॉफी और 5 लाख रू. का नकद पुरस्कार प्रदान किया गया। पुरस्कार दिये गये:

1. मैसर्स आयटोम इलेक्ट्रिक इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, कोयम्बटूर को समग्र इन्सूलेशन के साथ डिजीटल उच्च आवृत्ति एक्स–रे जेनरेटर के आधार पर विकसित लागत प्रभावी हस्त आयोजित बैटरी संचालित पोर्टेबल एक्स–रे मशीन के विकास एवं वाणिज्यीकरण के लिए दिया गया। यह उत्पाद लिथियम–आयन बैटरी पर काम करता है और इसका उपयोग उन स्थानों पर भी किया जा सकता है जहां बिजली उपलब्ध नहीं है।

मैसर्स आयटोम इलेक्ट्रि इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, कोयम्बटूर को एसएसआई यूनिट पुरस्कार

मैसर्स तेजस नेटवर्क्स लिमिटेड, बैंगलोर को एसएसआई यूनिट पुरस्कार

2. मैसर्स तेजस नेटवर्क्स लिमिटेड, बैंगलोर को टीजे1400 – पैकेट ट्रांसमिशन नोड – मोबाईल बेस–स्टेशन कनेक्टिविटी (2जी, 3जी, और 4जी के लिए), उद्यम डेटा सेवा और बैंडविड्थ सेवाओं के लिए आधुनिक फाइबर–आप्टिक ट्रांसमिशन नेटवर्क्स में तैनात किए गये, अभिनव, उच्च क्षमता, फाइबर ऑप्टिक नेटवर्किंग उत्पादों का एक परिवार के वाणिज्यीकरण के लिए दिया गया।

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस – प्रमोचित उत्पाद

डा. हर्षवर्धन, माननीय मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा मैसर्स एक्वाएग्री प्रोसेसिंग प्राईवेट लिमिटेड द्वारा समुद्री शैवाल से विकसित उत्पाद को 11 मई, 2016 को प्रौद्योगिकी दिवस–2016 के दौरान विज्ञान भवन में वाणिज्यीक प्रमोचन किया गया। हालांकि, यह परियोजना वर्श 2015–16 के दौरान पूर्ण हो चुकी थी।

डॉ. हर्शवर्धन, माननीय मंत्री (एस एंड टी एवं ईएस) द्वारा मैसर्स एक्वाएग्री प्रोसेसिंग प्राईवेट लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा विकसित "सीवीड एक्वासैप" नामक उत्पाद का प्रमोचन

मैसर्स एक्वाएग्री प्रोसेसिंग प्राईवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में सव्यं–सहायता समूहों के माध्यम से समुद्री शैवाल की खेती करने वाली भारत की पहली कम्पनी है। उत्पादकों का निर्माण एक पूर्व नियोजित कीमतों पर किया जाता है एवं इसे खाद्य एवं सौदर्य प्रसाधनों में उपयोग के लिए तैयार किया जाता है। यह सीएसएनसीआरआई, सीएसआईआर के स्वदेशी विकसित पेटेंट प्रकिया लाईसेंस पर आधारित है। एक्वाएग्री, मिट्टी, पत्ते एवं ड्रिप सिंचाई के लिए तरल और पाउडर के रूप में जैव–उत्तेजक, कई स्वरूपों में उपलब्ध कराता है। इन जैव–उत्तेजकों की जांच कृशि अनुसंधान प्रणाली द्वारा कई स्थानों में फसलों पर बड़े पैमाने पर की जा चुकी है और उपज और फसल, दोनों की गुणवत्ता में सुधार लाने की प्रभावकारिता को माना गया है।

पुरस्कार समारोह के बाद, डा. हर्षवर्धन, माननीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री ने विज्ञान भवन में टीडीबी से सहायता प्राप्त कम्पनीयों के प्रदर्शन का उद्घाटन किया जिसमें कि टीडीबी की सहायता से विकसित स्वदेशी नवोन्मेशी उत्पादों को दिखाया गया।

टीडीबी का 20वां स्थापना दिवस (1 एवं 2 सितम्बर, 2016)

1 सितम्बर, 2016 को टीडीबी ने अपना 20वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर, 1 एवं 2 सितम्बर, 2016 "तकनीकी और अभिनव के माध्यम से वाणिज्यीकरण" के विषय पर दो दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। विषय के रूप में निम्नलिखित छः क्षेत्रों को चुना गया था: i) रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण की जटिलताएं, ii) साईबर सुरक्षा (आईटी), आसन्न जोखित एवं संभावित समाधान, iii) रोबोटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स को दैनिक जीवन में एकीकृत करना, iv) नैनोविज्ञान एवं नैनोतकनीक: अतीत से वर्तमान, v) स्वच्छ एवं ग्रीन ऊर्जा : क्या हम मुद्दों पर गंभीर हैं, vi) स्वास्थ्य क्षेत्र में औद्योगिक हलचल। संगोष्ठी का समापन सत्र प्रौद्योगिकी नीति संरेखण पर था। सभी सत्र के लिए वक्ताओं को आध्यात्मिक और औद्योगिक क्षेत्र से आमंत्रित किया गया था। व्याख्यान के अलावा, इंडस्ट्रीज, डीआरडीओ, आर एंड डी संस्थान, नीति आयोग, फिक्की और सीआईआई के प्रतिनिधियों के बीच पैनल डिस्कशन भी हुआ।

1 सितम्बर, 2016 को संगोष्ठी का उद्घाटन प्रो. आशुतोष शर्मा, अध्यक्ष, टीडीबी द्वारा किया गया तदुपरान्त टीडीबी के प्रथम सचिव श्री एस. बी. कृष्णन द्वारा "टीडीबी की 2 दशकों की यात्रा" "इतिहास और दर्शन" और डॉ. वाराप्रसाद रेड्डी, पूर्व सीएमडी, शांता बायोटेक्निक्स द्वारा व्याख्यान भी दिया गया। श्री वाय. एस. चौधरी, माननीय राज्य मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एंव पृथ्वी विज्ञान द्वारा मुख्य भाषण दिया गया।

टीडीबी का 20वां स्थापना दिवस (यात्रा के दो दशक)

अन्य वक्ताओं – a) प्रोफ. रमेश चन्द, सदस्य नीति आयोग, b) प्रो. आशुतोष शर्मा, अध्यक्ष, टीडीबी, c) श्री अजय श्रीवास्तव, एमडी, मैसर्स डायमेंशन्स, d) श्री बी. के. जैन, विश्व हाईड्रोजेल, और e) इती गुप्ता, फिक्की के साथ "प्रौद्योगिकी नीति संरेखण" शीर्षक वाले अंतिम सत्र की अध्यक्षता डॉ. बिन्दु डे, सचिव, टीडीबी ने की थी। इस सत्र का उद्देश्य भारतीय प्रौद्योगिकी परिदृश्य में आगे बढ़ने के लिए हमारे दृष्टिकोण के आवश्यक मूल्यों को समझना और कार्यान्वित करना था।

उद्योगों के साथ पारस्परिक बैठकें

टीडीबी ने उद्योगों, संभावित उद्यमियों और प्रौद्योगिकी प्रदानकर्ताओं के साथ उद्योग संघों और आर एंड डी संगठनों इत्यादि के साथ बहुत सी बैठकें आयोजित की। टीडीबी ने विभिन्न प्रदर्शनियों में भी भाग लिया।

इन बहुविध प्लेटफॉर्मों के माध्यम से टीडीबी ने उद्योगों, आर एंड डी संगठनों, अकादमी संस्थानों, वैज्ञानिक और औद्योगिक शोध संगठनों इत्यादि में विशेषकर देश में विकसित प्रौद्योगिकी के लिए उनके वाणिज्यीकरण प्रयासों के लिए आसान शर्तों पर टीडीबी से वित्तीय सहायता की उपलब्धता के बारे में जागरुकता फैलाती है।

टीडीबी ने देश भर में फैले चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, ट्रेड संघों एवं संस्थानों के घनिष्ठ समन्वय में कार्यशालाएं आयोजित की और भागीदारी की। टीडीबी के अधिकारियों ने वर्ष 2016–17 के दौरान प्रदर्शनियों में भाग लिया और उद्योगों एवं संस्थानों के साथ कई पारस्परिक बैठकें आयोजित की।

टीडीबी ने इंडिया अफ्रीका दिवस पर्व 2016 में भागीदारी की (22 अप्रैल, 2016)

टीडीबी ने पीएसओआई क्लब इवेंट लॉन्स, विनय मार्ग, चाणक्यपुरी डिप्लॉमेटिक इन्कलेव, नई दिल्ली में एएसएएचओएम आयोजित, इंडिया अफ्रिका डेय गाला 2016 में 22 अप्रैल, 2016 में भागीदारी की।

यह कार्यक्रम, अफ्रिका के साथ ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और व्यवसायिक संबंधों को मजबूत करने और बढ़ाने के लिए एक सामाजिक मंच था। यह ब्रांडिंग, विपणन और प्रदर्शन के माध्यम से एक मजबूत व्यापार अवसर प्रदान करता है। कई गणमान्य व्यक्ति (मंत्री, सांसद, पूर्व राजदूत, थिंक टैंक, एनजीओ), विदेश मंत्रालय एवं अन्य मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय/सलाहकारों के साथ अफ्रिका के 37 उच्चायुक्त एवं राजदूत, अफ्रीका के 17 माननीय कन्सूलेट्स, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (जाने माने पीएसयूएस के सीएमडी), इंडियन इंडस्ट्री चैम्बर्स, प्राइवेट सेक्टर कम्पनीज, यूनिवर्सिटीज, शैक्षिक संस्थानों, अस्पतालों आदि ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया।

यह टीडीबी और उसकी निवेशित कम्पनियों के लिए अपने प्रौद्योगिकीयों के प्रदर्शन करने का एक अच्छा अवसर था, जो व्यवसाय विस्तार के अवसर प्रदान करता है।

स्वास्थ्य देखभाल / कृषि के लिए एक नए उर्ध्वाधर के रूप में एक क्लस्टर स्थापित करने (अफ्रीका गठबंधन) के लिए केन्या की यात्रा

तीसरे भारत–अफ्रिका मंच शिखर सम्मेलन (अक्टूबर, 2015) की सफलता और राजनयिकों की बातचीत ने आपसी सशक्तिकरण और पुनरूत्थान के लिए इस गठबंधन के विस्तार की आवश्यकता को मजबूत बनाया। ऐसा एक क्षेत्र – स्वास्थ्य देखभाल / कृषि / कृषि उपकरणों के निर्माण की गतिविधियों के लिए विनिर्माण क्लस्टर / इकाईयां है जिसमें रूचि दिखाई गयी है।

इस पृष्ठभूमि के साथ, टीडीबी ने फिक्की के सहयोग से 8–11 जूलाई, 2016 के दरम्यान माननीय प्रधानमंत्री के पहले केन्या दौरे के दौरान एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया।

इस प्रयास में टीडीबी को कई औद्योगिक इकाईयों का साथ मिला जिसको अफ्रिकी सरकार और उद्योग से एक प्रभावशाली प्रतिक्रिया प्राप्त हुई। भारतीय उद्यमियों ने भारत सरकार के अधिकारियों, फिक्की, केन्या, अन्य प्रतिभागी देशों और निजी क्षेत्र के महासंघों के माध्यम से अफ्रिका में अपनी प्रौद्योगिकी और नवीनताओं को नियुक्त करने और उनका वाणिज्यीकरण करने के लिए बातचीत की।

आन्ध्र प्रदेश सरकार के आर्थिक विकास बोर्ड (ईडीबी) के साथ समझौता ज्ञापन

भारत सरकार ने वर्ष 2014 में भारत को एक वैश्विक डिजाइन एवं विनिर्माण केंन्द्र के रूप में बदलने के लक्ष्य के साथ "मेक इन इंडिया" की शुरूआत की। यह पहल, घरेलू एवं बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को अपने उत्पादों का निर्माण भारत में करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसका उद्देश्य गैर जरूरी प्रकियाओं और नीतियों में सुधार के द्वारा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देकर वैश्विक स्तर पर भारत को एक आर्थिक शक्ति के रूप में विकसित करना है। इस पहल के अनुरूप, टीडीबी, घरेलू–विकसित, व्यवसायिक रूप से व्यवहार्य प्रौद्योगिकीयों / उत्पादों और स्पष्ट परिणाम वाले परियोजनाओं के लिए सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

इस पृष्ठभूमि के साथ, टीडीबी ने वर्ष के शुरूआत में "मेंक इन इंडिया" के तहत चिह्नित सामरिक महत्व क्षेत्रों में "प्रस्ताव के लिए कॉल" जारी किया जिसमें विशेशतः इमेजिंग अपकरण (जैसे सीटी स्कैनर, एमआरआई मशीन आदि) सहित मेडिकल डिवाईस शामिल है।

इस विज्ञापन को कम्पनियों से एक अच्छी प्रतिकिया मिली। इन प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए, टीडीबी ने 2700 एकड़ में फैले मेडिकल डिवाईस के स्वदेशी उत्पादन को प्राथमिकता देने वाले "आंध्र मेड टेक जोन" को सहायता उपलब्ध कराने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार से हाथ मिलाया। मेड टेक जोन में 25,000 करोड़ के निवेश सहित लगभग 20,000–25,000 नौकरियां उपलब्ध कराने वाली कम से कम 200–300 इकाईयों को समाहित करने का प्रस्ताव है।

टीडीबी ने आंध्र प्रदेश मेड टेक जोन में अपना उद्यम स्थापित करने वाले कम–से–कम 20 इकाईयों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने में अपनी रूचि दिखाई।

आंध्र प्रदेश सरकार के आर्थिक विकास बोर्ड (ईडीबी) और टीडीबी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया।

सोलन में "5वीं विज्ञान प्रर्दशनी 2016" में टीडीबी की भागीदारी (18–20 जूलाई, 2016)

सोलन, हिमाचल प्रदेश में 18–20 जूलाई, 2016 के दौरान संसा फाउंडेशन के द्वारा 5वां विज्ञान एक्सपो–2016 का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में सरकारी कार्यक्रमों और नीतियों के बारे में जानने के लिए एक मंच प्रदान करना और अन्य हिस्सेदारों के साथ बातचीत करके अपने अनुभवों, ज्ञान और प्रयासों को साझा करने का अवसर प्रदान करना था। एक्सपो का उद्देश्य मुख्यत: हिमाचल प्रदेश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी और भौतिक स्तर पर विज्ञान के स्वभाव को विकसित करना था। टीडीबी ने प्रदर्शनी में भाग लिया और अपनी पिछले 20 वर्शों की सफलता की कहानियों को प्रदर्शित करने के साथ–साथ छात्रों और आम जनता को अपनी योजनाओं के बारे में अवगत कराया। टीडीबी के अलावे, सीएसआईआर, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, कॉफी बोर्ड, राश्ट्रीय बागवानी बोर्ड, नारियल विकास बोर्ड, केन एवं बांस प्रौद्योगिकी केंन्द्र, बांबू विकास एजेंसी, मिजोरम, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, निर्यात निरीक्षण परिषद, भारत जैसे अन्य विभागों में भी एक्सपों में भाग लिया।

प्रदर्शनी का उद्घाटन शिमला विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति, प्रो. ए. डी. एन. वाजपेयी ने किया। शहर और अन्य राज्यों के स्कूली बच्चे और कॉलेज के छात्रों में प्रदर्शनी की दौरा किया और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में जानकारी हासिल की। विभिन्न विद्यालयों के छात्रों द्वारा "हाइड्रोलिक एलिवेटर", "इलेक्ट्रिक फैन", "ट्रैफिक लाइट्स के बिना सड़क", "वर्षा अलार्म" आदि जैसे अभिनव मॉडलों की प्रदर्शनी सबसे आकर्षक थी। कई आगंतुकों ने मॉडलों की सराहना की और इसे काम करता हुआ देखने की उत्सुकता जाहिर की। बड़ी संख्या में आगंतुकों ने टीडीबी की गतिविधियों के बारे में पूछताछ की।

प्रगति मैदान, नई दिल्ली मे "गवरमेंट एचिवमेंट एंव स्कीम्स एक्सपों–2016" (22–24 जुलाई, 2016)

टीडीबी ने हॉल सं. 7, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में 22–24 जूलाई, 2016 के दौरान एनएनएस इवेंट्स एंड एक्जीबिशन प्राईवेट लिमिटेड द्वारा आयोजित "गवरमेंट एचिवमेंट एंव स्कीम्स एक्सपों–2016" में भाग लिया। प्रदर्शनी का उद्देश्य केंद्रीय और राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, संस्थानों, बोर्डों, निकायों, आदि की उपलब्धियों, कल्याण एवं विकास योजनाओं और उत्पादों / सेवाओं आदि का प्रदर्शन करने के लिए एक मंच उपलब्ध कराना था।

प्रदर्शनी का उद्घाटन, माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री श्री हरिभाई पार्थिभाई चौधरी द्वारा किया गया। माननीय मंत्री ने विभिन्न स्टॉलों का दौरा किया और प्रदर्शकों के साथ चर्चा की। इस अवसर पर बोलते हुए, इस तरह के कार्यक्रमों से सरकार के विभिन्न जन कल्याण योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ने की बात का उल्लेख किया। केंद्रीय और राज्य सरकार के कई गणमान्य व्यक्तियों और अधिकारियों ने प्रदर्शनी में भाग लिया।

टीडीबी के स्टॉल में इसके द्वारा पिछले 20 साल की उपलब्धियों को दर्शाया गया। आगंतुकों की एक बड़ी संख्या ने टीडीबी की गतिविधियों के बारे में पूछताछ की और उन्हें टीडीबी को परियोजना वित्तपोषण निर्देशिका प्रदान की गई। टीडीबी की योजनाओं और उपलब्धियों के बारे में जागरूकता बनाने के लिए टीडीबी ब्रोशर भी दर्शकों के बीच वितरित किया गया।

एक्सपो को दर्शकों से एक उत्साहपूर्ण प्रतिक्रिया प्राप्त हुई। शहर और अन्य राज्यों के स्कूली बच्चे और कॉलेज के छात्रों में प्रदर्शनी की दौरा किया और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में जानकारी हासिल की। करीब 100 से अधिक प्रदर्शकों ने एक्सपों में हिस्सा लिया।

वाइब्रेन्ट गुजरात ग्लोबल समिट 2017 के दौरान आयोजित नोबेल प्राईज सीरिज इंडिया 2017 में टीडीबी की भागीदारी

जैवप्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) ने 9 एवं 10 जनवरी, 2017 को गांधीनगर में आयोजित वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन के 8वें चरण के दौरान पहली नोबेल पुरस्कार श्रृंखला भारत 2017 का आयोजन किया। कार्यक्रम का उद्घाटन, भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। इस आयोजन ने भौतिक, रसायन और जैविक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता 9 प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिको की मेजबानी की। कार्यक्रम का उद्देश्य भारत में छात्रों के बीच विज्ञान में नवीनता, रचनात्मक सोच और लगाव को बढ़ावा देना था।

कृषि तकनीक वाणिज्यीकरण प्लेटफॉर्म

टीडीबी ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स (आईआईसीए) और तकनीकी सूचना पूर्वानूमान एवं मूल्यांकन परिषद (टाईफैक) के साथ संयुक्त कार्यशालाओं, सेमिनार और सम्मेलनों का आयोजन करके वाणिज्यीकरण वाले नवाचार के लिए एक पायलट क्षमता निर्माण के पहल कि लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया।

इस समझौता ज्ञापन के माध्यम से, ये संस्थान खेती–भूमि उत्पादकता में सुधार के लिए "कृषि तकनीकी आधारित नवाचारों के स्काउटिंग और सोर्सिंग" के क्षेत्र में एक दूसरे का सहयोग करेंगे। कार्यक्रम, वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करने के प्रधानमंत्री के पहल के अनुरूप है।

इस पृष्ठभूमि के साथ, दो एग्री–टेक वाणिज्यीकरण प्लेटफॉर्म कार्यशालाओं का आयोजन दिल्ली एवं कोयम्बटूर में किया गया।

एनएएससी परिसर, पूसा में कृषितकनीक वाणिज्यीकरण कार्यशाला (18–20 जनवरी, 2017)

टीएनएयू, कोयम्बटूर में कृषि–तकनीक वाणिज्यीकरण कार्यशाला (24–25 जनवरी, 2017)

कार्यशालाओं में टीडीबी की वित्तपोषण निर्देशिका के एक संक्षिप्त अवलोकन के साथ परियोजना प्रस्ताव लेखन के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल शामिल था। प्रतिभागियों ने अपनी परियोजनाएं प्रस्तुत की जिन्हें टीडीबी से वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करने के लिए उनकी योग्यता के लिए मूल्यांकित किया गया। कुल 32 प्रस्तुतिकरण किए गए (6 नई दिल्ली में और 26 कोयम्बटूर में) जिनमें से 13 परियोजनाएं टीडीबी से वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करने के लिए उपयुक्त पाये गए।

"विजन जम्मू एवं कश्मीर प्रदर्शनी–2017" में टीडीबी की भागीदारी (23–25 फरवरी, 2017)

टीडीबी ने संसा फाउंडेशन, नई दिल्ली द्वारा जम्मू में दिनांक 23–25 फरवरी, 2017 के दौरान आयोजित "विजन जम्मू एंड कश्मीर–2017" में भाग लिया। प्रदर्शनी का उद्देश्य राज्य के औद्योगिक विकास के लिए एक राज्य में एक उद्योग अनुकूल वातावरण स्थापित करने में सरकार के प्रयासों में मदद करने का था। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन माननीय सांसद (राज्य सभा) एवं जेएंडके सरकार के माननीय मंत्री श्री श्याम लाल चौधरी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। आगंतुकों की एक बड़ी संख्या ने टीडीबी की गतिविधियों के बारे में पूछताछ की।

प्रौद्योगिकी विकास कोष योजना के कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर
(6 मार्च, 2017)

डीआरडीओ ने निजी उद्योगों के माध्यम से अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए और उच्च जोखिम वाले विकास कार्यों को बढ़ावा देने के लिए एक प्रौद्योगिकी विकास निधि (टीडीएफ) की स्थापना की है। टीडीएफ की स्थापना "मेक इन इंडिया" पहल के तहत रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत, उत्पादन प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए, आर एंड डी की लागत के बोझ को कम करके उद्योगों को उच्च तकनीकी क्षेत्रों में विकास गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। सितंबर, 2016 में डीआरडीओ द्वारा जारी टीडीएफ, निजी उद्योगों में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए बाध्य है।

डॉ. बिन्दु डे, सह–अध्यक्ष, गीता और श्री एम. एच. रहमान, सीसी आर एंड डी टी एम, डीआरडीओ, एमओडी, भारत सरकार ने प्रौद्योगिकी विकास कोष योजना के कार्यान्वयन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया।

टीडीएफ कार्यक्रम में निम्नलिखित प्रौद्योगिकी विकास को शामिल किया गया है:

- वर्तमान उत्पाद / प्रक्रिया / आवेदन आदि में महत्वपूर्ण सुधार / उन्नयन / विकास
- ट्राई–सीरिज आवश्यकताओं के अनुसार उत्पादों की प्राप्ति के लिए टीआरएल–3 से प्रौद्योगिकी रेडीनेस स्तर (टीआरएल) तक उन्नयन
- रक्षा उपयोगिता के लिए जरूरी भविष्य की तकनीक / नवीन उत्पादों का विकास
- भारतीय उद्योग के पास नही उपलब्ध तकनीक के घटक का आयात प्रतिस्थापन

वेबसाईट: www.tdb.gov.in

अनुसंधान एवं विकास उपकर

अनुसंधान एवं विकास उपकर अधिनियम 1986 यथा संशोधित 1995 को प्रौद्योगिकी के आयात के लिए सभी भुगतान पर लेवी और उपकर के समाहरण करने के लिए बनाया गया है। उपकर की दर 5 प्रतिशत है। औद्योगिक इकाईयां जो कि ऐसे आयातों के लिए भुगतान करने अथवा भुगतान किए जाने से पूर्व प्रौद्योगिकी आयात करती हैं, पर उपकर देय होता है। यह उपकर भारत के संचित निधि में जमा होता है। इसको देश में विकसित प्रौद्योगिकी के वाणिज्यीकरण और विदेशी प्रौद्योगिकी को वृहत रुप से घरेलू उपयोग के लिए अपनाए जाने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एकत्र किया जाता है।

भारत सरकार, उपकर समाहरण विनियोजन के माध्यम से प्रौद्योगिकी विकास और उसके प्रयोग के लिए फंड का भुगतान करती है जिसे देश में विकसित प्रौद्योगिकी के विकास एवं वाणिज्यीकरण और आयातित प्रौद्योगिकी को अपनाए जाने के लिए उपयोग किया जाता है। यह निधि प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड द्वारा प्रशासित की जाती है।

उपकर, समाहरण एवं भुगतान (1997 – 2017)

निम्नलिखित सारणी 1996–97 (जिस वर्ष प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, भारत सरकार द्वारा गठित किया गया) से वर्षवार उपकर समाहरण, टीडीबी को आवंटन तथा भुगतान को दर्शाती है:

(करोड़ रु. में)

वर्ष	उपकर समाहरण (सी.जी.ए. के आंकड़े)	टीडीबी को आवंटन		टीडीबी को किया गया वास्तविक भुगतान
		अनुमानित बजट	संशोधित बजट	
1996–97	80.13	30.00	30.00	29.97
1997–98	81.42	70.00	70.00	49.93
1998–99	61.10	50.00	50.00	28.00
1999–00	88.93	70.00	70.00	50.00
2000–01	98.91	70.00	70.00	62.79
2001–02	95.30	63.00	63.00	57.00
2002–03	99.47	58.00	58.00	56.00
2003–04	119.51	55.00	55.00	53.65
2004–05	156.99	54.00	54.00	48.10
2005–06	176.61	43.50	43.50	42.66
2006–07	186.56	33.50	33.50	4.32
2007–08	254.09	63.00	20.80	19.00
2008–09	310.33	20.80	20.80	–
2009–10	418.22	50.00	10.00	–
2010–11	592.22	50.00	5.00	5.00
2011–12	702.54	50.00	25.00	–
2012–13	685.62	50.00	25.00	22.50
2013–14	737.54	50.00	15.00	13.50
2014–15	906.78	211.06	7.50	6.75
2015–16	914.81	100.00	38.79	30.00
2016–17	1187.24	100.00	10.30	30.30
कुल	**7974.32**	**1341.86**	**775.19**	**609.47**

वर्ष 1996–2017 की अवधि के दौरान अनुसंधान एवं विकास उपकर समाहरण के कुल 7974.32 करोड़ रु. में से सरकार ने 21 वर्षों (1996–2017) के दौरान टीडीबी को 609.47 करोड़ रु. की संचित राशि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के गैर–योजना व्यय में से अनुदान सहायता के रुप में उपलब्ध कराया गया।

प्रशासन

वार्षिक रिपोर्ट और परीक्षित लेखे

प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड अधिनियम 1995 के अध्याय 12 में यह उल्लेख है कि बोर्ड अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष की गतिविधियों का पूरा वर्णन किया जाएगा। प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड अधिनियम के धारा 13 (4) के अनुसार बोर्ड केन्द्र सरकार को लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ अपनी लेखाओं की लेखा परीक्षित प्रति प्रस्तुत करेगा।

टीडीबी की वर्ष 2015–16 की वार्षिक रिपोर्ट सहित वार्षिक लेखों की लेखा परीक्षित प्रति राज्य सभा एवं लोक सभा के पटल पर क्रमशः दिनांक 22.03.2017 और 23.03.2017 को रख दी गई है।

टीडीबी सचिवालय

नए पदधारी

सीडीआर. स्मृति त्रिपाठी (रिटा.) ने 3 फरवरी, 2017 से अवशोसन के आधार पर अवर सचिव, प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड का कार्यभार ग्रहण किया।

आयकर छूट

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी), नई दिल्ली ने टीडीबी को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10[23सी (iv)], के तहत आकलन वर्ष 2000–01 और आगे के लिए 18 मई, 2007 एवं 21 मई, 2007 को जारी अधिसूचना सं. 173/2007 के तहत छूट प्रदान की है।

राजभाषा कार्यान्वयन

टीडीबी ने अपने गठन के समय से सरकार के राजभाषा संबंधी विभिन्न प्रावधानों को कार्यान्वित किया है और अधिसूचनाएं, वार्षिक रिपोर्ट, परियोजना वित्तपोषण दिशा निर्देश, ब्रोशर्स, वाउचर्स इत्यादि को हिन्दी एवं अंग्रेजी रुप में मुद्रित किया है। विभिन्न प्रदर्शनियों में दर्शाए जाने वाली प्रदर्शन संबंधी वस्तुओं / पैनलों को हिन्दी एवं अंग्रेजी में तैयार किया गया है।

प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड खातों का लेखापरीक्षित वार्षिक विवरण वर्ष 2016–17 के लिए

प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड

31 मार्च, 2017 की स्थितिनुसार तुलन–पत्र

(राशि रु. में)

कॉरपस / कैपिटल फंड और दायित्व	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
कॉरपस / कैपिटल फंड	1	9,96,70,13,160	9,41,88,62,234
रिजर्व और सरप्लस	2	-	
निर्धारित / इनडॉवमेंट फंड	3	4,94,47,559	5,79,11,687
सुरक्षित ऋण और लेनदारी	4	-	-
असुरक्षित ऋण और लेनदारी	5	-	-
आस्थगित क्रेडिट दायित्व	6	-	-
वर्तमान दायित्व और प्रावधान	7	1,01,00,919	99,92,974
कुल		**10,02,65,61,638**	**9,48,67,66,895**
परिसम्पत्तियाँ			
निर्धारित परिसम्पत्तियाँ	8	42,79,480	44,04,313
निर्धारित इनडॉवमेंट फंड में निवेश	9	65,99,000	65,99,000
निवेश – अन्य	10	2,23,04,81,571	2,20,16,73,340
वर्तमान परिसम्पत्तियाँ, ऋण, अग्रिम इत्यादि	11	7,78,52,01,587	7,27,40,90,242
विविध खर्चे (छूट न दिए जाने अथवा समायोजित न किए जाने की सीमा तक)			
कुल		**10,02,65,61,638**	**9,48,67,66,895**
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	24		-
आकस्मिक दायित्व और लेखों पर टिप्पणियाँ	25		-

-ह-
(डा. बिन्दु डे)
सचिव
प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड

-ह-
(प्रो. आशुतोष शर्मा)
अध्यक्ष
प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड

प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष की आय एवं व्यय का लेखा

(राशि रु. में)

आय	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
बिक्री / सेवाओं से आय	12	-	-
अनुदान / सब्सिडी	13	30,30,00,000	30,00,00,000
फीस / अंशदान	14	-	-
निवेश से आय (ईयरमार्क्ड/इनडोव में निवेश पर आय)	15	-	-
राजस्व, प्रकाशन आदि से आय	16	67,73,214	30,10,762
अर्जित ब्याज	17	53,87,59,669	53,30,85,105
अन्य आय	18	50,17,730	7,64,349
पूर्ण हो चुकी और चल रही मदों में वृद्धि/गिरावट	19	-	-
कुल (क)		**85,35,50,613**	**83,68,60,216**
व्यय			
स्थापना व्यय	20	2,29,91,710	1,84,62,366
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	21	21,57,98,678	4,84,49,413
अनुदान, सब्सिडी इत्यादि पर व्यय	22	5,94,00,000	11,09,89,391
ब्याज	23	-	-
मूल्यह्रास (अनुसूची 8 के तदनुसार वर्ष के अंत तक सकल योग)		9,31,994	5,70,221
कुल (ख)		**29,91,22,382**	**17,84,71,391**
व्यय पर आय में अधिकता (क–ख)		55,44,28,231	65,83,88,825
पहले की अवधि का समायोजन		2,715	(55,52,351)
जनरल रिजर्व में स्थानांतरण		-	-
कॉरपस फंड में दिया गया अतिरिक्त कोष		**55,44,30,946**	**65,28,36,474**
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	24	-	-
आकस्मिक दायित्व और लेखों पर टिप्पणियाँ	25	-	-

-ह-
(डा. बिन्दु डे)
सचिव
प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड

-ह-
(प्रो. आशुतोष शर्मा)
अध्यक्ष
प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड

प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष की प्राप्तियाँ एवं भुगतान का लेखा

(राशि रु. में)

प्राप्तियाँ		वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
आरंभिक कोष			
	लघु अवधि जमा में निवेश	43,20,00,000	52,02,08,332
	सुलभ नकद	1,23,557	13,037
	बैंक में नकद	30,63,97,743	23,01,73,455
	डीएफआईडी – इन्वेन्ट	2,91,67,365	36,158
प्रौद्योगिकी विकास एवं आवेदन के लिए फंड			
i.	टी डी फंड	30,30,00,000	30,00,00,000
ii.	लघु अवधि जमा पर ब्याज	350,21,306	4,86,38,653
iii.	ऋण पर ब्याज	12,63,82,620	6,18,71,525
iv.	राजस्व पर ब्याज	1,92,459	1,12,916
v.	अनुदान पर ब्याज	6,39,153	1,60,588
vi.	ऋण की अदायगी	28,46,97,567	30,65,72,805
vii.	राजस्व	67,73,214	30,08,066
viii.	दान	1,03,000	22,000
ix.	बचत खातों पर ब्याज (ईपीएफ खाते सहित)	39,97,235	35,39,169
x.	कर्मचारियों को अग्रिम	-	-
xi.	विविध प्राप्तियाँ	1,13,877	80,395
xii.	सिक्यूरिटि जमा प्राप्ति / अग्रिम	-	-
xiii.	वेतन से वसूली	19,65,154	17,33,511
xiv.	यूटीआई–एसेन्ट इंडिया फंड एवं आईटीवीयूएस	75,35,816	-
xv.	जीवीएफएल	-	-
xvi.	लाभांश	48,00,853	14,79,656
xvii.	सिडबी वेंचर फंड	57,54,569	85,68,716
xviii.	वेंचर ईस्ट टीनेट फंड	91,69,046	97,13,180
xix.	अन्य प्राप्तियाँ	3,588	52,722
xx.	डीएफआईडी – इन्वेंट	-	3,02,36,072
कुल		**1,55,78,38,122**	**1,52,62,20,956**

-ह-

(डा. बिन्दु डे)
सचिव
प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड

-ह-

(प्रो. आशुतोष शर्मा)
अध्यक्ष
प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड

प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष की प्राप्तियाँ एवं भुगतान का लेखा

(राशि रु. में)

भुगतान		वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
स्थापना व्यय			
i.	वेतन	2,08,70,215	1,71,56,588
ii.	यात्रा व्यय (घरेलू)	30,05,924	15,58,685
iii.	पारिश्रमिक	99,600	39,600
iv.	समयोपरि भत्ता	-	-
v.	चिकित्सा व्यय	3,04,423	5,85,129
vi.	प्रतिनियुक्ति के लिए पेंशन अंशदान	6,15,981	6,09,334
कार्यालय व्यय			
i.	टेलीफोन / टेलेक्स	24,65,020	8,27,821
ii.	डाक टिकट	1,48,074	1,53,318
iii.	पेट्रोल, तेल, लूब्रीकेन्टस	76,410	83,766
iv.	मरम्मत एवं रख–रखाव	5,58,003	4,42,075
v.	उपभोज्य स्टोर्स एवं छपाई	9,05,772	11,66,879
vi.	समाचार पत्र एवं पत्रिका	42,163	14,821
vii.	मनोरंजन एवं अतिथि सत्कार	1,53,841	2,21,907
viii.	बैठकों पर व्यय	9,94,828	9,29,714
ix.	विज्ञापन एवं प्रचार	89,09,634	43,75,391
x.	प्रौद्योगिकी दिवस व्यय	29,93,330	16,92,864
xi.	विविध व्यय	8,62,513	9,79,475
xii.	राष्ट्रीय पुरस्कार	30,00,000	10,00,000
xiii.	पुस्तकालय किताबें एवं जरनल्स	2,160	2,975
xiv.	विधि प्रभार	42,37,986	93,97,320
xv.	परिसम्पत्ति प्रबंधन प्रभार	1,85,05,737	2,24,49,080
xvi.	विशेषज्ञों को टी.ए. / डी.ए.	25,11,072	10,77,110
xvii.	विशेषज्ञों को पारिश्रमिक	23,42,542	11,80,500
xviii.	अग्रिम धन	-	1,00,000
xix.	बैंक प्रभार	-	4,865
xx.	स्थापना दिवस	6,70,096	-
xxi.	किराया	55,000	-
xxii.	अन्य विभागों से वसूली का प्रेषण	19,65,154	17,33,511
xxiii.	सुरक्षा जमा	1,10,000	-
xxiv.	शुल्क एवं कर	7,07,661	-

प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष की प्राप्तियाँ एवं भुगतान का लेखा

(राशि रु में)

भुगतान		वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
बोर्ड व्यय			
i.	सदस्यों को टी.ए. / डी.ए.	97,901	1,100
ii.	बोर्ड की बैठक का व्यय	1,46,455	81,811
iii.	बोर्ड के सदस्यों का शुल्क	82,500	30,000
पूंजीगत व्यय			
i.	अचल संपत्तियां	8,66,408	15,83,848
टीडीएफ से वितरण			
i.	ऋण	99,80,00,000	26,98,50,000
ii.	अनुदान	594,00,000	11,09,89,391
iii.	वेंचर इंस्ट टीनेंट फंड II	-	11,10,000
iv.	आरवीसीएफ	-	1,80,00,000
v.	जीआईटीए	46,99,000	2,40,20,000
vi.	सिडबी वीसीएफ	1,31,02,303	5,78,12,275
vii.	सीफ इंडिया एग्रीबिजनैस फंड	56,05,510	2,20,10,228
viii.	आईवीकेप वेंचर ट्रस्ट फंड–1	-	15,00,00,000
ix.	इंडियन फंड फॉर सस्टेनेबल एनर्जी (सीआईआईई)	2,78,60,449	3,52,60,910
x.	डीएफआईडी–इन्वेंट	83,18,807	-
अंतशेष			
i.	बैंक में लघु अवधि जमा डीएफआईडी सहित	6,93,00,000	43,20,00,000
ii.	सुलभ नकद	69,604	1,23,557
	बैंक में नकदी		
क)	बैंक राशि	25,03,27,087	30,63,97,743
ख)	बैंक राशि –डीएफआईडी इन्वेंन्ट	4,28,48,559	2,91,67,365
कुल		**1,55,78,38,122**	**1,52,62,20,956**

-ह-
(डा. बिन्दु डे)
सचिव
प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड

-ह-
(प्रो. आशुतोष शर्मा)
अध्यक्ष
प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड

प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष को तुलन पत्र के एक भाग को बनाने वाली अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 1 – कॉरपस / कैपिटल फंड :				
	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
वर्ष के प्रारंभ में शेष	9,41,88,62,234			8,76,60,25,760
जमा: कॉरपस / कैपिटल फंड में अंशदान	-		-	-
जमा: आय और व्यय लेखे से स्थानांतरित सकल आय का शेष	55,44,30,946			65,28,36,474
घटा: माफ किये गये ऋण (नोट 25 देखें)	62,80,020			-
वर्श के अंत में कोष		**9,96,70,13,160**		**9,41,88,62,234**

(राशि रु. में)

अनुसूची 2 – रिजर्व और आपूर्ति :				
	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
1. कैपिटल रिजर्व:				
पिछले एकाउंट के अनुसार	-	-	-	-
वर्ष के दौरान जमा	-	-	-	-
घटा: वर्ष के दौरान कटौती	-	-	-	-
2. पूनर्मूल्यांकन रिजर्व:				
पिछले एकाउंट के अनुसार	-	-	-	-
वर्ष के दौरान जमा	-	-	-	-
घटा: वर्ष के दौरान कटौती	-	-	-	-
3. विशेष रिजर्व:				
पिछले एकाउंट के अनुसार	-	-	-	-
वर्ष के दौरान जमा	-	-	-	-
घटा: वर्ष के दौरान कटौती	-	-	-	-
4. सामान्य रिजर्व:				
पिछले एकाउंट के अनुसार	-	-	-	-
वर्ष के दौरान जमा	-	-	-	-
घटा: वर्ष के दौरान कटौती	-	-	-	-
कुल योग				

प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष को तुलन पत्र के एक भाग को बनाने वाली अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 3 – निर्धारित / इनडोवमेंट फंड				
	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
दायित्व				
अ. आईडीबीआई का वीसीएफ				
1) भारत सरकार से आई डी बी आई द्वारा प्राप्त अंशदान		28,84,00,000		28,84,00,000
निवेश से आय				
क) ब्याज	13,08,52,144		13,08,52,144	
ख) राजस्व	5,51,97,900		5,51,97,900	
ग) लाभांश	86,23,794		86,23,794	
घ) उपार्जित आय घटा छूट	2,39,03,76,810		2,39,03,76,810	
	2,58,50,50,648		**2,58,50,50,648**	
घटा : टीडीबी को दी गई राशि	21,25,00,000		21,25,00,000	
	2,37,25,50,648		**2,37,25,50,648**	
घटा : पूर्व में वसूली गई राजस्व एवं मूल में समायोजित	1,12,50,000		1,12,50,000	
	2,36,13,00,648		**2,36,13,00,648**	
घटा : माफ किया गया ऋण	4,36,36,450		4,36,36,450	
घटा : निवेश की बिक्री से घाटा	26,76,250		26,76,250	
	2,31,49,87,948		**2,31,49,87,948**	
घटा : ऋण पर किया गया प्रावधान	8,10,04,357		8,32,79,357	
घटा : ब्याज एवं एफआईएलडी पर किये गये प्रावधान	2,39,03,76,810		2,39,03,76,810	
घटा : लेखा शुल्क एवं अन्य व्यय	17,52,075		17,61,564	
घटा : आईडीबीआई को प्रदान किया गया प्रबंधन शुल्क	14,32,60,000		13,63,00,000	
घटा : निवेश के मूल्य मे कमी	26,26,000	(30,40,31,294)	26,26,000	(29,93,55,783)
		(1,56,31,294)		(1,09,55,783)
टीडीबी से प्राप्त राशि (*)		2,22,30,294		1,75,54,783
		65,99,000		**65,99,000**
ख. प्रौद्योगिकी कोष के लिए अभिनव उपक्रम (इन्वेंट) – डीएफआईडी		**4,28,48,559**		**5,13,12,687**
कुल		**4,94,47,559**		**5,79,11,687**

(*)

1) निधि के गैर निष्पादन के कारण, आईडीबीआई द्वारा दावा किए गये प्रबंधन व्यय की राशि टीडीबी द्वारा स्वीकार नहीं की गई।

2) आईडीबीआई को टीडीबी द्वारा देय के रूप में दिखाए गए 2,22,30,294/– की राशि को टीडीबी के बैलेंस शीट में देय ऋण के रूप में स्वीकार नही किया गया है।

प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष को तुलन पत्र के एक भाग को बनाने वाली अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 4 – प्रतिभूत ऋण एवं उधार :				
	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
1. केन्द्र सरकार	-	-	-	-
2. राज्य सरकार (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-
3. वित्तीय संस्थाएं				
क) आवधिक ऋण				
ख) प्राप्त ब्याज और देय	-	-	-	-
4. बैंक :				
क) आवधिक ऋण				
– प्राप्त ब्याज और देय	-	-	-	-
ख) अन्य ऋण				
– प्राप्त ब्याज और देय	-	-	-	-
5. अन्य संस्थान एवं एजेंसियां	-	-	-	-
6. डिबेंचर्स एवं बॉन्डस	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-

टिप्पणी : वर्ष के भीतर देय राशि

(राशि रु. में)

अनुसूची 5 – अप्रतिभूत ऋण एवं उधार:				
	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
1. केन्द्र सरकार	-	-	-	-
2. राज्य सरकार (निर्दिष्ट करें)				
3. वित्तीय संस्थाएं	-	-	-	-
4. बैंक :				
क) आवधिक ऋण	-	-	-	-
ख) अन्य ऋण (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-
5. अन्य संस्थान एवं एजेंसियां	-	-	-	-
6. डिबेंचर्स एवं बॉन्डस	-	-	-	-
7. अचल जमा	-	-	-	-
8. अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-

प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष को तुलन पत्र के एक भाग को बनाने वाली अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 6 – आस्थगित ऋण देयताएं :				
	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
क. कैपिटल उपस्करों एवं अन्य परिसंपत्तियों के ऋण भार द्वारा सुरक्षित सहमति	-	-	-	-
ख. अन्य				
टिप्पणी : वर्ष के भीतर देय राशि	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-

(राशि रु. में)

अनुसूची 7 – चालू देयताएं एवं प्रावधान :				
	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
क. चालू देयताएं				
1. सहमति	-			-
2. विविध लेनदार				
क) माल के लिए				
ख) अन्य				-
3. प्राप्त प्रतिभूत		50,000		50,000
4. ब्याज प्राप्ति लेकिन इनपर देय नहीं:				
क) प्रतिभूत ऋण / उधार				
ख) अप्रतिभूत ऋण / उधार	-			-
5. सांविधिक देयताएं				
क) अतिदेय	-	1,97,908		7,05,511
ख) अन्य				
6. अन्य चालू देयताएं				
क) प्रतिनियुक्ति के लिए पेंशन अंशदान		16,41,175		6,15,981
ख) लेखा परीक्षा शुल्क		4,42,745		3,62,745
ग) पिछला समायोजन		-		75,00,000
घ) अन्य		-		-
कुल (क)		**23,31,828**		**92,34,237**
ख. प्रावधान				
1. टैक्स के लिए				
2. ग्रेच्यूटी		8,35,034		7,58,737
3. अधिवर्षता / पेंशन				
4. एकत्रित अवकाश का नकदीकरण				
5. विधि खर्च		69,34,057		
कुल (ख)		**77,69,091**		**7,58,737**
कुल (क + ख)		**1,01,00,919**		**99,92,974**

प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष को तुलन पत्र के एक भाग को बनाने वाली अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 8 : स्थायी परिसम्पत्ति : विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	वर्ष के आरंभ में कीमत / मूल्यांकन	वर्ष के दौरान जोड़े गए	वर्ष के दौरान कटौतियां	वर्ष के अंत तक कीमत / मूल्यांकन	वर्ष के आरंभ में	वर्ष के दौरान जोड़े गए	वर्ष के दौरान कटौतियां	वर्ष के अंत तक कुल	31.03.2017 तक	31.03.2016 तक
क. स्थायी परिसम्पत्ति										
1. जमीन										
क) फ्रीहोल्ड										
2. बिल्डिंग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क) फ्रीहोल्ड जमीन										
ख) लीजहोल्ड जमीन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) स्वामित्वधारी फ्लैट / परिसर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) जमीन पर अधिरचना अस्तित्व से संबद्ध नहीं	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. प्लांट एवं मशीनरी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. वाहन	6,74,375	-	-	6,74,375	-	1,01,156	-	1,01,156	5,73,219	6,74,375
5. फर्नीचर / फिक्सचर	27,92,552	87,283	-	28,79,835	14,51,816	1,34,074	-	15,85,890	12,93,945	13,40,736
6. कार्यालय उपस्कर	33,40,854	4,45,301	2,21,288	35,64,867	17,03,611	2,45,588	1,41,041	18,08,158	17,56,707	16,37,243
7. कम्प्यूटर / पैरीफेरल्स	20,50,520	-		20,50,520	12,98,559	4,51,176	-	17,49,735	3,00,785	7,51,961
8. इलेक्ट्रिक अधिष्ठापन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. पुस्तकालय की किताबें	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. सॉफ्टवेयर (पीएमएस)	-	3,54,824	-	3,54,824	-	-	-	-	3,54,824	-
11. अन्य अचल परिसम्पत्तियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
चालू वर्ष का कुल	**88,58,301**	**8,87,408**	**2,21,288**	**95,24,421**	**44,53,986**	**9,31,994**	**1,41,041**	**52,44,939**	**42,79,480**	**44,04,315**
ख. कैपिटल चल रहा कार्य	-	-	-	-	-	-	-	-		-
कुल	**88,58,301**	**8,87,408**	**2,21,288**	**95,24,421**	**44,53,986**	**9,31,994**	**1,41,041**	**52,44,939**	**42,79,480**	**44,04,315**
(उपर्युक्त को शामिल करते हुए किराए पर लिए गए परिसम्पत्तियों की लागत पर दी जाने वाली टिप्पणियां)										
पिछला वर्ष	**106,81,570**	**15,83,848**	**34,07,118**	**88,58,300**	**64,20,460**	**5,70,221**	**25,36,694**	**44,53,987**	**44,04,313**	

टिप्पणी: वर्ष के दौरान रू 2,21,288/- की संपति (एसी) जो प्रयोग करने योग्य नही थे या गैर कार्यात्मक थे को खत्म कर दिया गया।

प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष को तुलन पत्र के एक भाग को बनाने वाली अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 9 – निर्धारित / इनडोवमेंट फंडों से निवेश			
	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	-		-
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	-		-
3. शेयर	-		-
4. डिबेंचर्स और बॉन्ड्स	-		-
5. सब्सिडियरिज एवं संयुक्त उद्यम	-		-
6. आई डी बी आई का वीसीएफ (परिसम्पत्ति)	-		-
निवेश			
(1) ऋण	8,10,04,357		8,32,79,357
घटा : प्रावधान	8,10,04,357		8,32,79,357
(2) इक्विटी	92,25,000		92,25,000
घटा : मूल्य में कमी	26,26,000	65,99,000	26,26,000
वसूली योग्य			
(1) ब्याज	29,97,69,021		29,97,69,021
(2) एफआईएलडी	2,09,06,07,789		2,09,06,07,789
	2,39,03,76,810		2,39,03,76,810
घटा : प्रावधान	2,39,03,76,810		2,39,03,76,810
कुल		**65,99,000**	**65,99,000**

प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष को तुलन पत्र के एक भाग को बनाने वाली अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 10 – निवेश – अन्य :

		वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियों में		-		-
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां		-		-
3. शेयर – इक्विटी भागीदारी		-	28,46,72,726	28,46,72,726
4. डिबेंचर्स और बॉन्ड्स		-		-
5. सहायक उद्यम एवं संयुक्त उद्यम		-		-
6. वेन्चर फंड				
क) यूटीआई एसेंट इंडिया फंड	29,92,72,098			
घटा : विमोचन	75,35,816	29,17,36,282		29,92,72,098
ख) एपीआईडीसी वेन्चर फंड		30,00,00,000		30,00,00,000
ग) वेन्चर ईस्ट टीनेट फंड	12,29,31,623			
घटा : विमोचन	91,69,046	11,37,62,577		12,29,31,623
घ) जीवीएफएल	15,00,00,000			
जमा : विमोचन	-	15,00,00,000		15,00,00,000
ङ) आरवीसीएफ	13,25,92,511			
घटा : विमोचन	-	13,25,92,511		13,25,92,511
च) एसआईडीबीआई वीसीएफ	12,77,29,711			
जमा : वितरण	1,31,02,303	-		
घटा : विमोचन	57,54,569	13,50,77,445		12,77,29,711
छ) आईवीकेप वेंचर ट्रस्ट फंड–1		25,00,00,000		25,00,00,000
ज)मल्टी सेक्टर सीड कैपिटलफंड		20,00,00,000		20,00,00,000
झ) सीफ इंडिया एग्रीबिजनैस फंड	21,80,28,721			
जमा : वितरण	56,05,910	22,36,34,631		21,80,28,721
ञ) इंडियन फंड फॉर सस्टेनेबल एनर्जी (सीआईआईई)	4,90,94,950			
जमा : वितरण	2,78,60,449	7,69,55,399	1,87,37,58,845	4,90,94,950
7. जीआईटीए		6,73,51,000		
जमा : वितरण		46,99,000	7,20,50,000	6,73,51,000
कुल			**2,23,04,81,571**	**2,20,16,73,340**

प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष को तुलन पत्र के एक भाग को बनाने वाली अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 11 – चालू परिसम्पत्ति, ऋण, अग्रिम इत्यादि :			
	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष
क. चालू परिसम्पत्ति			
1. सामान्य सूची			
क) स्टोर्स एवं स्पेयर्स			
ख) लूज टूल्स			
ग) स्टॉक इन ट्रेड			
i) समाप्त माल			
ii) चल रहा कार्य			
iii) कच्ची सामग्री	-	-	-
2. विविध देनदार			
क) छः महीनों से अधिक अवधि से लंबित ऋण			
ख) अन्य			
3. हाथ में नकद कोष			
(चैक / ड्राफ्ट और अग्रदाय सहित)		69,604	1,23,557
4. बैंक कोष			
क) सूचीगत बैंकों के साथ			
– चालू खाते पर			
– जमा खाते पर – टीडीबी (इपीएफ खाते सहित)	25,03,27,087		30,63,97,743
– बचत खातों पर – इन्वेंट डीएफआईडी	4,28,48,559	29,31,75,646	2,91,67,365
ख) गैर–सूचीगत बैंकों के साथ			
– जमा खाते पर	6,93,00,000		41,00,00,000
– जमा खातों पर – इन्वेंट डीएफआईडी		6,93,00,000	2,20,00,000
ग) सूचीगत बैंकों के साथ–			
– चालू खाते पर			
– बचत खातों पर			
– जमा खाते पर			
5. डाक घर – बचत खाता			
कुल (क)		**36,25,45,250**	**76,76,88,665**

प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष को तुलन पत्र के एक भाग को बनाने वाली अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 11 – चालू परिसम्पत्ति, ऋण, अग्रिम इत्यादि (जारी है) :	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष
ख. ऋण, अग्रिम एवं अन्य परिसम्पत्तियां			
1. ऋण			
क) स्टाफ			
ख) अन्य सत्ताएं जो उनसे मिलती जुलती सत्ताओं की गतिविधियों / उद्देश्यों में सम्मिलित	-	-	-
ग) ऋण : शुरु हुए औद्योगिक इकाईयों को सहायता	3,58,06,32,583		3,62,52,49,602
जमा : वर्ष के दौरान	99,80,00,000		26,98,50,000
घटा : ऋण की अदायगी	29,37,47,434		(30,89,14,668)
घटा : बट्टे खाते में डाला गया	62,80,020		-
घटा : पूर्व अवधि समायोजन	-	4,27,86,05,129	(55,52,351)
2. नकद, अग्रिम एवं अन्य राशि की अथवा वस्तु अथवा उसके कीमत में वसूली			
क) कर्मचारियों को अग्रिम	-		-
ख) अन्य सरकारी विभागों से वसूली	10,38,686		10,38,686
ग) अन्य – प्रतिभूति जमा	2,33,000		1,23,000
घ) अन्य	7,680	12,79,366	11,268
3. प्राप्त आय			
क) निर्धारित / इनडोवमेंट फंड से निवेश पर			
ख) निवेश पर – लघु अवधि जमा	4,46,042		44,41,205
लघु अवधि जमा – इन्वेंट डीएफआईडी	-		1,40,457
ग) ऋण एवं अग्रिम पर	3,29,80,86,305		2,92,00,14,378
घटा : संदिग्ध ब्याज की वसूली का प्रावधान	14,98,67,154		
घटा : गैरवसूलीगत ब्याज को बट्टे खाते में डाला गया	58,93,351	3,14,27,71,842	
कुल (ख)		**7,42,26,56,337**	**6,50,64,01,577**
कुल (क + ख)		**7,78,52,01,587**	**7,27,40,90,242**

प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष को आय और व्यय के एक भाग को बनाने वाली अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 12 – बिक्री / सेवाओं से आय :	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष
1. बिक्री से आय			
क) तैयार माल की बिक्री	-	-	-
ख) कच्चे सामग्री की बिक्री	-	-	-
ग) कबाड़ की बिक्री	-	-	-
2. सेवाओं से आय			
क) श्रम एवं संसाधित प्रभार	-	-	-
ख) व्यावसायित / परामर्शी सेवाएं	-	-	-
ग) एजेंसी कमीशन और दलाली	-	-	-
घ) रखरखाव सेवाएं (उपस्कर / संपत्ति)	-	-	-
ङ) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-	-
कुल			

प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष को आय और व्यय के एक भाग को बनाने वाली अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 13 – अनुदान / सब्सिडी : (गैर वसूलीयोग्य अनुदान एवं वसूली गई सब्सिडी)	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष
1) केन्द्र सरकार	30,30,00,000		30,00,00,000
2) राज्य सरकार (रें)	-	-	-
3) सरकारी एजेंसियां	-	-	-
4) संस्थान / कल्याण बोर्ड	-	-	-
5) अंतर्राष्ट्रीय संगठन	-	-	-
6) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-	-
कुल	**30,30,00,000**	**-**	**30,00,00,000**

प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष को आय और व्यय के एक भाग को बनाने वाली अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 14 – शुल्क/अंशदान :	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष
1) प्रवेश शुल्क	-	-	-
2) वार्षिक शुल्क / अंशदान			
3) सेमिनार / कार्यक्रम शुल्क	-	-	-
4) परामर्शी शुल्क	-	-	-
कुल	-	-	-

टिप्पणी : प्रत्येक मद की बताई जाने वाली लेखा नीतियों का निर्धारित फंड से निवेश

प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष को आय और व्यय के एक भाग को बनाने वाली अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 15 – निवेश से आय :

(फंड में हस्तांतरित किया गया निर्धारित / इनडोवमेंट फंड से निवेश पर आय)

	निर्धारित फंड से निवेश		अन्य निवेश
	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष
1. ब्याज			
क) सरकारी प्रतिभूति पर			
ख) अन्य बॉन्ड्स / डिबेन्चर			
2. लाभांश			
क) शेयर पर			
ख) म्यूचूअल फंड प्रतिभूति पर			
3. किराए	-	-	-
4. अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-	-
कुल	-	-	-
निर्धारित / इनडोवमेंट फंड में हस्तांतरित			

प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष को आय और व्यय के एक भाग को बनाने वाली अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 16 – राजस्व, प्रकाशन इत्यादि से आय :	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष
1) राजस्व से आय		67,73,214	30,10,762
2) उपार्जित राजस्व			
घटा: राजस्व माफी			-
3) अन्य (निर्दिष्ट करें)			-
कुल		**67,73,214**	**30,10,762**

प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष को आय और व्यय के एक भाग को बनाने वाली अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 17 – अर्जित ब्याज :

	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष
1. आवधिक जमा पर			
क) सूचीगत बैंकों के साथ (डीएफआईडी सहित)	3,10,26,143		3,60,83,803
ख) गैर – सूचीगत बैंकों के साथ	-		-
ग) संस्थाओं के साथ	-		-
		3,10,26,143	-
2. बचत खातों पर			
क) सूचीगत बैंकों के साथ	39,97,235		35,39,169
ख) गैर – सूचीगत बैंकों के साथ	-		-
ग) डाक घर बचत खाता	-		-
घ) अन्य	-	39,97,235	-
3. ऋण पर			
क) कर्मचारी / स्टाफ			
ख) औद्योगिक इकाई को ऋण सहायता		50,29,04,680	49,31,88,629
4. राजस्व पर ब्याज		1,92,459	1,12,916
5. अनुदान पर ब्याज		6,39,152	1,60,588
कुल		**53,87,59,669**	**53,30,85,105**

टिप्पणी : स्रोत पर कर कटौती को दर्शाया गया है।

प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष को आय और व्यय के एक भाग को बनाने वाली अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 18 – अन्य आय :

	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष
1. संपत्तियों की बिक्री / निपटान से लाभ			
क) प्राप्त संपत्ति – यूटीआई की यूनिटें			
ख) अनुदान से प्राप्त अथवा निःशुल्क प्राप्त संपत्ति		-	(8,17,702)
2. यूनिटों के विमोचन से लाभ		-	-
3. लाभांश		48,00,853	14,79,656
4. विविध आय		1,13,877	80,395
5. विविध सेवाओं का आय			
6. दान		1,03,000	22,000
7. वेन्चर फंड से आय		-	-
कुल		**50,17,730**	**7,64,349**

प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष को आय और व्यय के एक भाग को बनाने वाली अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 19 – तैयार माल और चल रहे कार्य की वृद्धि / घटाव :	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष
क) बंद स्टॉक			
– तैयार माल	-	-	-
– चल रहा कार्य			
ख) घटा : ओपनिंग स्टॉक			
– तैयार माल	-	-	-
– चल रहा कार्य			
निवल वृद्धि / (घटाव) (क – ख)			

प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष को आय और व्यय के एक भाग को बनाने वाली अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 20 – स्थापना व्यय :	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष
क) वेतन और मजदूरी	1,89,05,061		1,54,27,064
ख) भत्ता और बोनस	-		-
ग) भविष्य निधि में अंशदान	19,65,154		17,33,511
घ) अन्य फंड में अंशदान	-		-
ङ) कर्मचारी कल्याण खर्च	99,600		39,600
च) कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति और आवधिक लाभों पर व्यय	16,41,175		6,15,981
छ) चिकित्सा प्रभारों की प्रतिपूर्ति	3,04,423		5,85,129
ज) ग्रेच्यूटी	76,297		61,081
कुल		**2,29,91,710**	**1,84,62,366**

प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष को आय और व्यय के एक भाग को बनाने वाली अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 21 – अन्य प्रशासनिक व्यय इत्यादि :		वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
क) राष्ट्रीय पुरस्कार		30,00,000	10,00,000
ख) विधि प्रभार		1,11,72,043	96,28,843
ग) संपत्ति प्रबंधन शुल्क		1,86,66,737	2,29,00,023
घ) बैंक प्रभार		-	4,865
ङ) टी.डी.एस. एवं ब्याज		179	-
च) परिसंपत्ति की बिक्री पर हानि		59,247	-
छ) मरम्मत एवं रख–रखाव		5,59,344	4,44,139
ज) डाक एवं टिकट		1,48,074	1,53,318
झ) प्रौद्योगिकी दिवस व्यय		29,93,330	16,92,864
ञ) वाहन चालन और रखरखाव		76,410	83,766
ट) टेलीफोन और संचार प्रभार		24,65,020	8,27,821
ठ) प्रिंटिंग, स्टेशनरी एवं उपभोज्य		9,10,915	11,67,441
ड) यात्रा और वाहन भत्ता			
क. घरेलु	25,88,957	-	
ख. विदेश	4,18,165	-	
ग. विशेषज्ञ	25,11,072	55,18,194	26,37,086
ढ) पुस्तकालय की किताबें एवं आवधिक		2,160	2,975
ण) बोर्ड सदस्यों को टीए/डीए/शूल्क		1,80,401	1,100
त) लेखा परीक्षा शुल्क		80,000	80,000
थ) आवभगत व्यय		1,53,841	2,21,907
द) बैठकों पर व्यय		9,97,836	9,35,498
ध) व्यवसायिक प्रभार		23,57,667	11,80,500
न) क) खराब एवं संदेहास्पद ऋण /अग्रिम का प्रावधान **(नोट 25(11) देखें)**		14,98,67,154	-
ख) गैरवसूली योग्य शेष का समापान – ऋण पर वसूली नहीं किया जाने वाला ब्याज **(नोट 25(10) देखें)**		58,93,351	-
प) स्थापना दिवस		6,70,096	-
फ) विविध व्यय		8,69,107	9,84,222
ब) अखबार एवं पत्रिका		42,163	14,821
भ) विज्ञापन एवं प्रचार		89,13,954	43,75,502
म) बोर्ड के खर्चे एवं शुल्क		1,46,455	1,12,722
य) किराया		55,000	-
कुल		**21,57,98,678**	**4,84,49,413**

प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष को आय और व्यय के एक भाग को बनाने वाली अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 22 – अनुदान पर व्यय :

	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष
1)संस्थानों / संगठनों को दिया गया अनुदान			
(i) इन्क्यूबेटर्स		5,94,00,000	11,09,89,391
(ii) अन्य एजेंसियां	-		-
2)संस्थानों / संगठनों को दी गई सब्सिडी			
कुल	**-**	**5,94,00,000**	**11,09,89,391**

नोटः संस्थाओं के नाम, उनकी गतिविधियों के साथ अनुदान / सब्सिडी का खुलासा

प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष को आय और व्यय के एक भाग को बनाने वाली अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 23 – ब्याज :

	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष
क) अचल ऋण पर			
ख) अन्य ऋण पर (बैंक प्रभार सहित)			
ग) अन्य (निर्दिष्ट करें)			
कुल			

अनुसूची–24

लेखा संबंधी प्रमुख नीतियां एवं लेखाओं पर टिप्पण – 2016–17

क. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. प्राप्तियों एवं भुगतानों से संबंधित लेखा को नकद प्राप्ति जर्नल से तैयार किया जाता है और यह विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत नकद लेन–देन का एक सारांश है। इसमें पूंजी तथा राजस्व दोनों प्रकार की आवतियों और भुगतानों का रिकॉर्ड रखा जाता है।

2. आय एवं व्यय लेखा वर्ष में हुए आय और व्यय का सारांश है। यह नकद तथा उपार्जन दोनों आधार पर तैयार किया जाता है। यह केवल राजस्व प्रकृति के आय एवं व्यय का रिकॉर्ड रखता है। संवितरित ऋण राशि पर उपार्जित ब्याज का लेखा, जिस वर्ष ऋण की किस्त जारी की जाती है, के लिए रखा जाता है तथापि ब्याज को वास्तव में तब प्राप्त किया जा सकता है जब परियोजना संबंधित ऋण करारों की शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार पूरी कर ली गई है। खातों में, साल के लिए स्टाफ के बकाया और लेखापरीक्षा शुल्क के अलावा, बकाया परन्तु भुगतान नही किये गये खर्चों के लिए प्रावधान नही किया गया।

3. अचल सम्पत्तियों पर मूल्यह्रास, ह्रासमान संतुलित पद्धति पर आयकर अधिनियम, 1961 में निर्धारित दरों के आधार पर प्रदान किया जाता है। वित्तीय वर्ष के दौरान अर्जित/बेची गई/स्थानांतरित/त्यागी गई अचल सम्पत्तियों पर कोई मूल्यह्रास नही प्रदान किया जाता है। अचल सम्पत्तियों में वृद्धि की गणना अधिग्रहण लागत के आधार पर की जाती है।

4. राजस्व संबंधी भुगतान आवती एवं भुगतान लेखा और तुलन पत्र (बैलेंस सीट) में प्राप्ति के आधार पर लिए जाते हैं।

5. सरकारी अनुदानों को आवती आधार पर मान्यता दी जाती है। व्यय नहीं की गई राशि को भारत सरकार को वापस नहीं किया जाता क्योंकि सरकार द्वारा जारी अनुदानों को प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड अधिनियम, 1995 की धारा 9 (1) (क) के अनुसार प्रौद्योगिकी विकास और अनुप्रयोग हेतु निधि में जमा कर दिया जाता है और इस प्रकार किसी प्रकार की वापसी की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः भारत सरकार को वापस करने हेतू कोई राशि बकाया नहीं है।

6. प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड अधिनियम, 1995 की धारा (1) के अनुसार प्रौद्योगिकी विकास और अनुप्रयोग हेतू निधि द्वारा प्रदत्त राशियों की अधिवसूली, ऋणों पर ब्याज की प्राप्तियों, राजस्व, अनुदानों और किसी अन्य स्त्रोत से प्राप्त राशि को इस निधि में जमा कर दिया जाता है। इस प्रावधान को ध्यान में रखकर तुलन पत्र (बैलेंस सीट) तैयार किया गया है।

7. आईडीबीआई द्वारा अनुरक्षित निर्धारित/स्थायी निधियों (उद्यम पूंजी निधि) के तुलन पत्र ने निम्नलिखित को दर्शाया है :

(क) राजस्व, प्रबंधन शुल्क और उस पर पैनल ब्याज के संबंध में आय/ परिव्यय जिन्हें वास्तविक प्राप्तियों / भुगतान के रुप में माना गया है को छोड़कर तुलन पत्र को प्रोदभवन आधार पर तैयार किया गया है।

(ख) परिसम्पत्तियों/ऋण/निवेश का मूल्यांकन, आईडीबीआई (फंड मैनेजर) द्वारा मूल्यांकित मूल्य पर किया गया और परिसम्पत्तियों की बुक मूल्य को कम करने के प्रायधान का अभिलेखन वित्तीय विवरण में उपलब्ध नोट्स के आधार पर किया गया।

(ग) तुलन पत्र के नोट के अनुसार, ग्राहक बकाया/वसूली में कोई बदलाव नहीं है, ज्ञापन पुस्तकों में ग्राहकों से वसूली योग्य राशि में अर्जित ब्याज/अतिरिक्त ब्याज आदि सभी राशियां शामिल होंगी। बकाया अर्जित ब्याज के साथ खराब ऋण को उस स्थिति में समाप्त किया जायेगा जहाँ वसूली प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है एवं ऋण खाते से कोई भी अदायगी की सम्भावना नही है और जिसे बोर्ड द्वारा समाप्त करने के लिए अनुमोदित किया गया है।

(घ) आईडीबीआई (वीसीएफ) के वित्तीय विवरण को तुलन पत्र के साथ उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये अन्य नोट्स एवं स्पष्टीकरण के साथ पढ़ा जायेगा।

8. निधि की राशियों को राष्ट्रीयकृत बैंकों में अल्पावधि जमा योजना में रखा जाता है अल्पावधि जमा पर ब्याज को प्राप्ती एवं भुगतान, लेखों और तुलन पत्र में दर्शाया गया है।

9. कंपनियों में निवेश को लागत मूल्य पर दर्शाया गया है। टीडीबी के मैंडेट के अनुसार यह निवेश टीडीबी के किसी भी कैपिटल अभिमूल्यन या अन्य लाभ के लिए नहीं किया गया है। शेयरों को उनके वास्तविक वसूली तक अधिग्रहण मूल्य के आधार पर लिया जायेगा। हालांकि, किसी भी कम्पनी के समापन/विघटन या किसी अन्य मामले में निवेश के उचित मूल्य में किसी भी प्रकार की स्थायी गिरावट की स्थिति में गिरावट मूल्य को आय एवं व्यय लेखों में चार्ज किया जायेगा।

10. अप्राप्ति के मामले में, किसी भी प्रकार के पुनर्निर्धारण करार (रों) को ऋण करार में निर्धारित नियम एवं शर्तों के आधार पर किया जायेगा एवं खाते में बकाया राशि मूल करार के आधार पर बहाल होगा। इस वजह से, मूल करार पर वापस जाने के कारण ऋणकर्ता के बकाया राशि में वृद्धि हो सकती है।

11. अगर उधारकर्ता ऋण करार के शर्तों के तहत ऋण/ब्याज की राशि का भुगतान करने में अक्षम है और वसूली का मामला विवाचन को निर्दिष्ट किया गया है तो बकाया ऋण राशि, दंडविषयक ब्याज के साथ ब्याज को मामले को विवाचन को निर्दिष्ट करने के तारीख पर रोक दिया जाता है। पुरस्कार शर्तों के अनुसार पारित पुरस्कार के प्राप्त हाने के बाद ही बकाया ब्याज का प्रावधान या समायोजन किया जाता है।

12. अगर उधरकर्ता ने ऋण करार के शर्तों के तहत ऋण/ब्याज की राशि का भुगतान करने में डिफॉल्ट किया है और उचित कानूनी प्रकिया में गये बिना ही परिसमापन में चला गया है तो परिसमापन की तारीख तक ब्याज लगाया जायेगा। चूंकि वसूली की तारीख तक ब्याज की वसूली का अधिकार टीडीबी के पास है अतः खारिज करने के लिए अंतिम प्रावधान आधिकारिक परिसमापक से मूलधन एवं ब्याज के अंतिम भुगतान की प्राप्ति के बाद ही किया जाता है।

13. ऋणकर्ता से अप्राप्ति एवं अनुवर्ती आर्बिट्रेसन अवार्ड पास होन के मामले में, ऋण एवं ब्याज का पुनःव्याख्यान एवं ब्याज की चार्जिंग आर्बिट्रेसन अवार्ड के आधार पर किया जायेगा। इस वजह से, ऋणकर्ता के बकाये ब्याज की राशि में वृद्धि/गिरावट हो सकती है।

14. मध्यस्थता कार्रवाई शुरु होने की स्थिति में, आर्बिट्रेसन कार्रवाई के शुरु होने से अवार्ड के प्राप्त होने तक ब्याज की गणना को रोक दिया जाता है। अवार्ड के प्राप्त होन के बाद, उस पर ऋण एवं ब्याज की गणना अवार्ड के आधार पर किया जाता है जबकि अन्य शर्तें नियत रहती हैं।

15. पूर्ण सम्मत राशि के लिए निधि न जारी करने और समयबद्ध पुनः भुगतान अनुसूची सक्रिय होने की स्थिति में, ब्याज की गणना करार के अनुसार लागू दर पर जारी राशि के आधार पर की जाती है।

16. वेंचर फंड एवं सीड फंड में निवेश लागत के आधार पर किया जाता है। चुंकि, ये फंड लगातार अपनी गतिविधियों के संदर्भ में विकसित हो रहे हैं एवं यह एक निरंतर प्रकिया है, निवेश के मूल्य में किसी भी प्रकार के स्थायी परिवर्तन परिकल्पित या उपलब्ध नहीं है। वेंचर फंड के निवेश में लाभ/हानि को या तो फंड के बंद होने पर या फंड के कार्यकाल के दौरान आय के संवितरण के दौरान स्वीकृत किया जाता है।

17. जबतक टीडीबी द्वारा किसी और तरह से नही माना जाता, उधारकर्ता से प्राप्त भुगतान निम्न बकाया के हिसाब से किया जायेगा जैसे ब्याज सहित अतिरिक्त ब्याज, चूक राशि पर अतिरिक्त ब्याज और मुआवजा क्षति, बकाया एवं देय मूल या बोर्ड द्वारा निर्धारित और अनुमोदित तरीके से।

18. भंडार का सत्यापन वार्षिक आधार पर किया जाता है।

19. आंकड़ों को निकटतम रुपए में पूर्वांकित किया जाता है।

अनुसूची – 25

लेखाओं पर टिप्पणी

1. वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान टीडीबी को अनुदान के रुप में 3030.00 लाख (पिछले वर्ष 3000.00 लाख रु) प्राप्त हुआ ।

2. प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड के पास 31 मार्च, 2017 तक 233.59 करोड रू. (पिछले वर्ष 242.59 करोड़ रू.) की अतिदेय ऋण की राशि (राशि देय पर प्राप्त नहीं) है। इसके अतिरिक्त, 94.02 करोड़ (पिछले वर्ष 92.62 करोड़) का साधारण ब्याज, 170.60 करोड़ रू. (पिछले वर्ष 133.53 करोड़ रू.) के बराबर ऋण पर आधारित अतिरिक्त ब्याज और साधारण ब्याज पर अतिरिक्त ब्याज के रुप में 49.04 करोड़ रु. (पिछले वर्ष 35.77 करोड़ रु.) भी देय है।

3. दिवाला और दिवालियापन नीति 2016 के माध्यम से नॉन–परफॉरमिंग एसेट्स (एनपीए) पर भारत सरकार के नीति में बदलाव के साथ, टीडीबी अतिदेय खातों से प्रर्याप्त वसूली की उम्मीद कर रहा है। इसलिए, ऐसे मामलों में संदिग्ध ऋण के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है या किसी हानि को मान्यता नहीं दी गई है।

4. उद्यम पूंजी निधियों (वीसीएफ) में निवेश और मूल्यांकनः

		Amount Invested								NAV	
Particulars	Par Value of Unit	Outstanding Amount as on 31.03.2016		Addition during the year		Redemption during the year		Closing Amount as on 31.03.2017		NAV as on 31.03.16	NAV as on 31.03.17
		Amount (Rs.)	Number of Units	Amount (Rs.)	Number of Units	Amount (Rs.)	Number of Units	Amount (Rs.)	Number of Units		
APIDC Venture capital fund pvt ltd	100,000	300,000,000	3,000	-	-	-	-	300,000,000	3,000	63,425.00	57,327.00
GVFL Limited, Ahmedabad	100,000	150,000,000	1,500	-	-	-	-	150,000,000	1,500	87,835.00	79,354.00
Ivy Cap venture Trust Fund	100,000	250,000,000	2,500		-	-	-	250,000,000	2,500	141,959.31	159,280.95
fund/multi sector seed capital fund	10,000	200,000,000	20,000	-	-	-	-	200,000,000	20,000	20,755.00	18,551.00
SME Tech Fund- RVCF Trust II	100	132,592,511	1,325,925		-		-	132,590,511	1,325,925	191.62	120.21
SEAF India Agri business fund	500,000	218,028,721	436	5,605,910	11	-	-	223,634,631	447	419,171.00	394,294.00
SIDBI Venture capital Ltd - India Opportunitie fund	1,000	127,729,711	127,730	13,102,303	13,102	5,754,569	5,754.57	135,077,445	136,077	881.63	800.35
Ascent India Fund	100	299,272,098	2,992,721	-	-	7,535,816	75,358.16	291,736,282	2,917,363	51.87	40.51
Venture East TeNet fund II	758	122,931,623	150,000		-	9,169,046	-	113,762,577	150,000	1,271.00	1,207.00
CIIE- Indian Fund for Sustainable Energy (IIETrust)	100	49,094,950	490,950	27,860,449	278,604	-	-	76,955,399	769,554	98.71	99.22
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			

NAV Value (in Rs)

Current Year [illegible]

Previous Year [illegible]

नोटः वर्ष के दौरान वेंचर फन्ड्स से प्रतिदान टीडीबी द्वारा की गई पूंजीगत अंशदान के खाते में दिखाया गया है। वर्ष के दौरान मोचन पर कोई आय प्राप्त नहीं हुआ है। निधि द्वारा वितरिण के आधार पर आय उपर्युक्त अनुसूची 24 के पैरा 16 के अनुसार निधि के वितरण के आधार पर आया मान्यता प्राप्त है।

5. टीडीबी ने, परिस्थितीकी तंत्र के सभी प्रमुख तत्वों को कवर करने के अधिदेश के साथ, जो इन्डस्ट्री एवं तकनीकी शुरुआतकर्ताओं को लाभान्वित करेगा, डीएसटी एवं अन्य संस्थानों के साथ, सीआईआई के साथ संयुक्त वेंचर में क्रमशः 51:49 की इक्विटी भागीदारी के साथ मेसर्स ग्लोबल इन्नोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एलायन्स (जीआईटीए) के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया। टीडीबी का जीआईटीए में इक्विटी भागीदारी 7.35 करोड़ रु. की है। 31 मार्च, 2017 तक टीडीबी ने 7.21 करोड़ रु. जारी किया है।

6. वर्ष के दौरान निम्नलिखित अनुदान का संवितरण किया गया

क्रम सं.	कम्पनी का नाम	उद्देश्य	राशि (लाख में)
1.	मेसर्स अम्रिता टेक्नोलॉजी बिजनेस इन्क्यूबेटर	सीड सहायता	30.00
2.	मेसर्स टीआईईटीएस / टीबीआई, आईआईटी खड़गपुर	सीड सहायता	30.00
3.	मेसर्स फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की)	अनुदान	500.00
4.	मेसर्स एनआईटी कैलिकट	सीड सहायता	20.00
5.	मेसर्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स	अनुदान	9.00
6.	इन्डो फ्रेंचसेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एकवांस्ड रिसर्च (सेफिप्रा)	कार्यक्रम प्रबंधन	5.00
	कुल		**594.00**

7. भारत सरकार द्वारा अनुदानों से संबंधित उद्यम पूंजी निधि (वीसीएफ) लेन – देन के मद के भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) के दस्तावेजों के बकाये राशियों की प्राप्तियों और देनदारियों को प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड अधिनियम 1995 की धारा 10 के अनुसार 1 सितम्बर 1996 को बोर्ड को हस्तांतरित करने की आवश्यकता है। 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए बोर्ड के तुलन–पत्र में शामिल किया गया है। तुलन–पत्र में आईडीबीआई के वीसीएफ से संबंधित पिछले वर्ष के आंकड़ों को भी दर्शाया गया है।

8. टीडीबी के साथ, आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए), भारत सरकार एवं अंतराष्ट्रीय विकास विभाग (डीएफआईडी), यूनाईटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन गवर्नमेंट के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन दिनांक 29.08. 2013 के अनुसार यह निर्णय लिया गया कि "इनोवेटिव वेंचर्स एंड टेक्नोलॉजी फॉर डेवलेपमेंट (इवेंट)" प्रोग्राम के इन्क्यूवेसन कम्पोनेंट का कार्यान्वयन एवं समीक्षा टीडीबी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा किया जायेगा। टीडीबी की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करने की है कि निर्धारित फंड का खर्च निश्चित गतिविधियों पर यथोचित परिणाम प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। तदनुसार, टीडीबी को करार के तहत वर्ष के भीतर वितरण के लिए 4,17,79,461 / – रू. के बराबर जीबीपी 500000 / – की राशि प्राप्त हुई। टीडीबी को फंड प्रबंधक के रूप में यह राशि एक अलग बैंक खाते में रखना है एवं इसे परियोजना दिशा–निर्देश के अनुसार जारी करना है और प्रगति रिपोर्ट एवं लेखा परीक्षित लेखों को डीएफआईडी को प्रस्तुत करना है।

9. सम्पत्ति प्रबंधक के रिपोर्ट के मुताबिक, निक्को कॉरपोरेशन द्वारा कंपनी का संचालन बंद किए जाने के कारण इसमें 1846.00 लाख रू. के धारित प्रेफरेंस शेयरों में अवमूल्यन हुआ है। 691.04 लाख रू. (ब्याज सहित) की ऋण राशि भी कम्पनी पर बकाया है। हालांकि इस निवेश को खातों में बंद नही किया गया है क्योंकि वसूली कि प्रकिया जारी है। (उपरोक्त नोट 3 देखें)

10. वर्ष के दौरान निम्नलिखित राशि को बट्टे खाते में डाला गया।

कम्पनी का नाम	बट्टा खाता	
		(₹ लाख में)
	मूल	ब्याज + अतिरिक्त ब्याज
मेसर्स मिडास	12.80	16.99
मेसर्स वैल्यूपिच	50.00	21.20
मेसर्स एंजल हेल्थ	-	20.73
कुल	**62.80**	**58.92**

11. डीआरसी द्वारा अनुशंसित और बोर्ड की उप–समिति द्वारा अनुमोदि त प्रस्ताव के अनुसार अपने बकाया राशि का भुगतान करने के तैयार होने के कारण निम्नलिखित छः कम्पनियों के खिलाफ ब्याज और अतिरिक्त ब्याज की राशि का प्रावधान किया गया।

कम्पनी का नाम	ब्याज एवं अतिरिक्त ब्याज पर प्रावधान
	(₹ लाख में)
मेसर्स मेडिरेड	705.39
मेसर्स सुदर्शन	152.04
मेसर्स लॉजिक इस्टर्न	393.88
मेसर्स इन्ड स्वीफ्ट लैब	129.35
मेसर्स कोरल टेलिकॉम	100.04
मेसर्स विजीटेक	17.94
कुल	**1498.67**

12. पिछले वर्ष के आंकड़ों को इस वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलनीय बनाने के लिए उन्हें एकजुट एवं पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

-ह-
(डा. बिन्दु डे)
सचिव
प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड

-ह-
(प्रो. आशुतोष शर्मा)
अध्यक्ष
प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड

वर्ष 2016–17 के लिए पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट

वर्ष 2016–17 के लिए प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड के लेखा पर भारत के लेखा नियंता एवं महालेखापरीक्षक की पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2017 को प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (टीडीबी), नई दिल्ली के संलग्न तुलन पत्र, उसी तिथि को समाप्त आय एवं व्यय लेखा और प्राप्ति एवं भुगतान लेखा की प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड अधिनियम, 1995 (1995 की सं. 44) के अनुच्छेद 13(2) के साथ पठित लेखा नियंता एवं महालेखापरीक्षक (दायित्व, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें), अधिनियम 1971 के 19(2) के अन्तर्गत लेखा परीक्षा की है। ये वित्तीय विवरण बोर्ड के प्रबंधन का दायित्व है। हमारा दायित्व, अपनी लेखा परीक्षा पर आधारित इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय देना है।

2. इस पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में भारत के लेखा नियंता एवं महालेखापरीक्षक की वर्गीकरण, उत्तम लेखा नीतियों के सदृश लेखा मानक, प्रकटीकरण मानदंड इत्यादि से संबंधित लेखा प्रतिपादनों पर टिप्पणी शामिल है। वित्तीय लेनदेनों पर विधि अनुपालन सहित लेखा परीक्षा टिप्पणीयां, नियम एवं विनियम (प्रोपराइटी और रेग्यूलेटरी) और दक्षता–सह निष्पादन पहलू इत्यादि यदि कोई है तो इसे निरीक्षक रिपोर्ट/नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा के माध्यम से रिपोर्ट किया गया।

3. हमने यह लेखा परीक्षा, भारत में सामान्यतः अपनाए गए मानकों के अनुसार किया है। इन मानकों में यह अपेक्षित होता है कि हम लेखा परीक्षा को इस तरह योजनागत और निष्पादित करें कि इस बात का उचित आश्वासन प्राप्त किया जा सके के वित्तीय विवरण सामग्री, गलत विवरणों से मुक्त हो। लेखा परीक्षा में जांच के आधार पर वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत की गई राशियों के समर्थन में प्रमाणों और प्रकटीकरण की जांच शामिल है। लेखा परीक्षा में प्रयोग किए गए लेखा सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा महत्वपूर्ण आकलनों का मूल्यांकन शामिल है। हमारा विश्वास है कि हमारा लेखा परीक्षा विचारों को एक औचित्यपूर्ण आधार प्रदान करेगा।

4. हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर हम यह रिपोर्ट देते हैं कि:

(i) हमने सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो कि हमारी जानकारी और विश्वास में लेखा परीक्षा के उद्देश्य के लिए अनिवार्य है।

(ii) इस रिपोर्ट में दिए गए तुलन पत्र और आय एवं व्यय लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखा को वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत प्रारूप में तैयार किया गया है।

(iii) हमारे विचार से अपेक्षित लेखों की समुचित बहियों और अन्य संबंधित रिकॉर्डों को टीडीबी, नई दिल्ली द्वारा अनुरक्षित किया गया है जैसा कि हमारी ऐसी बहियों की जांच से पता चलता है।

(A) तुलन पत्र

मौजूदा परिसम्पत्तियॉं, ऋण, अग्रिम इत्यादि – अनुसूची 11

(i) टीडीबी ने वर्तमान परिसम्पत्तियों, इन्वेन्टरीज–स्टोर्स और स्पेयर का बैलेंश शून्य दिखाया है जबकि वर्ष 2016–17 के उपभोज्य रजिस्टर के जांच के पता चलता है कि 31 मार्च, 2017 को स्टॉक रजिस्टर में 0.43 लाख रू. का माल मौजूद था। इसके परिणामस्वरूप, मौजूदा परिसम्पत्यिों के महत्व को 0.43 लाख रू. घटाकर और व्यय को 0.43 लाख रू. बढ़ाकर दिखाया गया है।

(ii) टीडीबी ने टेलीफोन और संचार शुल्क पर 24.65 लाख रू. का व्यय दिखाया है। इसमें 1.04.2017 से 31.03.2018 के अवधि के लिए इंटरनेट कनेक्शन के लिए अगिम भुगतान के रूप में 9.32 लाख रू. शामिल थे जिसको कि वर्तमान भुगतानों के तहत अग्रिम भुगतान के रूप में दिखाये जाने की आवश्यकता थी। इसके परिणामस्वरूप, मौजूदा परिसम्पत्तियों के महत्व को 9. 32 लाख रू. घटाकर और व्यय को 9.32 लाख रू. बढ़ाकर दिखाया गया है।

(B) आय एवं व्यय खाते

1. व्यय

(a) अन्य प्रशासनिक खर्चे इत्यादि – अनुसूची 21

(i) 2016–17 में टेलीफोन भुगतान के कारण 0.22 लाख रू. के अवैतनिक व्यय को न तो 'बकाया खर्च' के रूप में लिख गया था और न ही अनुसूची–7 "वर्तमान देयताएं और प्रावधान" में देनदारियों में दिखाया गया था। इसके परिणामस्वरूप खर्च एवं देयताओं को 0.22 लाख रू. से कम करके दिखाया गया।

(ii) परिसम्पत्ति प्रबंधकों को वर्ष 2015–16 के लिए किया गया 23.61 लाख रू. के व्यय को गलती से मौजूदा वर्ष के व्यय के रूप में दिखाया गया जिससे व्यय बढ़ गया और पूर्व अवधि का व्यय 23.61 लाख रू. से कम हो गया।

(iii) टीडीबी ने वर्ष 2015–16 के लिए टेलीफोन शुल्क के रूप में किए गए 0.32 लाख रू. के भुगतान को वर्तमान वर्ष के खर्च के तहत दिखाया है। जिससे व्यय बढ़ गया और पूर्व अवधि का व्यय 0.32 लाख रू. से कम हो गया।

(iv) टीडीबी ने वर्ष 2015–16 के लिए कानूनी शुल्क के रूप में किए गए 16.33 लाख रू. के भुगतान को वर्तमान वर्ष के खर्च के तहत दिखाया है। जिससे व्यय बढ़ गया और पूर्व अवधि का व्यय 16.33 लाख रू. से कम हो गया।

(b) स्थापना व्यय इत्यादि – अनुसूची 20

पिछले वर्ष के सम्बन्धित 14.97 लाख रू. के स्थापना व्यय को वर्तमान वर्ष के व्यय में शामिल किया गया था। इसी प्रकार, मार्च, 2017 का वेतन जिसका भुगतान अप्रैल, 2017 में किया के रूप में बकाया 17.27 लाख रू. को नहीं दिखाया गया। जिससे कारण, 17.27 लाख रू. तक के देयताओं को कम करके दिखाने के अलावे, व्यय और और पूर्व अवधि का व्यय क्रमश: 2.31 लाख रू. एवं 14.97 लाख रू. से कम हो गया।

(ग) अनुदान सहायता

टीडीबी को आरएंडडी सेस लेवी के अन्तर्गत, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से अनुदान प्राप्त होता है जिसे प्रौद्योगिकी के आयात के लिए 5 प्रतिशत की भुगतान दर पर सरकार द्वारा वसूल किया जाता है। टीडीबी को वर्ष 2016–17 के दौरान डीएसटी से 3030.00 लाख रू. का अनुदान मिला।

नकद/बैंक शेष के 7676.89 लाख रू. के प्रारंभिक शेष के अलावे टीडीबी को वर्ष 2016–17 के दौरान कम अवधि जमा/ऋणों/ राजस्व/अनुदान, ऋण की अदायगी, उद्यम निधि से आय, लाभांश, जमानत इत्यादि पर ब्याज के रूप में 7901.49 लाख रू. प्राप्त हुए। 11952.93 लाख रू. के निवेश, स्थापना/कार्यालय खर्च में निवेश और ऋण/अनुदान के वितरण के बाद, 3625.459 लाख रू. को 31 मार्च 2017 तक अव्यतित शेष के रूप में दिखाया गया।

(C) सामान्य

1. निवेश – अन्य

(i) (अनुसूची 10–22304.82 लाख रू.) और ईयरमार्क्ड / इन्डो मेंट निधियों से निवेश (अनुसूची 9–65.99 लाख रू.)

उपरोक्त में शेयर–इक्विटी/पसंद की भगीदारी में 28.47 करोड़ रू. एवं आईडीबीआई के उद्यम पूंजी निधि के माध्यम से ईयरमार्क्ड/इन्डोमेंट निधियों में 65.99 लाख रू. का व्यय शामिल है। टीडीबी ने शेयरों और ईयरमार्क्ड/इन्डोमेंट निधि में निवेश के लिए दो अलग नीतियों को अपनाया क्योंकि इक्विटी एवं ऋण के मूल्य का मूल्यांकन 65.99 लाख रू., निवेश के मोचन के मामलों में 26.26 लाख रू. मूल्य में कमी के बाद दिखाया गया। हालांकि, मूल्य में कमी की नीति सभी निवेशों के लिए नहीं अपनाया गया।

(ii) इक्विटी में निवेश का रूपान्तरण नहीं होना

तुलन–पत्र के अनुसूची–10 "निवेश' के अनुसार, 28.47 करोड़ रू. को 'शेयर–इक्विटी भागीदारी' के शीर्ष के रूप में दर्शाया गया जिसमें मार्च 2007 में लिए गए मेसर्स रेवा इलेक्ट्रिक कार कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड में 1,44.68 प्रति शेयर पर 156.18 लाख रू. के 107798 इक्विटी शेयरों में निवेश शामिल है। चूंकि इस कम्पनी को महिन्द्रा ग्रुप ने मई 2010 में अधिग्रहित करके इसे मेसर्स महिन्द्रा रेवा इलेक्ट्रिक विहाइकल्स लिमिटेड नामक एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी में तब्दील कर दिया इसलिए टीडीबी के शेयरों को इस नयी गठित/परिवर्तित पब्लिक लिमिटेड कम्पनी के इक्विटी शेयरों में बदले जाने की जरूरत थी।

सितंबर, 2017 में अपनी बोर्ड की 59वीं बैठक में टीडीबी ने कुछ और समय इंतजार करने का फैसला किया क्योंकि मैसर्स महिन्द्रा एंड महिन्द्रा लिमिटेड ने रेवा के इक्विटी शेयरों को 25.90 रू. प्रति शेयर की कीमत पर खरीदने की पेशकश की, जो कि बहुत कम था।

(iii) विभिन्न कम्पनियों के संदेहास्पद ऋण का प्रावधान नहीं किया जाना

वार्षिक लेखों के अनुसार, 100 कम्पनियों में 427.86 करोड़ रू. बकाया था। इनमें से 61 कम्पनियों ने 233.59 लाख रू. के बकाये साथ टीडीबी को उनके ऋण अदायगी में चूक की।

इसके अलावे, 329.81 करोड रू. को लेखा में 31 मार्च 2017 तक अर्जित ब्याज के रूप में दिखाया गया था जिसमें इन कम्पनियों से वसूली के लिए अतिदेय की 313.66 करोड़ रू. की राशि भी शामिल है।

उपरोक्त से यह पता चलता है कि इन अतिदेय और अप्राप्य परिसम्पत्तियों ने मौजूदा परिसम्पत्तियों के अन्दर टीडीबी के ऋण पोर्टफोलियो का बढ़ाया। टीडीबी ने अब छः कम्पनीयों के लिए 14.99 करोड़ रू. के ब्याज को प्रोविजन किया।

कम्पनियों की चुकौती वाली देयताओं का विश्लेशन करते हुए यह पता चला कि वर्श 1998–99 के बाद लगभग हर कम्पनी/फर्म ने अपनी ऋण एवं ब्याज के भुगतान में चूक की। 100 कम्पनीयों में से 61 कम्पनीयों ने ब्याज की चुकौती में चूक की।

उपरोक्त से यह पता चलता है कि इन अतिदेय और अप्राप्य परिसम्पत्तियों ने मौजूदा परिसम्पत्तियों के अन्दर टीडीबी के ऋण पोर्टफोलियो का बढ़ाया इन संदेहास्पद एवं अप्राप्य ऋण और उसपर अर्जित ब्याज की एक बड़ी राशि को वार्शिक लेखा में दिखाने के लिए एक अनुकूल प्रावधान किया जाना चाहिए। उपरोक्त को देखते हुए, हम बकाया ऋण एवं अग्रिम की सत्यता को सत्यापित नहीं कर सकते।

(D) प्रबंधन पत्रः कोई नही

(I) पूर्ववर्ती पैराग्राफों में दिये गये हमारे प्रेक्षणों के आधार पर हम रिपोर्ट देते हैं कि तुलनपत्र और आय एवं व्यय लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखा, इस रिपोर्ट में लेखा बहियों के साथ मेल खाता है।

(ii) हमारी राय एवं हमारी सूचना तथा हमे दिये स्पष्टीकरणों के आधार पर क्योंकि पूर्व पैराओं में विचारित प्रेक्षणों के प्रभावों के कारण, हम लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक में उल्लेखित लेखा नीतियां एवं लेखाओं पर टिप्पणियों एव अन्य मामले, भारत में सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के साथ समरुपता में सत्य एवं सही दृष्टि देते हैं।

a. यह 31 मार्च, 2017 तक के प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड के तुलनपत्र एवं अन्य मामलों से सम्बंधित है।
b. अब तक यह इसी तारीख को समाप्त वर्ष हेतू आय और व्यय के अधिशेष से सम्बंधित है।

भारत सरकार के सी ए जी के लिए और उनकी ओर से

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः

–ह.–
मुख्य लेखा परीक्षा निदेशक
वैज्ञानिक विभाग

लेखा परीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक – 1

आन्तरिक नियंत्राण प्रणाली

1. आन्तरिक लेखा प्रणाली की पर्याप्तता :

बोर्ड की आंतरिक लेखापरीक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रिंसिपल पेय एंड लेखा कार्यालय के आंतरिक लेखा परीक्षा शाखा द्वारा किया जाना था जो कि मार्च, 2016 तक पूरा हुआ। कुल 17 पैरा (दो 2008–10 से 2011–13 से और 15 2013 की अवधि से सम्बन्धित हैं) आज तक बकाया है (सितम्बर, 2017)

2. आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता :

लेखापरीक्षा में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली से सम्बन्धि निम्नलिखित कमियां पायी गईः–

(i) पूंजीगत आस्तियों के निर्माण के लिए अनुदान से बनाये गए सम्पत्तियों का रखरखाव नही किया जाना

पूंजीगत सम्पत्ति के निर्माण के लिए अनुदान सहायता से बनाई गई सम्पत्ति परियोजना पूरा होने पर बोर्ड को लौटाई जानी थी जबतक की अनुदान सहायता प्राप्त संस्था द्वारा उसको अपने पास रखने की स्वीकृति बोर्ड से न प्राप्त कर ली गई हो। अनुदान प्राप्त संस्थानों द्वारा ऐसी अप्रचलित और अनुपयुक्त हो चुकी सम्पत्तियों के निपटान के लिए भी बोर्ड की पुर्व अनुमति लेने की आवश्यकता होती है। हालांकि, बोर्ड ने विभिन्न अनुदानप्राप्त संस्थानों के लिए पूंजिगत संपत्ति के निर्माण कि लिए प्रदान की गई अनुदानों से बनाई गई सम्पत्तियों का कोई रिकॉर्ड नही रखा गया।

(ii) बोर्ड द्वारा जारी अनुदानों के रजिस्टर का रखरखाव नही करना

जीएफआर 2017 के नियम 234 के अनुसार, मंजूरी प्राधिकारी द्वारा जीएफआर–21 फॉर्म के तहत एक अनुदानों को एक रजिस्टर तैयार किया जाना चाहिए, हालांकि, 2011–12 से 2016–17 के दौरान बोर्ड द्वारा 2951.93 करोड़ रू. के जारी किए गए अनुदान सहायता जारी करने के बावजूद इसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा गया।

(iii) जीएफआर 2017 के फॉर्म 12–ए (नियम 238 के तहत) डीएसटी से बोर्ड द्वारा प्राप्त अनुदान सहायता के संबंध में वित्तीय वर्श 2016–17 के लिए तात्कालिक उपयोगिता प्रमाणपत्र डीएसटी को भेजे गये थे।

(iv) उपयोगिता प्रमाणपत्र का अनुविक्षण

जीएफआर 2017 के नियम 238 में प्रावधान है कि अनुदान के वास्तविक उपयोग का प्रमाणपत्र, जिस उद्देश्य के लिए इसे जीएफआर 12–ए के तहत स्वीकृत किया गया है, का अनुदान प्राप्त करने वाले संस्थान के द्वारा वित्तीय वर्श के समापन के 12 महीनों के अंदर जमा करवाने पर जोर दिया जाना चाहिए। हालांकि, यूसी की कमजोर निगरानी के कारण, वर्श 2014–15 में जारी 5.78 करोड़ रू. के जारी अनुदान से सम्बन्धित 17 यूसी की प्राप्ति मार्च, 2017 तक लंबित थी।

(v) बैंक सामंजस्य स्टेटमेंट

टीडीबी ने मार्च, 2017 के महीने का बैंक सामंजस्य स्टेटमेंट प्रस्तुत किया, जिससे पता चला कि मार्च, 2017 से पहले 2500 रू. का केवल एक चेक बकाया था और मार्च, 2017 की अवधि के 13133 रू. के दो चेक अगस्त, 2017 तक लंबित थे जिनका समय समाप्त हो चुका है।

3- संपत्ति/इन्वेटरीज के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

वर्ष 2016–17 के लिए परिसम्पत्तियों, उपभोज्य वस्तुओं और सामग्रियों का भौतिक सत्यापन पूरा हो चुका है और कोई गलती नही पाई गई।

4- सांविधिक देय राशि के भुगतान में नियमितता

सभी सांविधिक देय का भुगतान समय पर किया जा चुका है।

–ह.–

उप–निदेशक (निरीक्षण)

ANNUAL REPORT
2016-17

Composition of the Technology Development Board

(As on 31st March, 2017)

1.	**Prof. Ashutosh Sharma** Secretary, Department of Science & Technology	Ex-officio Chairman
2.	**Dr. Girish Sahni** Secretary, Department of Scientific & Industrial Research	Ex-officio Member
3.	**Dr. S. Christopher** Secretary, Department of Defence Research & Development	Ex-officio Member
4.	**Shri Ashok Lavasa** Secretary, Department of Expenditure	Ex-officio Member
5.	**Shri Ramesh Abhishek** Secretary, Department of Industrial Policy and Promotion	Ex-officio Member
6.	**Shri Amarjeet Sinha** Secretary, Department of Rural Development	Ex-officio Member
7.	**Shri S. P. Shukla** Chairman, Mahindra Aerospace,Mumbai	Member
8	**Dr. Ajay Ranka** MD, Zydex Industries, Vadodara	Member
9.	**Shri G. Sreeramakrishna** Ex-CGM, SBI, Secunderabad	Member
10.	**Shri Pradeep Goyal** Chairman, Pradeep Metals Ltd., Navi Mumbai	Member
11.	**Dr. Bindu Dey** Secretary, Technology Development Board	Ex-officio Member (Member Secretary)

Photographs of the Board Members
(As on 31st March, 2017)

Prof. Ashutosh Sharma
Chairman & Secretary, DST

Dr. Girish Sahni

Dr. S. Christopher

Shri Ashok Lavasa

Shri Ramesh Abhishek

Shri Amarjeet Sinha

Shri S.P. Shukla

Dr. Ajay Ranka

Shri G. Sreeramakrishna

Shri Pradeep Goyal

Dr. Bindu Dey

Shri Ashok Lavasa has taken charge as Secretary, Department of Expenditure w.e.f. 2nd May, 2016 in place of Shri Ratan P. Watal; Shri Amarjeet Sinha has taken charge as Secretary, Department of Rural Development w.e.f. 1st August, 2016 in place of Shri J. S. Mathur.

TDB-YEAR AT A GLANCE

The year 2016-17 has been very productive for TDB as 14 agreements were concluded for financial assistance to various industrial concerns. Through these agreements, TDB committed Rs. 275.77 crore out of total project outlay of Rs. 958.37 crore covering various sectors such as Defence, Medical Devices, Healthcare, Engineering and Information Technology etc.

Applications Received in 2016-17

TDB received 71 applications during 2016-17 for financial assistance from various industrial concerns with total project cost of Rs. 2788.20 crore and TDB's assistance of Rs. 1128.31 crore. Out of that, about 50 applications were found suitable for further processing for financial assistance by TDB. While 14 applications cultivated into agreement signing, others are under different stages of processing.

The state-wise distribution of 71 applications is as under:

(Rs. in Crore)

S.No.	State / Union Territory	Number of Applications	Estimated Total cost	Assistance sought from TDB
1	Andhra Pradesh	11	696.39	201.88
2	Karnataka	19	340.44	157.01
3	Haryana	4	32.75	15.26
4	Madhya Pradesh	1	39.80	19.90
5	Kerala	1	3.92	1.00
6	Maharashtra	7	782.79	377.64
7	Tamilnadu	6	106.51	46.97
8	Telangana	1	11.49	3.00
9	Punjab	2	50.37	8.82
10	Gujarat	5	497.96	161.71
11	Uttar Pradesh	3	22.60	11.12
12	Goa	1	0.00	0.00
13	West Bengal	1	7.06	4.00
14	Delhi	7	194.82	118.5
15	Jharkhand	1	1.30	0.50
16	Others	1	0.00	1.00
	Total	**71**	**2788.20**	**1128.31**

Southern states of Karnataka and Andhra Pradesh continue to dominate in seeking financial support from TDB.

The sector-wise details of receipt of applications are given in the table below:

(Rs. in Crore)

S.No.	Sector	Number of Applications	Estimated Total cost	Assistance sought from TDB
1	Agriculture	15	537.67	310.52
2	Textile	1	5.25	2.09
3	Engineering	5	289.74	123.17
4	Defence	1	385.00	109.00
5	Healthcare & Medical	28	1269.20	479.72
6	Information Technology	2	11.6	6.00
7	Telecommunication	7	100.92	56.84
8	Electronics	1	9.60	4.00
9	Chemical	4	40.42	16.51
10	Nano Science	3	12.76	2.61
11	Energy & Waste Utilization	1	33.19	15
12	Others	3	92.85	2.85
	Total	**71**	**2788.20**	**1128.31**

Applications were received from private limited and public limited companies as given below:

(Rs. in Crore)

Category	Number of Applications	Estimated Total Cost	Assistance Sought from TDB
Private Limited Company	44	1450.22	558.32
Public Limited Company	17	1280.37	532.68
Others	10	57.61	37.31
Total	**71**	**2788.20**	**1128.31**

New Products and Services

During the year, TDB signed 14 new agreements for financial assistance to support the following project for development & commercialization of innovative technologies :

(I) Indigenized development and commercialization of key components such as Motor, Charger, Controller, DC-DC Converter for Electric Vehicles by M/s Ampere Vehicles Pvt. Ltd, Coimbatore;

(ii) Commercialization and Setting up of Manufacturing Line for Indigenous Medical LINAC by M/s Panacea Medical Technologies Pvt. Ltd., Bangalore;

(iii) Commercialization of Fiber Laser Systems by M/s Sahajanand Laser Technology Ltd., Gandhinagar;

(iv) Specialized Digital Audio Hardware Solution for Residential and Professional Audio Segments by M/s Sonodyne Technologies Pvt. Ltd., Kolkata;

(v) Manufacturing Facility for Pneumococcal Conjugate Vaccine by M/s Biological E Ltd., Hyderabad;

(vi) Development and Commercialization of Foot-and-Mouth Disease (FMD) Vaccine for Veterinary Use by M/s Sanvita Biotechnologies Pvt. Ltd. Hyderabad;

(vii) Setting up of Defence Manufacturing Facility at 50 acres Land at Vemagal Industrial Area, Kolar District, Karnataka by M/s Tata Power Company Limited, Strategic Engineering Division (Tata Power- SED), Bangalore;

(viii) Development and commercialization of Rule Buddy products (erstwhile "Arcita") by M/s Softest Engineers Pvt. Ltd., Pune;

(ix) Commercialization of High speed serial link products by M/s Terminus Circuits Pvt. Ltd., Bangalore;

(x) Development of an affordable connected Hemodialysis Machine for Rural Public Health Centers by M/s Renalyx Health Systems Pvt. Ltd., Bangalore;

(xi) Changing Energy Habits by M/s Energos Technologies Pvt. Ltd., Mumbai;

(xii) Development and Commercialization of Portable X-ray machine by M/s Iatome Electric India Pvt. Ltd., Coimbatore;

(xiii) Manufacture and Commercialization of Novel, Innovative, point of care, diagnostic tests for monitoring of Diabetes by M/s DiabetOmics Medical Pvt. Ltd., Hyderabad;

(xiv) Design, Development & Manufacturing of Industrial Robots by M/s Systemantics India Pvt. Ltd., Bangalore.

Disbursements

TDB disbursed an amount of Rs. 110.68 crore towards on-going & new projects and other schemes in FY 2016-17. This included Rs. 99.80 crore as loan; Rs. 0.47 crore as Equity; Rs. 5.80 crore as Grant and Rs. 4.61 crore to VCF for investment.

Projects Completed

None of the TDB supported companies declared their project completed during the FY 2016-17.

Settlement of Repayment of Loan

During the year, following companies financed by TDB repaid their loan and settled loan account as per the agreement:

- M/s Rotofilt Engineers Ltd., Ahmedabad
- M/s Samics Research Materials Pvt. Ltd., Bareilly (UP)
- M/s Sahajanand Laser Technology Ltd., Gandhinagar, Gujarat
- M/s Uurmi Systems Pvt. Ltd., Hyderabad
- M/s Veryx Technologies Pvt. Ltd., Chennai
- M/s Zen Technologies Ltd., Hyderabad
- M/s Ravindranath GE Medical Associates Pvt. Ltd., Hyderabad
- M/s Angels Health Pvt. Ltd., Navi Mumbai
- M/s Sanzyme Ltd., Hyderabad
- M/s SoftTech Engineers Pvt. Ltd., Pune

Technology Day

The Technology Day 2016 was celebrated on 11th May 2016 at Vigyan Bhawan, New Delhi with the theme "Technology Enablers for Start-up India". Hon'ble President of India, Shri Pranab Mukherjee, was the Chief Guest and Dr. Harsh Vardhan, Hon'ble Union Minister of Science & Technology and Earth Sciences presided over the Function.

On this occasion, the National Award for indigenous development and commercialization was given to M/s RESIL Chemicals Pvt. Ltd., Bangalore; alongwith their technology developers SMITA Research Lab of Indian Institute of Technology, Delhi (IITD) and International Advanced Research Centre for Power Metallurgy & New Materials (ARCI), Hyderabad for the product N9 Pure Silver.

The SSI Unit Awards were also presented to:

1. M/s Iatome Electric India Pvt. Ltd., Coimbatore for their cost-effective hand-held battery operated portable X-ray machine
2. M/s Tejas Networks Ltd., Bangalore for commercialization of TJ1400 – Packet Transport Node: a family of innovative, high-capacity, fiber optic networking products.

Product Release- Dr. Harshvardhan, Hon'ble Minister of Science & Technology & Earth Science commercially launched the product namely "Seaweed Aquasap" developed by M/s AquAgri Processing Private Limited, Delhi during Technology Day-2016. However, the project was completed in year 2015-16

TDB supported companies showcased their achievements through an exhibition.

Foundation Day

TDB celebrated its 20th Foundation Day on 1st September 2016. On this occasion, a 2-day Symposium was organized with the theme "Strategizing Commercialization through Technology & Innovation" on 1st – 2nd September, 2016. Sessions were held on: i) Intricacies of Indigenization in Defence Sector, ii) Cyber Security (IT): Imminent Risks & Potential Solutions, iii) Robotics & Electronics: Integrating into Daily Lives, iv) Nanoscience and Nanotechnology: Journey from Past to Recent, v) Clean and Green Energy: Are we serious about issues, vi) Industrial Vibrancy in Health Sector. The concluding session of the symposium was on Technology Policy Alignment. For all the sessions, invited speakers were chosen from Academia and Industries. Besides the lectures, there were panel discussions with panelists from Industries, DRDO, R&D Institutions, NITI Aayog and representation from FICCI, CII, etc.

Pro-active approach

Issuance of "Call for Proposals" - TDB issued "Call for Proposal' in the following key areas:

1 **BioMedical devices and Instrumentation**- TDB published the Call for Proposals for Medical Instrumentation/Devices including Imaging Equipment for the indigenous design and manufacturing of biomedical devices and instruments including imaging equipment (such as CT scanners, MRI machines etc.).

2 **Wireless Communication Technology**- TDB published the Call for Proposals for Innovation & Advances in Wireless Technology for Improving Cellphone Connectivity to engage key players in the industry for the indigenous development and commercialization of a wide range of technological solutions for improving wireless communication services.

3 **Innovative Technology for Farm Stubble** – TDB published the Call for Proposals for Innovative Technological Solutions to Agro-waste Management and Prevention of Stubble burning to invite proposals from industrial concerns to come up with out of the box ideas to help eliminate the harmful practice of stubble burning and reducing environmental pollution.

4 **Nanoscience and Nanotechnology** – TDB published the Call for Proposals under the "Nano application and Technology Development Programme" of Nano Mission Phase-II for development and commercialization of new product, processes, designs and prototypes/devices for Nano application and Nano Technology development.

5 **Call for the National Awards-2017** – TDB announced awards under three categories: i) Industrial concern which has successfully developed & commercialized an indigenous technology; ii) MSME that has successfully commercialized a technology product based on indigenous technology; iii) National Technology Start-up Award for promising new technology with potential for commercialization.

Participation in Venture Capital Funds (VCFs) - TDB continued networking with technology focused VCF to support technologically-innovative viable ventures. Upto 31st March, 2017, TDB has invested in 11 VCFs, with committed investment of Rs. 285.00 crore out of which the return on investment in five VCFs has already started. The details of VC Managers, fund size and TDB's contribution are given below:

(Rs. in crore)

S. No.	Fund Name	Fund size	TDB Commitment
1)	UTI-India Venture Unit Scheme (ITVUS)	103.00	25.00
2)	The Biotechnology Venture Fund	100.00	30.00
3)	UTI-Ascent India Fund-II	300.00	75.00
4)	Ventureast TeNet Fund II	60.00	15.00
5)	SME Technology Venture Fund	250.00	15.00
6)	SME Tech Fund RVCF -II	150.00	15.00
7)	Indian Fund For Sustainable Energy	75.00	10.00
8)	India Opportunities Fund	1000.00	25.00
9)	SEAF India Agribusiness Fund	125.00	25.00
10)	Multi Sector Seed Capital Fund	100.00	25.00
11)	IvyCap Ventures Trust - Fund 1	200.00	25.00
TOTAL		**2463.00**	**285.00**

Seed Support Scheme for Start-ups in Incubators - During the year 2016-17, the TBIs and STEPs funded by TDB were reviewed on 12th & 13th May, 2016. All the TBIs and STEPs were invited to make presentation before the Review Committee. The Committee observed that a strong system of evaluation, mentoring and monitoring of Start-ups has been established as a result of the seed support system and TBIs could build a vibrant eco-system for start-ups ensuring their sustainability.

MoU with Foreign Institution - TDB announced "Call for Proposal" under its TDB-Bpifrance collaboration that was renewed on 10th May, 2016 with CEFIPRA as the Management Body aiming to fund proposals in Aeronautics, Automotive & Biotechnology. The "Call for proposal" has received four proposals on : one in Automotive; two in Aeronautics and one in Health Biotechnology.

MoU with WWF-India for Climate Solver Partner – During the year 2016-17, TDB extended the validity of agreement with WWF-India upto 21.05.2019. Climate Solver is part of WWF's global initiative to strengthen the development and widespread use of innovative low carbon technologies. Climate Solver aims to showcase their potential, expand their outreach and generate awareness along with the overall value of innovation, as an immediate and practical solution to climate change.

INVENT Program – The Innovative Ventures and Technologies for Development (INVENT) Programme showed progress in the FY 2016-17. The program is designed to create a platform to support inclusive innovation solutions, both technological and process oriented, that have a positive social and economic impact on people in the lower income segments.

M/s Villgro Innovations Foundation (VIF) acting as the lead incubator supported four incubators. The 1st Bi-annual Review Meeting for the INVENT Programme was held on 27th & 28th March, 2017 at the Startup Oasis, Jaipur. The four incubators and ten incubatees were present along with INVENT team and representatives from TDB & DFID. Presentations were made by the incubators and incubatees on the progress of each. A full day training program for the INVENT incubators was also planned by Villgro on 28th March at Startup Oasis, Jaipur.

Global Innovation & Technology Alliance (GITA) – GITA signed many agreements during the year, the most important of which was with the DRDO to carry out activities under Technology Development Fund (TDF) Scheme.

Millennium Alliance (MA) – The MA concluded its first three rounds of selection process during FY 2016-17 and selected about 60 projects of social importance for support under the programme.

Exhibitions/ Seminars - To create awareness in the industry, entrepreneurs and R&D institutions about the available financial support from TDB, various activities were undertaken such as interactive meetings / participation in exhibitions in collaboration with other organizations.

OVERVIEW

Introduction

The Government of India constituted the Technology Development Board (TDB) in September 1996 as per the provisions of the Technology Development Board Act, 1995 with an aim to promote development and commercialization of indigenous technology and adaptation of imported technology for wider domestic applications.

The Act enabled the creation of a Fund for Technology Development and Application to be administered by TDB. The Fund receives grants from the Government of India out of the R&D Cess collected by the Government from the industrial concerns under the provisions of the Research and Development Cess Act, 1986, as amended in 1995. The Act also enables TDB to build up the Fund by crediting all sums received by TDB from any other source, recoveries made of the amounts granted from the Fund, and any income from investment of the amount of the Fund. The Finance Act, 1999, enabled full deductions to donations to the Fund for income tax purposes.

During the period of 1996-97 to 2016-17, the Government has collected Rs. 7974.32 crore as R&D cess. Out of this, TDB received a cumulative sum of Rs. 609.42 crore over the period of 20 years as Grant-in-aid from non-plan route of the Department of Science & Technology, Government of India.

The mandate of the TDB is to provide financial assistance to the industrial concerns and other agencies attempting development and commercial application of indigenous technology or adapting imported technology for wider domestic application.

Modes of Financial Assistance

TDB accepts applications for financial assistance from all sectors of economy throughout the year. The financial assistance from TDB is available in the form of loan or equity and/or in exceptional cases, grant.

The loan assistance is up to 50 percent of the approved project cost and carries 5% simple interest per annum. Royalty is also payable on sales of products under TDB's project during concurrency of the loan. TDB does not collect administrative, processing or commitment charges from the applicants. The loan amount is provided in instalments linked to implementation of associated milestones in accordance with the terms and conditions of the loan agreement. In some cases, TDB may have nominee director(s) on the Board of Directors of the assisted industrial concern. The implementation period of a project should generally not exceed three years. The loan and interest is secured through collaterals and guarantees. Normally, the repayment of the loan and payment of interest commences after the project is completed and a moratorium period not exceeding one year. The loan amount is generally recoverable in nine, half yearly instalments thereafter. The accumulated interest up to the repayment of the first instalment is distributed over a period of three years.

TDB subscribes by way of equity capital in an industrial concern (incorporated under the Companies Act, 1956), on its commencement, start-up and/or growth stages according to the requirements as assessed by TDB and keeping in view the debt-equity ratio. The equity subscription is decided by the full Board of TDB. It is up to 25 percent of the approved project cost, provided such investment does not exceed the capital paid-up by the promoters. The industrial concern is to issue, at par, its share certificates to TDB equivalent to the amount subscribed by TDB. As per the pre-subscription conditions, the promoters should

have subscribed and fully paid up their portion of the share capital. The promoters shall pledge their shares to TDB of a value equal to the equity subscription by TDB. TDB has a right to have nominee director(s) on the Board of Directors of such companies. TDB, at its discretion, may divest its shareholdings in the company after three years of completion of the project or after five years from the date of subscription in accordance with the procedure prescribed in the TDB (equity capital) Regulations. However, the first option to buy back the shares is given to the promoters.

TDB does not consider substituting the existing loan or equity of the industrial concerns which have obtained such finances from other institutions.

TDB also provides financial assistance by way of grants to industrial concerns and R&D institutions engaged in developing indigenous technologies. The sanction of grants is decided by the full Board and provided in exceptional cases having importance towards fulfilling national interest.

Till 31st March 2017, TDB has signed 330 agreements since its inception in 1996 with a project cost of Rs. 7219.80 crore and TDB's commitment of Rs. 1771.61 crore. TDB has disbursed Rs. 1408.24 crore from the grants provided by the government and through internal accruals.

The following table indicates the modes of financial assistance provided by TDB till 31st March 2017:

(Rs. in Crore)

Instrument	Sanctioned by TDB	Disbursement by TDB
Loan	1304.54	983.44
Equity	33.06	34.66
Grant	149.01	143.73
Venture Funds	285.00	246.41
Total	**1771.61**	**1408.24**

Sector-wise Coverage of Agreements

TDB's financial assistance has covered almost all sectors of the economy. The following table gives sector-wise projects sanctioned by TDB upto 31st March, 2017, since inception in 1996-97.

(Rs. in Crore)

S.No.	Sector	Number of Aggrements	Total cost	TDB's Commitment
1	Health & Medical	84	1747.21	491.40
2	Engineering	66	664.40	239.23
3	Information Technology	42	374.07	146.01
4	Chemical	23	206.07	71.99
5	Agriculture	21	141.55	47.40
6	Tele-communications	12	99.88	37.85
7	Road Transport	10	527.04	81.20
8	Energy & Waste Utilization	8	132.36	55.98
9	Electronics	4	52.56	17.75
10	Air Transport	1	131.38	64.90
11	Defence and Civil Aviation	9	517.45	165.05
12	Others			
	a) Venture Funds	11	2463.00	285.00
	b) STEP-TBI	35	35.00	35.00
	c) CII	1	0.83	0.50
	d) Millennium Alliance	1	112.00	25.00
	e) Global Innovation & Technology Alliance	1	15.00	7.35
	f) INVENT Programme	1	-	-
	TOTAL	**330**	**7219.80**	**1771.61**

Healthcare and Engineering sectors have received a significant share in comparison to other sectors. The support by TDB is largely market-driven and technology oriented in all its new ventures and various industrial sectors.

State-wise Distribution of Agreements 1996-2017

The State-wise distribution (based on registered office of the company) of agreements signed during the years 1996-2017 is given below:

(Rs. in Crore)

Sl No.	State, Union Territory	Number of Agreements	Total cost	TDB Commitment
1	Andhra Pradesh	85	1673.57	539.44
2	Karnataka	41	920.58	322.84
3	Maharashtra	41	763.5	145.9
4	Tamil Nadu	36	309.24	95.78
5	Delhi	19	230.8	74.65
6	Gujarat	13	147.88	45.52
7	West Bengal	9	121.58	51.26
8	Uttar Pradesh	7	52.03	33.88
9	Madhya Pradesh	6	154.23	41.5
10	Haryana	6	44.15	18.00
11	Punjab	5	52.20	14.46
12	Chandigarh	4	43.75	16.5
13	Kerala	3	19.03	7.15
14	Himachal Pradesh	1	6.24	1.90
15	Jammu & Kashmir	1	5.65	2.38
16	Manipur	1	7.94	2.70
17	Pondicherry	1	5.83	1.90
18	Rajasthan	1	35.77	3.00
19	Others - Including			
	Venture Funds	11	2463.00	285.00
	STEP-TBIs	35	35.00	35.00
	CII	1	0.83	0.50
	Millennium Alliance	1	112.00	25.00
	Global Innovation & Technology Alliance	1	15.00	7.35
	INVENT Programme	1		
	Grand Total	**330**	**7219.80**	**1771.61**

As per its mandate, TDB support is given on pan-India basis. However, the above table reflects that maximum financial assistance has been availed by companies based in Southern States of India as they have been pro-active in submitting proposals to TDB.

Processing of Project Proposals

An industrial concern seeking financial assistance from TDB need to submit the application in a prescribed format. The format of application seeking financial assistance and other details are provided in 'Project Funding Guidelines' available on demand. The industrial concern or the entrepreneur/promoter can also download the same from the website of TDB i.e. www.tdb.gov.in and apply online @http://e-techcom.tdb.gov.in. TDB receives the applications throughout the year.

Initial Screening of Applications

An Initial Screening Committee (ISC) examines the applications received for financial assistance, from the point of view of completeness of the application, objective of the project, status of the technology etc. Such screening includes formal presentation by the applicant and technology provider in front of a duly constituted Technical-cum-Financial ISC. Additional information/details or a second presentation may also be required for assessment and clarity. If the application does not meet the criteria prescribed for TDB's financial assistance, the ISC may reject the application after providing written reasons for not recommending it for further processing.

Project Evaluation Committee (PEC)

Based on the recommendations of the ISC, the application is referred to a PEC for on-site visit and assessment on ground. For each project, the PEC is constituted keeping in view the nature of the project and the product. PEC consists of experts (scientific, technical and financial) in the relevant fields from outside TDB for an independent evaluation of the project.

The experts (serving or retired) may belong to government departments, R&D organizations, academic institutions, industry, industry associations, financial institutions and commercial banks. The applicant along with the technology provider is given full opportunity to give a detailed presentation on the scientific, technical, marketing, commercial and financial aspects and to provide in-depth information on various issues related to the project & the company.

High Level Expert Committee (HLEC)

In order to expedite the process of evaluation for pending/area specific proposals, Chairperson, TDB from time to time has constituted High Level Expert Committee/s consisting of eminent experts (scientific, technical, academia, marketing and financial) in the relevant fields from outside TDB under the Chairmanship of a renowned expert for independent evaluation of the projects.

Evaluation Criteria

The application is evaluated for its scientific, technological, commercial and financial merits. The evaluation criteria include:

- Uniqueness and innovative content of the proposal
- Soundness, scientific quality and technological merit
- Potential for wide application and the benefits expected to accrue from commercialization
- Adequacy of the proposed effort
- Capability of the R&D institution(s) in the proposed action network
- Organizational and commercial capability of the enterprise including its internal accruals
- Reasonableness of the proposed cost and financing pattern
- Measurable objectives, targets and milestones.
- Track record of the entrepreneur

Confidentiality and Transparency

TDB recognizes that it is important to maintain confidentiality, as each proposal is a commercial proposal involving a new product or process. In case the applicant mentions that some information provided in the project proposal has to be treated as strictly confidential, it is not circulated to the experts of the PEC or HLEC. The PEC or HLEC respects the sensibility of the applicant's apprehensions in disclosing certain vital information on the processes.

After a comprehensive discussion/deliberation with the applicant, the observations and recommendations are finalised by the experts constituting the PEC or HLEC.

Approval of Financial Assistance

All the project proposals recommended by the PEC go for a third party due diligence by an empaneled Asset Manager Company, if TDB's assistance exceeds Rs. 10.00 crore or total project cost is above Rs. 30.00 crore. The project recommended by HLEC for financial assistance is compulsorily assessed through a Due-diligence process by an independent third party i.e. Asset Managers empaneled by TDB. The recommendations of the PEC or HLEC, alongwith the due-diligence report (as applicable), are placed before the Board for approval.

If the project proposal is not recommended by PEC or HLEC, the application is closed by TDB under intimation to the applicant quoting the reasons.

Upon clearing the above levels of evaluation, Chairperson, TDB, approves proposals upto Rs. 2.50 crore; proposals between Rs. 2.50 crore to Rs. 10.00 crore are approved by the Sub-committee of the Board duly constituted by the Chairperson by the powers delegated by the Board; and project proposals beyond Rs. 10.00 crore are approved by the full Board.

Monitoring and Review

TDB releases the approved assistance to the beneficiaries in instalments, based on compliance of pre-defined milestones. The second and subsequent release of instalments depends on the recommendations of a Project Monitoring Committee (PMC) constituted for each approved project. The PMC again consists of scientific/technical and financial experts and invariably has a technical and a financial expert who was the member of PEC or HLEC at the time of on-site evaluation of the project.

Proactive Role

Besides responding to the applications received from industrial concerns and other agencies, TDB takes a pro-active role to ensure a comprehensive support for technology development and commercialization. Under the aegis of its mandate, TDB has encouraged development and commercialization of indigenous technologies through the following initiatives:

(a) Participation in Venture Capital Funds (VCFs)

TDB participated in technology-focused VCFs to support technologically innovative, financially viable ventures i.e. SMEs/early stage ventures having innovation and innovative products/services. TDB's participation in VCFs on the selective basis in high-risk, high-return technology-oriented projects is an excellent tool for increasing geographical and technological spread.

The Board in its 44th meeting in March 2010, decided to constitute a committee to consider and review the support to VCFs and suggesting methodology for this purpose. The Board finalized the broad guidelines for participation of TDB in VCFs in its 45th meeting on 10th May 2010.

Since then, TDB has participated in 11 VCFs, with reputed and well-experienced managers namely, APIDC-Biotechnology Fund; UTI-Ascent India Fund, UTI-India Technology Venture Unit Scheme; Vetureast Tenet Fund-II, GVFL-SME Technology Venture Fund; RVCF-SME Tech Fund RVCF-II; CIIE-Indian Fund For Sustainable Energy; SIDBI-India Opportunities Fund, SEAF India Agribusiness Fund; Blume Venture's Multi Sector Seed Capital Fund and Ivy Cap Ventures Trust Fund-1. These funds are targeted to support technology-oriented ventures in various sectors such as IT/ITES, Biotechnology, Health, Telecommunications, Nano-technology, Cleantech Energy and Agribusiness etc. with a view to leverage co-investment in innovative projects. The total committed investment of TDB is to the tune of Rs. 285.00 crore out of which the return on investment in five VCFs has already started.

TDB's motivation and participation has resulted in the venture capitalists contouring their assistance to TDB's mission. This initiative of TDB has given confidence to Private Equity Funds to come up in big way to support the technology-based projects with a pronounced emphasis on sectors which are the growth drivers of Indian economy. Further participation of TDB in VCFs is under review by the Board.

(b) Seed Support for Start-ups in Incubators

In 2005, TDB instituted the Seed Support Scheme to provide early stage /start-up financial assistance to young entrepreneurs with innovative technology venture ideas to incubate and bring their ideas under development to fruition and finally to reach the market place. The proposed assistance was positioned to act as a bridge between development & commercialization of the technologies. The scheme was started for providing financial assistance for Start-ups in Incubators / Technology Business Incubators (STEP/TBI) administered by the National Science & Technology Entrepreneurship Development Board (NSTEDB) of DST.

Till 31st March, 2017, TDB has supported 35 (which includes two times financial assistance to 4 TBIs/STEPs) TBIs and STEPs with a financial assistance of Rs. 1.00 crore each aggregating to Rs. 35.00 crore. These incubators have provided assistance to several incubates companies for their projects spread in the areas of Telecom, IT, Robotics, Agriculture, Instrumentation, Engineering, Environment, Pharma, Food, Solar, Textile and Biotechnology. The scheme progressed well and benefited a number of entrepreneurs in up-scaling and related work. It also facilitated in building up a corpus of incubation fund by the incubators.

In the 53rd Board meeting held in March 2016, it was decided that since NSTEDB of DST is also pursuing the Seed Support scheme in a big way, TDB should discontinue further funding in this scheme. However, the TBIs / STEPs that have already been funded by TDB may continue to invest in new incubatees through the incubation fund.

During the year 2016-17, the TBIs and STEPs funded by TDB were reviewed. The review meeting was held on 12th & 13th May 2016. All the TBIs and STEPs were invited to make presentations before the Review Committee. The Review Committee observed that a strong system of evaluation, mentoring and monitoring of Start-ups has been established at the TBIs and TBIs have been able to build a vibrant eco-system for start-ups ensuring their sustainability.

(c) MoU with Foreign Institution

TDB continues its technical collaboration with Bpifrance, France earstwhile, OSEO, France, as per renewed Memorandum of Understanding (MoU) between TDB and Bpifrance dated 10th May, 2016 signed at New Delhi along with CEFIPRA. The agreement entails to carry out activities related to the exchange of best practices and setting up of coordinated measures to foster technological exchanges in the field of Science, Technology and Innovation through collaboration between companies, organizations and institutions of France & India. The first phase of the MoU aims to fund proposals on Aeronautics, Automotive & Biotechnology areas.

(d) MoU with WWF-India for Climate Solver Partner

Considering India's strength in innovation wherein it has been ranked 12th on the Global CleanTech Innovation Index 2012, TDB decided to join the Climate Solver Platform launched by WWF-India.

The Climate Solver platform is a part of WWF's global initiative to strengthen the development and widespread use of innovative low carbon technologies thereby contributing towards reduced emissions and enhanced energy access. The platform provides an interface between low carbon technology innovators and industry associations, investors, government, incubation centers, and the media. After careful screening and selection of innovative clean technologies, developed by small and medium enterprises, Climate Solver aims to showcase their potential, expand their outreach and generate awareness about them along with the overall value of innovation, as an immediate and practical solution to climate change. Climate Solver was first launched by WWF Sweden in 2008 and so far 28 innovative technologies have been awarded. These technologies range from electric vehicles, green materials for buildings to energy storage systems, solar heating and cooling, etc.

In India, besides TDB, the Confederation of Indian Industry (CII), New Ventures India, Centre for Innovation Incubation & Entrepreneurship (IIM Ahmedabad) and Skyquest Technology Consulting Pvt. Ltd. are participating in this programme. TDB and WWF-India mutually extended the validity of agreement upto 21.05.2019.

(e) Collaborations

- **INVENT Program:**

TDB in partnership with Department for International Development (DFID), UK had initiated the Innovative Ventures and Technologies for Development (INVENT) Programme in the FY 2015-16. The program was designed to create a platform to support inclusive innovation solutions, both technological and process oriented, that have a positive social and economic impact on people in the lower income segments, also known as the Bottom of the Pyramid (BoP). The support includes, but not be limited to the provision of funding, intense mentoring, knowledge and access to capacity building programmes, support services, and relevant networks in the 8 Low Income States (LIS) of India (UP, MP, Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand, Rajasthan, Orissa and West Bengal).

The ultimate aim is:

- creating the viable social enterprises pipeline for impact investment in the above mentioned 8 LIS.
- Generate 50 investments ready for profit social enterprises in 8 Low Income States.
- Support 160 entrepreneurs in the 8 Low Income States.

The impact:

- An ecosystem will be in place to diversify of funding opportunities that are appropriate to scale social enterprises in 8 LIS.
- Increment in government support to break down the cultural barriers and encourage more people to get involved in social entrepreneurship.
- Established social incubator with strong recognition.

An Agreement was executed between TDB and M/s Villgro Innovations Foundation (VIF) in FY 2015-16 wherein Villgro was selected to act as the lead incubator to provide incubation support aimed at creating a viable social enterprise (for profit) pipeline for impact investments in the 8 low income states of India. Villgro is presently supporting four incubators viz. IIM Calcutta Innovation Park (IIMCIP), KIIT Technology Business Incubator at Bhubaneswar (KIIT TBI), SIDBI Innovation & Incubation Centre at IIT Kanpur (SIIC IITK) and Startup Oasis (an initiative of CIIE, IIM Ahmedabad and RIICO) in the LIS to hand-hold innovative businesses at seed or early stages of enterprise development that benefit the poor in the LIS of India while being commercially successful.

- **Global Innovation & Technology Alliance (GITA)**

In 2011, Global Innovation & Technology Alliance (GITA) was established as a "not–for–profit" Section-8 (Companies Act 2013) Public Private Partnership (PPP) company in a joint venture between CII and TDB with equity contribution of 51:49 respectively.

GITA is an innovative platform of Government of India and Indian industry / R&D Institutions to manage the funds assigned by governmental and non-governmental organizations for innovative technology solutions through: mapping technology gaps, evaluating technologies available across the globe and forging techno-strategic collaborative partnerships appropriate for Indian economy. GITA encourages industrial investments and connects industrial and institutional partners for effective matchmaking and collaborative industrial R&D projects, providing funding for technology development / acquisition / customization / deployment.

GITA assists DST in implementing industrial R&D programme with different countries under bilateral & multilateral Science & Technology Cooperation agreements. Under these country-specific programmes, an industry from India and an industry from another country can submit a joint R&D proposal for developing a marketable product. To facilitate this, both the governments provide financial support up to 50% of project cost to their respective industries. GITA has implemented, Indo-Israel, Indo-Canada, Indo-Spain, Indo-UK and Indo-Korea programmes of DST in this manner. Over the years, GITA has also been instrumental in implementing National R&D programmes with different government agencies such as Department of Heavy Industries, DIPP, MSME and recently of the DRDO.

- **Millennium Alliance (MA)**

The Millennium Alliance (MA) Program was launched in 2011 jointly by TDB, United States Agency for International Development (USAID) and Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI) to ensure that the benefits of innovation percolate to the BoP population. This alliance was forged as an innovation partnership for global development focusing on important sectors including health, basic education, water & sanitation, food security/agriculture and clean energy. Later, the platform was joined by UK's DFID, ICCO Cooperation, ICICI Foundation for Inclusive Growth, World Bank Group and Facebook. The MA is an inclusive platform to leverage Indian creativity, expertise, and resources to identify and scale innovative solutions being developed and tested in India to address development challenges that will benefit BoP populations across India and the world. The MA is a network to bring together various social innovators, philanthropy organizations, social venture capitalists, angel investors, donors, service providers and corporate foundations to stimulate and facilitate financial and other support to the innovators.

A USD 25 million fund was set up for a period of 5 years of which TDB contributed Rs. 25 crore (Rs. 5 Crore per year). Under the program, innovators are provided with seed funding, grants, incubation, networking opportunities, business support, knowledge exchange and technical assistance which facilitates further access to equity, debt, and other capital.

Contributing to social and economic development in over 20 Indian states and 7 developing countries, the program has so far supported 86 social enterprises with a funding support of over Rs. 60 crore and directly benefitted more than 6.8 million people. Over 27,000 people have been successfully trained by the project awardees. Additionally, innovators have also been able to leverage their association with the MA to raise external funds worth Rs. 451 million as well as develop over 90 partnerships for extensive and sustainable project implementation.

(f) Technology Day and Presentation of National Awards

Technology Day

Every year 'National Technology Day' is observed across India on May 11. This day glorifies the importance of science in day-to-day life and motivates students to adopt science as a career option.

National Technology Day is being commemorated to celebrate the anniversary of first of the five tests of Operation Shakti (Pokhran-II) nuclear test which was held on 11 May, 1998 in Pokhran, Rajasthan. Apart from Pokhran nuclear test, on this day first indigenous aircraft Hansa-3 was test flown at Bangalore and India also conducted successful test firing of the Trishul missile on the same day. Considering all these achievements 11 May was chosen to be commemorated as National Technology Day.

This day urged the industry to forge powerful partnerships with the national laboratories and to create knowledge networks with academic institutions to promote research and development and to gain entry into global markets.

National Award

To commemorate this day, Technology Development Board (TDB) has instituted a National Award. This award is conferred on to industries for their successful achievement in commercialization of Indigenous Technology. The award carries a cash prize of Rs. 10 lakh and a trophy. In case a technology has been developed and commercialized by separate entities, both are eligible to get the award separately. The National Award was given for the first time on the occasion of the Technology Day on 11th May, 1999.

The first National Award for successful commercialization of indigenously developed technology was given to M/s Shantha Biotechnics Private Limited, Hyderabad and its R&D unit in May, 1999 for commercial production of "recombinant DNA based Hepatitis - B vaccine" by the then Prime Minister of India, Shri Atal Bihari Vajpayee.

During 2016-17, TDB took a pro-active approach and announced awards under three categories to be implemented from FY 2017-18:

- One cash Award of Rs. 25.00 lakh and a trophy to an industrial concern which has successfully developed & commercialized an indigenous technology; in case the technology developer and commercializing organizations are different each one would be eligible for cash prize and trophy;

- Three cash award of Rs. 15.00 lakh and a trophy each to a MSME that has successfully commercialized a product based on indigenous technology;

TDB instituted a new Award i.e. National Technology Start-up Award of Rs. 15.00 lakh and a trophy for promising new technology with potential for commercialization.

Award for SSI unit

In August 2000, TDB introduced a cash award of Rs. 2 lakh and a trophy to a SSI unit that has successfully commercialized a technology-based product. The first SSI award was given on 11th May, 2001. The number and quantum of the award was increased to three and Rs. 5 lakh, respectively in the year 2011. In 2016, this award has been renamed as 'MSME Award' and the quantum has been increased to Rs. 15 lakh.

(g) Issuance of "Call for Proposals"

The Board takes a pro-active approach and from time to time issues "Call for Proposal' in different areas of importance in order to sensitize local industry towards the intent of TDB to support innovation-driven technology focused projects in various strategic areas as identified in "Make in India".

(h) Dispute Resolution Committee (DRC)

Since inception of TDB, about sixty cases have been declared stressed either due to technology failure or commercialization failure. Unlike banks and other financial institutions, TDB cannot resort to mechanisms like Debt Recovery Tribunals (DRTs); and has instead engaged asset managers, arbitrators and other legal recourses.

The Board, in several meetings, discussed the matter of bad debts and suggested suitable steps to be taken for recoveries. Section 4.42 of Manual of Standing Orders (MSO) of TDB of 2002 provided for provision of One Time Settlement (OTS) which stated:

"The Rules should provide for one-time settlement in exceptional cases, to be decided by TDB and there should be proper procedure drawn up by TDB for such a settlement keeping in view the procedures adopted by the financial institutions like IDBI. Any institution that has benefited from one-time settlement would be made ineligible for any assistance from TDB in future".

Owing to these NPAs/Stressed cases, pre-litigation and litigation cases, TDB with the approval of the Chairperson, initiated a mechanism for addressing by constituting a "Dispute Resolution Committee (DRC)" in late 2015. The objective of DRC is to reduce the expenditure on unnecessary litigation, particularly in cases where the company does not dispute its liability towards repayment of the loan and requesting TDB for settlement or re-scheduling the repayment schedule. This was a one-time measure to make an effort to liquidate the pendency and ensure maximum recovery of the loan and other charges on mutually agreed terms. The DRC nowhere interferes with the legal proceedings already initiated by TDB.

The recommendations of DRC are placed for approval before the Sub-Committee of the Board on OTS, duly constituted by the Board. Through this process, many cases have been settled and significant recovery made in a short span of time.

(I) Creation of Social Media Platforms

In order to create transparency in functioning and getting more connectivity and also considering the importance of social media platforms in present scenario, TDB felt the need of having its own Social Media platform and created its official page as following:

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/technology-development-board

Facebook: https://www.facebook.com/tdbgoi/

Twitter: https://twitter.com/tdbgoi

TDB has set-up a robust Project Management System (PMS) and new official website at NIC server with the domain name www.tdb.gov.in. The website is being developed in accordance with the Government of India Guidelines for Government Website (GIGW) to facilitate ease of getting information about TDB and its schemes by public at large.

Acknowledgement

TDB is grateful to all Board Members for their time, efforts, guidance and contributions.

-sd-
(Prof. Ashutosh Sharma)
Chairperson
Technology Development Board

Place: New Delhi

PROJECTS & PRODUCTS

M/s Ampere Vehicles Pvt. Ltd., Coimbatore

Agreement signed on 15th July 2016

Name of the Project

Indigenized development and commercialization of key components such as motor, chargers, controllers and DC-DC converters for Electric Two-Wheeler Vehicles

Sector

Road Transport

Objective of the Project

TDB signed a loan agreement with M/s Ampere Vehicles Pvt. Ltd., Coimbatore for a project titled "Indigenized development and commercialization of key components such as motor, chargers, controllers and DC-DC converters for Electric Two-Wheeler Vehicles".

The project envisages indigenized development and commercialization of the 4 key components for battery operated vehicles that include motor, chargers, controllers and DC-DC converters for electric vehicles. At present, these components are majorly imported. Importation has associated issues like high costs due to currency fluctuations, unpredictable quality, need to source components in higher volumes, thus creating inefficiencies in the supply chain. Further, imported products are not customized to Indian usage leading to component failures, which in turn leads to increase in the cost of the vehicle. Ampere Vehicles proposes to completely indigenize and manufacture these key components required for electric two-wheelers to achieve manufacturing competitiveness. The technology and manufacturing process has been developed by in-house research and development. Over the past four years, the company has gained expertise in creating prototypes of the four key components using local methods and processes.

Ampere Vehicles has been in the business of development, manufacturing and sale of electric 2- and 3- wheelers for the last 7 years. They have been importing these components from China. They felt the need to indigenize these components to suit Indian requirements and also to reduce dependency on imported parts and associated risks in business. This initiative of Ampere Vehicles is aligned to 'Make in India' policy of Govt. of India.

Total Project Cost

Rs. 6.91 crore

TDB's Assistance

Rs. 2.43 crore

M/s Panacea Medical Technologies Pvt. Ltd., Bangalore

Agreement signed on 6th October 2016

Name of the Project

Commercialization and Setting up of Manufacturing facility for Indigenous Medical LINAC

Sector

Healthcare

Objective of the Project

TDB signed a loan agreement with M/s Panacea Medical Technologies Pvt. Ltd., Bangalore for a project titled "Commercialization and Setting up of Manufacturing facility for Indigenous Medical LINAC".

Under this project, Panacea intends to commercialize indigenous 6MV Medical Linear Accelerator (LINAC) with advanced radiotherapy delivery techniques such as Intensity Modulated Radiation Therapy (IMRT), Image Guided Radiation Therapy (IGRT), Volumetric Modulated Arc Therapy (VMAT) and Stereotactic Body Radiation Therapy (SBRT). Panacea has acquired the technology from SAMEER & Deity. The company plans to set up the manufacturing line with an objective to provide such advanced treatment to the Indian population at an affordable cost and offer an alternate to high cost machines currently available. In addition, there is huge export potential for this product to various Asian, African and European countries. The total demand for these machines is estimated to be more than 4000 machines by 2020 according to IAEA. Panacea intends to compete against the three major global manufacturers of medical LINAC – Varian (USA), Elekta (Sweden) and Accuray (USA) by launching a full feature-loaded 6MV LINAC machine at a lower price.

Panacea Medical Technologies is a professional healthcare company, engaged in developing state of the art technology in radiotherapy & radiology thereby nurturing a culture of innovation and clinical solutions for diagnosis and therapy of cancer. It is one of the main radiotherapy equipment manufacturers in Asia and features among the 6 key players in the world.

Total Project Cost

Rs. 19.30 crore

TDB's Assistance

Rs. 7.40 crore

M/s Sahajanand Laser Technology Ltd., Gandhinagar

Agreement signed on 13th October 2016

Name of the Project
Commercialization of Fiber Laser Systems

Sector
Engineering

Objective of the Project
TDB signed a loan agreement with M/s Sahajanand Laser Technology Limited (SLTL), Gandhinagar for a project titled "Commercialization of Fiber Laser Systems".

The project entails in-house production of medium to high power 1 µm Continuous-Wave (CW) fiber laser sources at SLTL. The targeted power levels are from single-mode 500W to multimode multi-kW (up to 3kW), using high power fiber combiners and commercialization of these fiber lasers. The company has already developed part of the basic modules of 500W single-mode fiber lasers. Through this project, they aim to build capability and infrastructure for in-house production of fiber lasers at SLTL. This will narrow the gap in products and prices between foreign and domestic suppliers, and thus enable not only cost savings but also access to better and timely services to domestic customers, including government, defence labs and commercial organizations.

The fiber lasers developed under the project will replace the imported fiber lasers in the laser cutting and welding systems, which are already being marketed by SLTL in the country and abroad in these machines. Further, the stand-alone fiber lasers also can be marketed in the country as well as abroad.

SLTL Gandhinagar, Gujarat is specialized in designing, developing, manufacturing, marketing and servicing sophisticated laser systems. It also manufactures a number of Special Purpose Machineries (SPM), which are customized & made to order as per the specific requirement of each individual customer for specific industrial application. SLTL is global pioneer in manufacture of Fibre laser cutting machine with linear motor.

Total Project Cost
Rs. 24.53 crore

TDB's Assistance
Rs. 6.40 crore

M/s Sonodyne Technologies Pvt. Ltd., Kolkata

Agreement signed on 7th December 2016

Name of the Project

Specialised Digital Audio Hardware Solution for Residential and Professional Audio Segments

Sector

Engineering

Objective of the Projective

TDB signed a loan agreement with M/s Sonodyne Technologies Pvt. Ltd. (STPL), Kolkata for a project titled "Specialized Digital Audio Hardware Solution for Residential and Professional Audio Segments".

As part of the project, STPL shall integrate the specialized audio products into the digital ecosystem. This will involve design and manufacturing of new models with facility to integrate with LAN, USB, Bluetooth, Wi-fi and other such digital interfaces. Additionally, there will be production capacity enhancement and plant modernization. The products will be exported from Sonodyne's existing facility located in SEZ, Falta, Bengal, and will also be sold in India from a new facility that has been setup in Howrah, Bengal.

The aim is to utilize and upgrade inherent R&D and manufacturing processes to introduce world class digital products in the residential and professional arena and subsequently create products for export and also provide import substitution.

STPL having pioneered in the field of residential audio (amplifiers, speakers) and TVs in the '70s and '80s, now make specialized amplifiers, speakers and related power electronics back-up for Indian and Export markets. These products are used both in residential and professional spaces and Sonodyne exports these products to over 40 nations.

Total Project Cost

Rs. 16.24 crore

TDB's Assistance

Rs. 5.00 crore

M/s Biological E Ltd., Hyderabad

Agreement signed on 8th December 2016

Name of the Project

Setting up manufacturing facilities for Pneumococcal Conjugate Vaccine

Sector

Healthcare

Objective of the Project

TDB signed a loan agreement with M/s Biological E Ltd., Hyderabad, for a project titled "Setting up manufacturing facilities for Pneumococcal Conjugate Vaccine"

The proposed product is conjugate vaccine wherein polysaccharides from different etiologically important strains of Streptococcus pneumonia are chemically coupled to a carrier protein (CRM197) that is known to trigger protective immune response in the vaccinated subjects. Each dose of the vaccine consists of several different polysaccharides conjugated to a carrier protein (CRM197) in a liquid formulation. The vaccine is predominantly used for infants (below 5 years) and adults (above 60).

The vaccine composition is unique containing 14 serotypes of Streptococcus pneumoniae that have the highest propensity to cause respiratory disease in children. The company initially plans to produce around 25 million doses, which will be eventually scaled up to 100 million doses annually. With the facility in India this superior product, including more number of serotypes, can be provided to the masses at a reasonable price.

BEL promoted in 1953 is a closely held public limited company in the manufacture of vaccines (Pentavalent), Pharma Products (cough, cold, Gastrointestinal products, Nutraceuticals etc.), Critical Care (Polyvalent Snake Venom, Anti- Coagulants). The company has developed the product through an in-house research and has filed two patents for the vaccine composition and polysaccharide purification.

Total Project Cost

Rs. 320.39 crore

TDB's Assistance

Rs. 100.00 crore

M/s Sanvita Biotechnologies Pvt. Ltd., Hyderabad

Agreement signed on 9th December 2016

Name of the Project

Development and Commercialization of Foot-and-Mouth Disease (FMD) Vaccine for Veterinary Use

Sector

Healthcare

Objective of the Project

TDB signed a loan agreement with M/s Sanvita Biotechnologies Pvt. Ltd., Hyderabad, for a project titled "Development and Commercialization of Foot-and-Mouth Disease (FMD) Vaccine for Veterinary Use".

The proposed project envisages setting up an integrated state-of-the-art facility for manufacturing & formulation of FMD vaccine for veterinary use, complying with WHO cGMP and adhering to safety norms. Moreover, it is also proposed to construct a modern BSL3 compliant and comprehensive animal testing unit with unique features having dedicated incinerator, underground bio-waste collection and disposal systems.

The project, apart from implementing the indigenously developed technology, will meet the social objectives by increasing life of live-stock and earnings to the farmers across the country, socially relevant to public health and will play an important role in supporting the national program on "control of FMD". The demand for FMD vaccine in the country is increasing as more and more animals are vaccinated under the FMD Control Programs (FMD-CP) being sponsored by both central and state government agencies. During the last 5 years the country has used about 150 - 200 million doses of FMD vaccine per year under various programmes. FMD vaccine requirements in our country during the 12th Plan period will be about 600 million doses per year due to increased areas for FMD control.

M/s Sanvita Biotechnologies Pvt. Ltd., an affiliate company to M/s Vivimed, has been involved in setting up the facilities for production of veterinary and human vaccines by licensing the technologies developed by Indian Veterinary Research Institute, ICAR, GOI. It has been working on FMD vaccine and Brucelliosis in animals for the last couple of years with the aim of commercialization.

Total Project Cost

Rs. 101.18 crore

TDB's Assistance

Rs. 16.00 crore

M/s TATA Power Company Ltd. – Strategic Engineering Division (TATA Power SED), Bangalore

Agreement signed on 17th December 2016

Name of the Project :

Setting up a Defence Manufacturing Facility at 50 acres Land at Vemagal Industrial Area, Kolar District, Karnataka

Sector

Defence

Objective of the Project

TDB signed a loan agreement with M/s TATA Power Company Ltd. – Strategic Engineering Division (TATA Power SED), Bangalore for a project titled "Setting up a Defence manufacturing Facility at 50 acres Land at Vemagal Industrial Area, Kolar District, Karnataka".

Under this project, TATA Power SED proposes to set-up a defence manufacturing facility at an acquired land at Vemagal for the development of products in strategic defence areas such as telecom products, strategic electronics, avionics, opto-electronics and power supplies for ESDM Products. The facility will be used for manufacturing and integration of high volumes and large systems for various ongoing and upcoming programmes such as IEWS-MT, TCS, BMS, Rocket and Missile Launchers e.g. Pinaka, Akash, MRSAM etc.

TATA Power SED have core competency in system engineering capabilities for Indian defence. They have provided turnkey solutions in the areas of air defence, electronic warfare, command & control system. The company has been identified as a capable developing agency for two large Make Programme of the Ministry of Defence (MoD) viz. Tactical Communication System (TCS) and Battle Field Management System (BMS).

Total Project Cost

Rs. 385.00 crore

TDB's Assistance

Rs. 109.00 crore

M/s SoftTech Engineers Pvt. Ltd., Pune

Agreement signed on 6th February, 2017

Name of the Project

Development and commercialization of RuleBuddy products (erstwhile "ArchiTx")

Sector

Information Technology

Objective of the Project

TDB signed a loan agreement with M/s SofTech Engineers Pvt. Ltd., Pune, for a project titled "Development and commercialization of RuleBuddy products (erstwhile "ArchiTx")".

The project aims to develop & commercialize RuleBudddy as an e-Commerce portal to provide services for project feasibility and building permits through leveraging penetration of its flagship product AutoDCR. The scope of the RuleBuddy portal is to provide a design for professional depth and information about building bylaws and building plan approval. It is completely indigenous product developed in-house as one stop solution to address current pain areas in construction project feasibility and building permits during the conception and design stages. Currently, no online portal is available in India to provide such services.

The commercial services offered by RuleBuddy would help architects, builders, real estate developers, infrastructure companies and investors in knowing their project potential & approval requirements well in advance. Use of RuleBuddy by investors in infrastructure industry will help them understand the need for various departmental NOC's and will create a common platform thereby enhancing efficiency & reducing time in approval process drastically. This is in line with focus of GOI to help catalyze the growth towards infrastructure development in the country.

The company is in the business of developing end-to-end solution in Architecture Engineering & Construction Space (AEC space) encompassing all three main user segments viz. professional users like structural engineers, architects & consultants, corporate users in private sector as well as public sector like property developers, investors, real estate companies and Central/State Government & bodies of local self-governance like Municipal Corporations etc.

Total Project Cost

Rs. 6.15 crore

TDB's Assistance

Rs. 2.45 crore

M/s Terminus Circuits Pvt. Ltd., Bangalore

Agreement signed on 16th March, 2017

Name of the Project

Commercialization of High Speed serial link products

Sector

Information Technology

Objective of the Project

TDB signed a loan agreement with M/s Terminus Circuits Pvt. Ltd., Bangalore for a project titled "Commercialization of High Speed serial link products".

In this project, the company aims to expand the availability of its silicon proven IPs in variety of flavors to improve its customer base in India and worldwide. These products are import substitutes and export oriented. Terminus circuits is 7+ year old company in the design and development of High Speed Serial Link products. Its flagship products are USB3.0/3.1, PCIE Gen4/3/2/1 and multi-standard SerDes.

The innovative architectures developed in-house bring in the superior performance products with high throughput and low latency. The state-of-the art subsystems like PCIE Gen4, USB3.1 and the HSS links that go into high end computing systems like High Performance Computers for cloud computing, brain simulations, weather forecasting in enterprise applications and for applications like laptops, mobiles etc., in consumer products.

M/s Terminus Circuits Pvt. Ltd., Bangalore was started in January, 2010. Its main focus is into high speed interface circuits and Analog IP design & development. The nature of activity is in highly skilled area with high gestation period. The company has developed complete solution for high speed serial links for developing the circuit design and architecture to fulfil the needs of stringent standards set by the standards group like IEEE, USB, PCI-SIG etc.

Total Project Cost

Rs. 20.79 crore

TDB's Assistance

Rs. 9.70 crore

M/s Renalyx Health Systems Pvt. Ltd., Bangalore

Agreement signed on 16th March, 2017

Name of the Project

Development of an affordable connected Haemodialysis Machine for Rural Public Health Centres

Sector

Healthcare

Objective of the Project

TDB signed a loan agreement with M/s Renalyx Health Pvt. Ltd., Bangalore for a project titled "Development of an affordable connected Haemodialysis Machine for Rural Public Health Centres".

The company aims to build a total system for early detection of Chronic Kidney Disease (CKD) through a hemodialysis machine, Renalife. Renalife is an internet-connected machine and can be configured in two ways in an atypical dialysis center - the first one as a standalone dialysis machine and the other as a console in a Centralized dialysate distribute system (CDDS). Renalife dialysis machine has user friendly and intuitive user interface made available on an Android tablet.

Real-time data of dialysis patient can be collected and sent to a remotely located computer and can be accessed by a remotely located nephrologist. This connectivity enables the nephrologist to guide the dialysis technician from a remote location, to take appropriate action. In addition, based on the patient's history, reminders for upcoming dialysis schedule and for medications, precautions, and dietary recommendations will be sent to the patient or the caregiver. All the products by Renalyx Health Systems are developed in-house.

Renalyx Health Systems was incorporated in October, 2012 with a vision to provide affordable world class health care solutions for CKD. The company is running ongoing programs both in prevention as well as treatment of CKD.

Total Project Cost

Rs. 11.99 crore

TDB's Assistance

Rs. 4.00 crore

M/s Energos Technologies Pvt. Ltd., Mumbai

Agreement signed on 23rd March, 2017

Name of the Project

Changing Energy Habits

Sector

Information Technology

Objective of the Project

TDB signed a loan agreement with M/s Energos Technologies Pvt. Ltd., Mumbai for a project titled "Changing Energy Habits".

Under this project, the company aims to commercialize an IOT device to provide a complete solution for monitoring and control of electricity for commercial offices with room air-conditioners through development of advanced analytics and setting-up of global 24X7 network operating centre to commercialize energy saving services on a SaaS model. Energos has designed and developed this self-learning intelligent IOT device to automate and monitor equipment located at multiple cities across India and the world. It has been successfully implemented across different offices of Axis Bank, ICICI Bank & Cafe Coffee Day. Further analytics and decision-making algorithms are under development for other business verticals.

Efficient use of energy and its conservation assumes even greater importance in view of the fact that one unit of energy saved at the consumption level reduces the need for capacity creation. Further, such saving through efficient use of energy can be achieved at significantly lower investment on capacity creation. Energy efficiency would therefore significantly supplement the efforts to meet power requirement.

Energos has been established with a vision to use latest trends in ICT technologies to achieve energy savings with a challenge to measure real-time impact and to achieve efficiency in terms of practicing sustainability. It is an Information Technology & services company offering web based M2M technology solutions to large consumers of conventional or renewable energy.

Total Project Cost

Rs. 6.55 crore

TDB's Assistance

Rs. 2.25 crore

M/s Iatome Electric India Pvt. Ltd., Coimbatore

Agreement signed on 28th March, 2017

Name of the Project

Development and Commercialisation of Portable X-ray machine

Sector

Healthcare

Objective of the Project

TDB signed a loan agreement with M/s Iatome Electric India Pvt. Ltd., Coimbatore for a project titled "Development and Commercialization of Portable X-ray machine".

The project entails manufacturing and commercialization of four types of X-Ray imaging equipment including:

- Portable Hand-Held X-Ray- This is a battery operated compact X-ray machine that can be hand-held and operated. This equipment is specifically designed for dental intra-oral radiography.
- Digital Imaging for Dental X-Ray- To complement Product 1, the company is working on a digital X-ray sensor. Using this, X-ray imaging can go filmless. The software shall be developed in-house.
- Portable General X-Ray- A multi-purpose X-ray equipment. The device is designed to be highly mobile/portable, simple to operate & reliable with a battery back-up to enable usage even without electric power.
- X-Ray Generator for Fluoroscopy- This will be an OEM sub-component product for use by the many C-Arm system builders in the country.

Iatome is a power electronics engineering and technology company with product profile on X-ray generators and high voltage electronics. The company has developed products for GE Medical Systems & BPL Medical Systems. Further, they have researched and developed their own indigenous technology for X-ray generation, involving advanced methods in electrical, mechanical, high voltage, materials & software engineering.

Total Project Cost

Rs. 5.36 crore

TDB's Assistance

Rs. 2.04 crore

M/s DiabetOmics Medical Pvt. Ltd., Hyderabad

Agreement signed on 28th March, 2017

Name of the Project

Manufacture and Commercialization of Novel, Innovative, Point-of-Care Diagnostic Tests for Monitoring of Diabetes

Sector

Healthcare

Objective of the Project

TDB signed a loan agreement with M/s DiabetOmics Medical Pvt. Ltd. (DML), Hyderabad, for a project titled "Manufacture and Commercialization of Novel, Innovative, Point-of-Care Diagnostic Tests for Monitoring of Diabetes".

The project relates to the manufacture and commercialization of point-of-care tests for monitoring diabetes. The company has adopted the tests to a lateral flow format enabling performance with very minimal equipment at the point of care.

- "Lumella" is a point-of-care test for pre-eclampsia and gestational diabetes and uses a drop of blood from finger prick to quantify the levels of "Glycosylated Fibronectin", a novel biomarker that helps to triage pregnant women at risk of developing pre-eclampsia and GDM in their pregnancy.

- Insudex is a rapid, point-of-care test for detection of auto antibodies in patients with Type-I Diabetes. This test is based on finger prick sample for detection of common antibodies such as GAD 65, insulin antibodies and islet cell antibodies seen in patients with Type 1 Diabetes.

- The company has been active in the domain of development & manufacture of innovative, novel, point-of-care tests for the monitoring of Gestational Diabetes (GDM), Pre-eclampsia (PE), Type 2 Diabetes and Autoimmune Diabetes. The company has multiple national and global patents on these.

Total Project Cost

Rs. 25.77 crore

TDB's Assistance

Rs. 5.00 crore

M/s Systemantics India Pvt. Ltd., Bangalore

Agreement signed on 31st March, 2017

Name of the Project

Design, Development & Manufacturing of Industrial Robots

Sector

Engineering

Objective of the Project

TDB signed a loan agreement with M/s Systemantics India Pvt. Ltd., Bangalore for a project titled "Design, Development & Manufacturing of Industrial Robots".

Systemantics India Pvt Ltd., (SIPL) has been setting-up facilities, based on in-house technologies to manufacture industrial robots, with the objective to enable widespread adoption of flexible automation in Indian industry for tedious or hazardous tasks that manpower is not suited to perform on a sustainable basis and not for tasks that benefit from human judgment and which human labour is effective and content to perform. The proposed products are Planar Parallel Manipulator (PPM) which is a 4-axis robot, the articulated 6 Axis (A6A) robot and the Hybrid 6 Axis (H6A) combining 6 axis and large 1.5 meter reach and loads between 10 to 20 kg.

Systemantics is in the industrial robotics market, a market that is growing significantly in India and worldwide. It addresses the market need of reduced cost and greater affordability to enable widespread use of robotics. Its value proposition resonates with the target market and its vision & mission is fully aligned with the government's 'Make in India' initiative. Technologies are innovative, patented and developed completely in-house, using latest advances in electronics and software, leading to lower costs and greater efficiency.

Total Project Cost

Rs. 8.20 crore

TDB's Assistance

Rs. 4.10 crore

PROMOTIONAL ACTIVITIES

Technology Day and National Awards 2016 (11th May, 2016)

The Technology Day 2016 was celebrated on 11th May 2016 at Vigyan Bhawan, New Delhi with the theme "Technology Enablers for Start-up India". Hon'ble President of India, Shri Pranab Mukherjee, was the Chief Guest on this occasion. Dr. Harsh Vardhan, Hon'ble Union Minister of Science & Technology and Earth Sciences presided over the function. Prof. Ashutosh Sharma, Secretary, DST and Chairman, TDB gave the welcome address and touched upon the theme of the event.

Addressing the occasion, Hon'ble President said, "It is the untiring efforts and missionary zeal of dedicated scientists and technologists of our nation that has paved the way for India's emergence as a technology power. We are now working towards a technological revolution aimed at empowering millions of our countrymen. The National Technology Day is symbolic of our quest for scientific inquiry and technological excellence, and a translation of that quest into an integrated scientific, societal and industrial approach. It marks not only our technological innovations but their successful commercialization making the fruits of painstaking research available to the people at large".

The Hon'ble President highlighted the achievements of the country and said that India is gradually inching towards becoming one of the leading countries in the field of scientific research. It is enviably placed amongst the top five nations in the field of space exploration. ISRO's Polar Satellite Launch Vehicle, in its thirty-fifth flight recently, successfully launched a 1,425 kg satellite into the orbit. He congratulated the entire community of Indian space scientists for this unique "Made in India" accomplishment. He emphasized that we must not rest on our laurels as this achievement should propel us to further up-grade our existing technologies. With rapid changes occurring in science education and research, only those countries having a technological edge will emerge successful in the fiercely competitive global market. He said that innovation is the antidote to stagnation. The youth of our country are brimming with ideas and enterprise. They are harnessing technology to find solutions to day-to-day problems of the common man.

National Awards – 2016 for Successful Commercialization of Indigenous Technology

The National Award was given to M/s RESIL Chemicals Pvt. Ltd., Bangalore for indigenous development and commercialization of N9 Pure Silver developed by the company, jointly in collaboration with SMITA Research Lab of Indian Institute of Technology, Delhi and International Advanced Research Centre for Power Metallurgy & New Materials, Hyderabad.

National Award to M/s RESIL Chemicals Pvt. Ltd., Bangalore

N9 Pure Silver is an internationally certified silver-based antimicrobial that can be effectively used on textiles and other substrates. It is skin and environment safe, in addition to being easy to apply through exhaust, padding, spraying, moulding and coating processes. As an antimicrobial, it not only keeps the treated surface hygienic, but also offers a safe and natural way to keep textiles odour-free and fresh. N9 Pure Silver finds applications in work wear, military uniforms, hospitality sector, healthcare industry, home care and fashion apparel industry.

A trophy with a cash award of Rs. 10.00 lakh was presented by the Hon'ble President of India.

Awards for SSI Unit-2016 for Success Commercialization of Indigenous Technology Based Product

Hon'ble President of India also presented Awards for SSI Unit-2016 for successful commercialization of indigenous technology based product. Each awardee was presented with a trophy and a cash award of Rs. 5.00 lakh. The awards were given to:

1. M/s Iatome Electric India Pvt. Ltd., Coimbatore for developing and commercializing a cost-effective hand-held battery operated portable X-ray machine, based on digital high frequency X-ray generator technology with composite insulation. The product works on Lithium-Ion battery and is versatile enough to be carried and used in locations with no electricity.

SSI Unit Award to M/s Iatome Electric India Pvt. Ltd., Coimbatore

SSI Unit Award to M/s Tejas Networks Ltd., Bangalore

2. M/s Tejas Networks Ltd., Bangalore for commercialization of TJ1400 - Packet Transport Node: a family of innovative, high-capacity, fiber optic networking products that are deployed in the modern-day fiber optic transmission networks for mobile base-station connectivity (for 2G, 3G & 4G), enterprise data service and bandwidth services.

National Technology Day - Product Released

Dr. Harshvardhan, Hon'ble Minister of Science & Technology & Earth Science commercially launched the product namely "Seaweed Aquasap" developed by M/s AquAgri Processing Private Limited, New Delhi during Technology Day-2016 on 11th May, 2016 at Vigyan Bhawan. However, the project was completed in year 2015-16.

Commercial launch of "Seaweed Aquasap" developed by M/s AquAgri Processing Private Limited, New Delhi

M/s AquAgri Processing Private Limited is the first company in India to introduce commercial cultivation of seaweeds through self-help groups in coastal Tamil Nadu. The produce of the growers is procured at pre-agreed prices and processed to manufacture Carrageenan, used by the food and cosmetics industries and bio-stimulants for agriculture application. This is based on an indigenously developed patented process licensed from CSMCRI, CSIR. AquAgri offers the bio-stimulants in multiple formats, in both liquid and powder form to suit soil, foliar and drip irrigation application. These bio-stimulants have been extensively tested across crops in multiple locations by the agricultural research system and the efficacy in improving both the yield and the quality of crop has been validated.

After the award ceremony, Dr. Harsh Vardhan inaugurated an exhibition of TDB supported companies at Vigyan Bhawan wherein indigenous innovative products developed by enterprises under TDB's financial assistance were showcased.

20th Foundation Day of TDB (1st & 2nd September, 2016)

TDB celebrated its 20th Foundation Day on 1st September 2016. On this occasion, a 2-day symposium was organized on "Strategizing Commercialization through Technology & Innovation" on 1st - 2nd September, 2016. Topics were selected in the following six areas: i) Intricacies of Indigenization in Defence Sector, ii) Cyber Security (IT): Imminent Risks & Potential Solutions, iii) Robotics & Electronics: Integrating into Daily Lives, iv) Nanoscience and Nanotechnology: Journey from Past to Recent, v) Clean and Green Energy: Are we serious about issues, vi) Industrial Vibrancy in Health Sector. The concluding session of the symposium was on Technology Policy Alignment. For all the sessions, invited speakers were chosen from Academia and Industries. Besides the lectures, there were panel discussions with experts from Industries, DRDO, R&D Institutions, NITI Aayog and representation from FICCI, CII, etc.

The symposium was inaugurated on 1st September 2016 by Prof. Ashutosh Sharma followed by deliberations on '2 Decades of TDB Journey' by Shri. S.B. Krishnan, First Secretary, TDB on 'History & Philosophy' and by Dr. K.I. Varaprasad Reddy, Former CMD, Shantha Biotechnics on 'Taking Incremental Steps'. The keynote address was delivered by Sh. Y.S. Chowdary, Hon'ble Minister of State for S&T and ES.

TDB-20th Foundation Day (2 Decades of Journey)

The last session titled "Technology Policy Alignment" was chaired by Dr. Bindu Dey, Secretary, TDB and included the following speakers - a) Prof. Ramesh Chand, Member NITI Aayog, b) Prof. Ashutosh Sharma, Chairman, TDB, c) Shri Ajay Shrivasatava, MD, M/s Dimensions, d) Shri B.K. Jain, Vishwa Hydrogel, and e) Ms. Eittee Gupta, FICCI. The aim of this session was to understand and implement the necessary values to our vision for the race ahead for Indian technology landscape.

Interactive Meetings with Industry

TDB organised a series of interactive meetings with industry, potential entrepreneurs and technology providers through the industry associations and R&D organizations, etc. TDB also participated in various exhibitions.

Through these multifunctional platforms, TDB aims at creating an awareness amongst the Industries, R&D Organisations, Academic Institutions, Scientific and Industrial Research Organisations, etc., on the availability of financial assistance from TDB on soft terms for their commercialization efforts especially for indigenously developed technologies.

TDB has participated and organized workshops in close co-ordination with chambers of commerce, trade associations and institutions spread all over the country. TDB officers participated in various exhibitions and interactive meetings held with industry and institutions during 2016-17.

TDB partnering in India Africa Day Gala 2016 (22nd April, 2016)

TDB partnered in India Africa Day Gala 2016 organized by ASAHOM on 22nd April, 2016 at PSOI Club Event Lawns, Vinay Marg, Chanakyapuri Diplomatic Enclave, New Delhi.

The event was a social platform to network, strengthen and enhance the historic, cultural, social and business relationships with Africa. It provided a strong business opportunity through branding, marketing and displays. Several dignitaries (Ministers, MPs, Former Ambassadors, Think-tanks, NGOs), representatives from Ministry of External Affairs & Other Ministries, 37 African High Commissioners & Ambassadors with Commerce, Ministers / Counsellors, 17 African Honorary Consulates, Public Sector Undertakings (CMD of Prominent PSUs), Indian Industry Chambers, Private Sector Companies, Universities, Educational Institutions, Hospitals, etc. attended the event.

It was a great opportunity for TDB and its investee companies to demonstrate their technologies in the forum, which led to business development opportunities.

Visit to Kenya for establishing a Cluster for Healthcare/Agriculture as a new vertical (Africa Alliance)

The success of 3rd India-Africa Forum Summit (October, 2015) and further rounds of diplomatic interactions reinforced the need for expanding the scoepe of this alliance for mutual empowerment and resurgence. One area in which an interest has been strongly evinced is "Manufacturing Cluster/s OR units under Healthcare/agriculture/farm equipments activities".

With this background, TDB in association with FICCI organized a special programme in Kenya on the sidelines of the Hon'ble Prime Minister of India's maiden visit to Kenya during 8th -11th July, 2016.

A number of industry players accompanied TDB in this endeavour, which received an impressive response from African Government and Industry. Indian enterprises interacted through Indian government officials, FICCI, Kenya, Governments of other participating counties and private sector federations to deploy and commercialize their technologies and innovations in Africa.

MoU with Economic Development Board (EDB) of the A.P. Government

The Government of India launched the "Make in India" initiative in 2014 with the aim of transforming India into a global design and manufacturing hub. The initiative is focused on encouraging domestic and multinational companies to manufacture their products in India. It aims to develop India as a force to reckon with on a global scale by completely revamping and overhauling out-dated processes and policies, thus promoting self-reliance and boosting the economy. In line with this initiative, the TDB is committed to provide support for projects that will help in the development of home-grown, commercially viable technologies/products and bring them to fruition in the form of clear deliverables.

In the backdrop of the above, TDB issued "Call for Proposals" earlier this year in various strategic areas as identified in "Make in India", especially the Medical Devices sector including imaging equipment (such as CT scanners, MRI machines etc).

The advertisement received an enthusiastic response from companies. To further its efforts, TDB joined hands with the Government of Andhra Pradesh to provide a major thrust to the indigenous manufacturing of medical devices in its "Andhra Med Tech Zone" spread over 270 acres. Med Tech Zone proposes to have at least 200-300 units, providing jobs to 20,000 - 25,000 persons, entailing investment of approximately Rs. 25,000 crores.

TDB expressed a keen interest in funding at least 20 units that would like to set up their enterprises in the Andhra Med Tech Zone.

An MoU was signed between Economic Development Board (EDB) of the Government of Andhra Pradesh and TDB.

TDB participation in "5th Science Expo 2016" at Solan (18th – 20th July, 2016)

The 5th Science Expo 2016 was organized by Sansa Foundation, New Delhi during 18th -20th July, 2016 at Solan, Himachal Pradesh. The objective was to provide a platform for masses to know about the Government programs & policies in various fields and an opportunity to interact with other stake-holders and share their experiences, knowledge and efforts. The expo aimed to spread awareness on science and technology and inculcate science temperament at the grass root level, primarily amongst students and general public at Himachal Pradesh. TDB participated in the exhibition by showcasing its success stories of the last 20 years and made the students and general public aware about its schemes. Besides TDB, other Departments/ organizations like CSIR, Ministry of Earth Science, Coffee Board, National Horticulture Board, NRDC, Coconut Development Board, Cane & Bamboo Technology Centre, Bamboo Development Agency, Mizoram, National Innovation Foundation, Export Inspection Council of India also participated in the Expo.

The Exhibition was inaugurated by Hon'ble Prof. A. D. N. Bajpai, Vice Chancellor of Shimla University. School children & college students from across the city & others states visited the exhibition and got awareness about the Science & Technology. A display by students from various schools on their innovative models such as "Hydraulic Elevator", "Electric Fan", "Roads without Traffic Lights", "Rain Alarm", etc. was the most attractive event. Many visitors appreciated the models and were keen to see the working models. A large number of visitors enquired about TDB's activities.

TDB at "Government Achievements & Schemes Expo -2016" at Pragati Maidan, New Delhi (22nd - 24th July, 2016)

TDB participated in "Government Achievements & Schemes Expo-2016" organised by NNS Events and Exhibition Pvt. Ltd. during 22nd - 24th July, 2016 at Hall No.7, Pragati Maidan, New Delhi. The exhibition aimed to showcase the achievements, welfare and developmental schemes, products/services etc. of various ministries, departments, institutions, boards, corporate bodies, etc. of the central and state governments at a single platform.

The Exhibition was inaugurated by Hon'ble Minister of State for Micro, Small & Medium Enterprises, Shri Haribhai Parthibhai Chaudhary. The Hon'ble Minister visited various stalls and held discussions with the exhibitors. While speaking on the occasion, he mentioned that events such as this spread awareness among the masses about the various People's Welfare Schemes of the government. Many dignitaries and senior officers of the central and state governments attended the exhibition.

The achievements made by TDB during the last 20 years were displayed. A large number of visitors enquired about TDB's activities and the Project Funding Guidelines were provided to the interested visitors. The TDB brochures were also distributed to the visitors for awareness about TDB's schemes and achievements.

Around 100+ exhibitors participated in the expo. The expo received very enthusiastic response from the visitors. School children & college students from across the city & other states visited the exhibition and got awareness about the Science & Technology.

TDB participation in First Nobel Prize Series India 2017 during - Vibrant Gujarat Global Summit 2017

Department of Biotechnology (DBT) organized the first Nobel Prize Series India 2017 on 9th & 10th January, 2017 during 8th edition of the Vibrant Gujarat Global Summit. The event was inaugurated by the Hon'ble Prime Minister of India. The event hosted 9 Nobel Laureates and eminent Indian scientists from fields of Physical, Chemical and Biological Sciences. The programme was aimed to stimulate innovation, creative thinking and engagement in science among students in India.

AgriTech Commercialization Platform

TDB signed an MoU with Indian Institute of Corporate Affairs (IICA) and Technology Information Forecasting and Assessment Council (TIFAC) to establish a pilot capacity building initiative in sourcing innovations for commercialization and hosting joint workshops, seminars and conferences.

Through this MoU, these entities collaborated with each other in the area/s of "Scouting and sourcing agriculture-technology based innovations for improving farm-land productivity". The program is in line with Prime Minister's Vision to Double Farmers' Income (DFI) by 2022.

In the backdrop of the above, two Agri-tech Commercialization Platform workshops were conducted at New Delhi and Coimbatore:

Agri-Tech Commercialization Workshop at NASC Complex, Pusa (18th-20th January, 17)

Agri-Tech Commercialization Workshop at TNAU, Coimbatore (24th-25th January, 2017)

The workshops included a brief overview of TDB funding guidelines followed by training modules for project proposal writing. The participants presented their projects which were then evaluated for their eligibility to apply for financial assistance from TDB. A total of 32 presentations (6 at New Delhi and 26 at Coimbatore) were made out of which 13 projects were found suitable for applying for financial support from TDB.

TDB participation in "Vision Jammu & Kashmir Exhibition-2017" (23rd – 25th February, 2017)

TDB participated in "Vision Jammu & Kashmir Exhibition-2017" organized by Sansa Foundation, New Delhi during 23rd -25th February, 2017 at Jammu. The exhibition was aimed to help State Government's endeavour to establish an industry friendly environment in the State by playing the role of a facilitator for holistic industrial development. The exhibition was inaugurated jointly by Hon'ble Member of Parliament (Rajya Sabha) Shri Shamsher Singh and Hon'ble Minister J&K Govt. Shri Shyam Lal Chaudhary. At TDB pavilion, a large number of visitors enquired about TDB's activities.

Signing MoU on 'Implementation of Technology Development Fund Scheme' (6th March, 2017)

DRDO has operationalized a Technology Development Fund (TDF) to encourage research through private industries and to handhold them in high-risk development tasks. The TDF has been established to promote self-reliance in Defence Technology as a part of the "Make in India" initiative. Under this scheme, the industries will be involved in development activities in high-end technical areas to accelerate the production process without any burden on R&D cost. The TDF released by DRDO in September, 2016 is bound to encourage and enhance the R&D activities in private industries.

Dr. Bindu Dey, Co-Chair, GITA and Mr. M H Rahman, CC R&D TM DRDO MoD GoI, signed an MoU on 'Implementation of Technology Development Fund Scheme'.

The TDF programme covers the following technology development in terms of:

- Significant improvement/upgradation/further development in the existing product / process / application etc.
- Technology Readiness Level (TRL) of upgradation from TRL-3 onwards to realization of products as per Tri-series requirements.
- Development of futuristic technologies / innovative products which can be useful for the defence application.
- Import substitution of components whose technologies does not exist with the Indian industry.

Website: www.tdb.gov.in

RESEARCH
&
DEVELOPMENT CESS

The Research and Development Cess Act, 1986, as amended in 1995, provides for the levy and collection of cess on all payments made towards the import of technology. The rate of cess is 5 percent. The cess is payable by an industrial concern which imports technology on or before making any payments towards such import. The proceeds of the cess are credited to the Consolidated Fund of India. The cess is levied and collected for the purpose of encouraging the commercial application of indigenously developed technologies and for adapting imported technologies for wider domestic application.

Out of the cess collections, the Government of India, through appropriations made by Parliament, pay to the Fund for Technology Development and Application to be utilized for development and commercialization of indigenous technology and adaptation of imported technology. The Fund is administered by the Technology Development Board.

Cess Collections and Payments (1997-2017)

The following table indicates the year-wise cess collection from 1996-97 (the year in which the Technology Development Board was constituted by the Government) and allocations to TDB and payments to TDB.

Research and Development Cess, Collections and Disbursements (Rs. in crore)

Year	Cess Collection (CGA's (Figures)	Allocation to TDB		TDB
		Budget Estimate (BE)	Revised Estimate (RE)	
1996-97	80.13	30.00	30.00	29.97
1997-98	81.42	70.00	70.00	49.93
1998-99	81.10	50.00	50.00	28.00
1999-00	88.93	70.00	70.00	50.00
2000-01	98.91	70.00	70.00	62.79
2001-02	95.30	63.00	63.00	57.00
2002-03	99.47	58.00	58.00	56.00
2003-04	119.51	55.00	55.00	53.65
2004-05	156.99	54.00	54.00	48.10
2005-06	176.61	43.50	43.50	42.66
2006-07	186.56	33.50	33.50	4.32
2007-08	254.09	63.00	20.80	19.00
2008-09	310.33	20.80	20.80	0.00
2009-10	418.22	50.00	10.00	0.00
2010-11	592.22	50.00	5.00	5.00
2011-12	702.54	50.00	25.00	0.00
2012-13	685.62	50.00	25.00	22.50
2013-14	737.54	50.00	15.00	13.50
2014-15	906.78	211.06	7.50	6.75
2015-16	914.81	100.00	38.79	30.00
2016-17	1187.24	100.00	10.30	30.30
Total	**7974.32**	1341.86	775.19	**609.47**

A total of Rs. 7974.32 crore was collected through R&D cess during the year 1996-2017. A cumulative sum of Rs. 609.47 crore over the period of 21 years (1996-2017) has been made available through Grant-in-aid from non-plan expenditure of Department of Science & Technology.

ADMINISTRATION

Section 12 of the Technology Development Board Act, 1995, prescribes that the Board shall prepare its annual report, giving a full account of its activities during the previous financial year. As per section 13(4) of the Technology Development Board Act, the Board has to furnish to the Central Government, its audited copy of accounts together with auditor's report.

The Annual Report, including audited copy of the Annual Accounts of the Technology Development Board for the year 2015-16 was laid before Rajya Sabha and Lok Sabha on 22.03.2017 and 23.03.2017 respectively.

TDB Secretariat

New Incumbent

Cdr Smriti Tripathi (Retd), joined Technology Development Board as Under Secretary w.e.f. 3rd February 2017 on absorption basis.

Income Tax exemption

The Central Board of Direct Taxes (CBDT), New Delhi has granted exemption to TDB - u/s 10[23C(iv)] of the Income Tax Act, 1961 for the further period i.e. Assessment Year 2000-01 and onwards vide notification no. 173/2007 dated 18th May, 2007 issued on 21st May, 2007.

Implementation of Official Language

The Technology Development Board, since its inception, has implemented various provisions pertaining to the official language of the Union, and had printed Notifications, Annual Reports, Project Funding Guidelines, Brochures, Vouchers etc. in Hindi and English. The exhibits / panels are prepared in Hindi and English for display in various exhibitions.

ACCOUNTS STATEMENT FOR THE YEAR 2016-17

TECHNOLOGY DEVELOPMENT BOARD

BALANCE SHEET AS ON 31st March, 2017

Amount in Rupees

CORPUS/ CAPITAL FUND AND LIABILITIES	Schedule	Current Year	Previous Year
CORPUS/CAPITAL FUND	1	99670,13,160	9,41,88,62,234
RESERVES AND SURPLUS	2	-	
EARMARKED / ENDOWMENT FUNDS	3	494,47,559	5,79,11,687
SECURED LOANS AND BORROWINGS	4	-	-
UNSECURED LOANS AND BORROWINGS	5	-	-
DEFERRED CREDIT LIABILITIES	6	-	-
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	7	101,00,919	99,92,974
TOTAL		**100265,61,638**	**9,48,67,66,895**
ASSETS			
FIXED ASSETS	8	42,79,480	44,04,313
INVESTMENTS- FROM EARMARKED/ ENDOWMENT FUNDS	9	65,99,000	65,99,000
INVESTMENTS- OTHERS	10	22304,81,571	2,20,16,73,340
CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC.	11	77852,01,587	7,27,40,90,242
MISCELLANEOUS EXPENDITURE (TO THE EXTENT NOT WRITTEN OFF OR ADJUSTED)		-	-
TOTAL		**100265,61,638**	**9,48,67,66,895**
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	24	-	-
CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS	25	-	-

-sd-

(DR. BINDU DEY)
SECRETARY
TECHNOLOGY DEVELOPMENT BOARD

-sd-

(PROF. ASHUTOSH SHARMA)
CHAIRPERSON
TECHNOLOGY DEVELOPMENT BOARD

TECHNOLOGY DEVELOPMENT BOARD

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31st March 2017

(Amount in Rupees)

INCOME	Schedule	Current Year	Previous Year
Income from Sales/ Services	12	-	-
Grants / Subsidies	13	3030,00,000	3000,00,000
Fees/ Subscriptions	14	-	-
Income from Investments (Income on Invest. from earmarked/endow.)	15	-	-
Income from Royalty, Publication etc.	16	67,73,214	30,10,762
Interest Earned	17	5387,59,669	53,30,85,105
Other Income	18	50,17,730	7,64,349
Increase / (decrease) in stock of Finished goods and works-in-progress	19	-	-
TOTAL (A)		**8535,50,613**	**8368,60,216**
EXPENDITURE			
Establishment Expenses	20	229,91,710	1,84,62,366
Other Administrative Expenses etc.	21	2157,98,678	4,84,49,413
Expenditure on Grants, Subsidies etc.	22	594,00,000	11,09,89,391
Interest	23	-	-
Depreciation (Net Total at the year -end - corresponding to Schedule -8)		9,31,994	5,70,221
TOTAL (B)		**2991,22,382**	**17,84,71,391**
Balance being excess of Income over Expenditure (A-B)		5544,28,231	65,83,88,825
Prior Period Adjustments		2,715	(55,52,351)
Transfer to General Reserve		-	-
BALANCE BEING SURPLUS CARRIED TO CORPUS FUND		**5544,30,946**	**65,28,36,474**
Significant Accounting Policies	24	-	-
Contingent Liabilities and Notes on Accounts	25	-	-

-sd-

(DR. BINDU DEY)
SECRETARY
TECHNOLOGY DEVELOPMENT BOARD

-sd

(PROF. ASHUTOSH SHARMA)
CHAIRPERSON
TECHNOLOGY DEVELOPMENT BOARD

TECHNOLOGY DEVELOPMENT BOARD

RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31st March, 2017

(Amount in Rupees)

RECEIPTS		Current Year	Previous Year
Opening Balance :			
	Investment in short term deposits	4320,00,000	5202,08,332
	Cash in hand	1,23,557	13,037
	Cash at bank	3063,97,743	23,01,73,455
	DFID-INVENT	291,67,365	36,158
Fund for Technology Development & Application			
i)	TD Fund	3030,00,000	3000,00,000
ii)	Interest on short term deposits	350,21,306	4,86,38,653
iii)	Interest on loans	1263,82,620	6,18,71,525
iv)	Interest on royalty	1,92,459	1,12,916
v)	Interest on grants	6,39,153	1,60,588
vi)	Repayment of loans	2846,97,567	30,65,72,805
vii)	Royalty	67,73,214	30,08,066
viii)	Donations	1,03,000	22,000
ix)	Interest on saving accounts	39,97,235	35,39,169
x)	Advance to staff members	-	-
xi)	Miscellaneous receipts	1,13,877	80,395
xii)	Security Deposit Received / Advance	-	-
xiii)	Recoveries from salaries	19,65,154	17,33,511
xiv)	UTI_Ascent Indian Fund & ITUVS	75,35,816	-
xv)	GVFL	-	-
xvi)	Dividend	48,00,853	14,79,656
xvii)	SIDBI Venture Fund	57,54,569	85,68,716
xviii)	Venture East Tenet Fund	91,69,046	97,13,180
xix)	Other Receipt	3,588	52,722
xx)	DFID - INVENT	-	3,02,36,072
TOTAL		**15578,38,122**	**15262,20,956**

-sd-

(DR. BINDU DEY)
SECRETARY
TECHNOLOGY DEVELOPMENT BOARD

-sd-

(PROF. ASHUTOSH SHARMA)
CHAIRPERSON
TECHNOLOGY DEVELOPMENT BOARD

TECHNOLOGY DEVELOPMENT BOARD

RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31st March, 2017

Amount in Rupees

PAYMENTS		CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
ESTABLISHMENT EXPENSES			
i)	Salaries	208,70,215	1,71,56,588
ii)	Travel Expenses (Domestic)	30,05,924	15,58,685
iii)	Honorarium	99,600	39,600
iv)	Over Time Allowance	-	-
v)	Medical Expenses	3,04,423	5,85,129
vi)	Pension Contribution for Deputationists	6,15,981	6,09,334
OFFICE EXPENSES			
i)	Telephone / Telex	24,65,020	8,27,821
ii)	Postage stamps	1,48,074	1,53,318
iii)	Petrol, Oil, Lubricants	76,410	83,766
iv)	Repairs & Maintenance	5,58,003	4,42,075
v)	Consumable Stores & Printing	9,05,772	11,66,879
vi)	Newspapers & Magazines	42,163	14,821
vii)	Entertainment & Hospitality	1,53,841	2,21,907
viii)	Meeting Expenses	9,94,828	9,29,714
ix)	Advertisement & Publicity	89,09,634	43,75,391
x)	Technology Day Expenditure	29,93,330	16,92,864
xi)	Miscellaneous Expenses	8,62,513	9,79,475
xii)	National Award	30,00,000	10,00,000
xiii)	Library Books & Journals	2,160	2,975
xiv)	Legal Charges	42,37,986	93,97,320
xv)	Asset Management Charges	185,05,737	2,24,49,080
xvi)	TA / DA to Experts	25,11,072	10,77,110
xvii)	Honorarium Experts	23,42,542	11,80,500
xviii)	Earnest Money	-	1,00,000
xix)	Bank Charges	-	4,865
xx)	Foundation Day	6,70,096	-
xxi)	Rent	55,000	-
xxii)	Remittance of recoveries to other deptts.	19,65,154	17,33,511
xxiii)	Security Deposits	1,10,000	-
xxiv)	Duties & Taxes	7,07,661	-

TECHNOLOGY DEVELOPMENT BOARD

BOARD EXPENSES

i)	TA / DA to Members	97,901	1,100
ii)	Board Meeting Expenses	1,46,455	81,811
iii)	Fee to Board Members	82,500	30,000
CAPITAL EXPENDITURE			
i)	Fixed Assets	8,66,408	15,83,848
DISBURSEMENTS FROM TDF			
i)	Loans	9980,00,000	26,98,50,000
ii)	Grants	594,00,000	11,09,89,391
iii)	Venture East TeNet Fund II	-	11,10,000
iv)	RVCF	-	1,80,00,000
v)	GITA	46,99,000	2,40,20,000
vi)	SIDBI VCF	131,02,303	5,78,12,275
vii)	SEAF India Agribusiness Fund	56,05,510	2,20,10,228
viii)	IvyCap Venture Trust Fund-1	-	15,00,00,000
ix)	Indian Fund for Sustainable Energy (CIIE)	278,60,449	3,52,60,910
x)	DFID-INVENT	83,18,807	-
CLOSING BALANCE			
i)	Investment in short term deposits including DFID	693,00,000	43,20,00,000
ii)	Cash in hand	69,604	1,23,557
	Cash at Bank		
a)	Bank Balance	2503,27,087	30,63,97,743
b)	Bank Balance - DFID INVENT	428,48,559	2,91,67,365
TOTAL		**15578,38,122**	**15262,20,956**

-sd-

(DR. BINDU DEY)

SECRETARY

TECHNOLOGY DEVELOPMENT BOARD

-sd-

(PROF. ASHUTOSH SHARMA)

CHAIRPERSON

TECHNOLOGY DEVELOPMENT BOARD

TECHNOLOGY DEVELOPMENT BOARD

SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET AS ON 31st March, 2017

(Amounts in Rupees)

SCHEDULE 1- CORPUS/CAPITAL FUND :

	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
Balance as at the beginning of the year	94188,62,234			8,76,60,25,760
Add: Contributions towards Corpus/Capital Fund	-		-	-
Add : Balance of net income transferred from the Income and Expenditure Account	5544,30,946			65,28,36,474
Less: Loans written off (Refer to note 25)	62,80,020			-
BALANCE AS AT THE YEAR - END		**99670,13,160**		**94188,62,234**

SCHEDULE 2- RESERVES AND SURPLUS:

	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
1. Capital Reserve:				
As per last Account	-	-	-	-
Addition during the year	-	-	-	-
Less: Deduction during the year	-	-	-	-
2. Revaluation Reserve:				
As per last Account	-	-	-	-
Addition during the year	-	-	-	-
Less: Deduction during the year	-	-	-	-
3. Special Reserves:				
As per last Account	-	-	-	-
Addition during the year	-	-	-	-
Less: Deduction during the year	-	-	-	-
4. General Reserve:				
As per last Account	-	-	-	-
Addition during the year	-	-	-	-
Less: Deduction during the year	-	-	-	-
TOTAL				

TECHNOLOGY DEVELOPMENT BOARD

SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET AS ON 31 st March, 2017

(Amount in Rupees)

SCHEDULE 3- EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS				
	Current Year		Previous Year	
LIABILITIES				
A. VCF of IDBI				
1) Contribution received by IDBI from Government of India		2884,00,000		2884,00,000
Income from Investment				
a. Interest	13,08,52,144		13,08,52,144	
b. Royalty	5,51,97,900		5,51,97,900	
c. Dividend	86,23,794		86,23,794	
d. Accrued income Less waivers	2,39,03,76,810		2,39,03,76,810	
	2,58,50,50,648		**2,58,50,50,648**	
Less : Amount transferred to TDB	21,25,00,000		21,25,00,000	
	2,37,25,50,648		**2,37,25,50,648**	
Less: Excess Royalty recd. Earlier adjusted towards principal	1,12,50,000		1,12,50,000	
	2,36,13,00,648		**2,36,13,00,648**	
Less : Loans written off	4,36,36,450		4,36,36,450	
Less : Loss on sale of Investment	26,76,250		26,76,250	
	2,31,49,87,948		**2,31,49,87,948**	
Less : Provision on loan	8,10,04,357		8,32,79,357	
Less : Provision on interest & FILD	2,39,03,76,810		2,39,03,76,810	
Less: Audit Fees & other Expenses	17,52,075		17,61,564	
Less: Management fees to IDBI	14,32,60,000		13,63,00,000	
Less: Diminution in value of investment	26,26,000	(30,40,31,294)	26,26,000	(29,93,55,783)
		(156,31,294)		(1,09,55,783)
Amount receivable from TDB (*)		222,30,294		1,75,54,783
		65,99,000		**65,99,000**
B. Innovative Ventures for Technology Development (INVENT) – DFID		**428,48,559**		**513,12,687**
TOTAL		**494,47,559**		**579,11,687**

(*)

1) Due to non performace of the fund, the amount of management expenses claimed by IDBI has not been accepted by TDB.

2) The amount of Rs. 2,22,30,294/-, shown as payable by TDB to IDBI has therefore not been Acknowledged as payable debt in the Balance Sheet of TDB.

TECHNOLOGY DEVELOPMENT BOARD
SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET AS ON 31st March, 2017

(Amount in Rupees)

SCHEDULE 4- SECURED LAONS AND BORROWINGS:	Current Year		Previous Year	
1. Central Government	-	-	-	-
2. State Government (Specify)	-	-	-	-
3. Financial Institutions				
a) Term Loans				
b) Interest accrued and due	-	-	-	-
4. Banks:				
a) Term Loans				
- Interest accrued and due	-	-	-	-
b) Other Loans (Specify)				
- Interest accrued and due	-	-	-	-
5. Other Institutions and Agencies	-	-	-	-
6. Debentures and Bonds	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-
Note: Amounts due within one year				

TECHNOLOGY DEVELOPMENT BOARD

(Amount in Rupees)

SCHEDULE 5- UNSECURED LOANS AND BORROWINGS	Current Year		Previous Year	
1. Central Government	-	-	-	-
2. State Government (Specify)				
3. Financial Institutions	-	-	-	-
4. Banks:				
a) Terms Loans	-	-	-	-
b) Other Loans (Specify)	-	-	-	-
5. Other Institutions and Agencies	-	-	-	-
6. Debentures and Bonds	-	-	-	-
7. Fixed Deposits	-	-	-	-
8. Others (Specify)	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-
Note: Amounts due within one year				

TECHNOLOGY DEVELOPMENT BOARD

SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET AS ON 31st March, 2017

(Amount in Rupees)

SCHEDULE 6- DEFERRED CREDIT LIABILITIES	Current Year		Previous Year	
a. Acceptances secured by hypothecation of capital equipment and other assets	-	-	-	-
b. Other				
Note: Amounts due within one year				
TOTAL				

TECHNOLOGY DEVELOPMENT BOARD

(Amount in Rupees)

SCHEDULE 7- CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	Current Year		Previous Year	
A. CURRENT LIABILITIES				
1. Acceptances	-		-	-
2. Sundry Creditors				
a) For Goods				
b) Others				
3. Security Received		50,000		50,000
4. Interest accrued but not due on :				
a) Secured Loans /borrowings				
b) Unsecured Loans/borrowings	-	-	-	-
5. Statutory Liabilities				
a) Overdue		1,97,908		7,05,511
b) Others		-		
6. Other current Liabilities				
a) Pension contribution for deputations		16,41,175		6,15,981
b) Audit fee payable		4,42,745		3,62,745
c) Pending Adjustment		-		75,00,000
d) Others		-		-
TOTAL (A)		**23,31,828**		**92,34,237**
B.PROVISIONS				
1. For Taxation		-		
2. Gratuity		8,35,034		7,58,737
3. Superannuation/Pension		-		-
4. Accumulated Leave Encashment		-		-
5. Legal Charges		69,34,057		-
TOTAL (B)		**77,69,091**		**7,58,737**
TOTAL (A+B)		**101,00,919**		**99,92,974**

TECHNOLOGY DEVELOPMENT BOARD

SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET AS ON 31st

(Amount in Rupees)

SCHEDULE 8 - FIXED ASSETS										
DESCRIPTION	GROSS BLOCK				DEPRECIATION				NET BLOCK	
	Cost/ valuation As at beginning of the year	Additions during the year	Deductions during the year	Cost/ valuation at the year-end	As at the beginning of the year	On Additions during the year	On Deductions during the year	Total up to the year -end	As at 31.03.2017	As at the 31.03.2016
A. FIXED ASSETS:										
1. LAND:										
a) Freehold	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. BUILDING:										
b) On Leasehold Land	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Ownership Flats/ Premises	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d) Superstructures on Land not belonging to the entity	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. PLANT MACHINERY & EQUIPMENT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 VEHICLES	6,74,375	-	-	6,74,375	-	1,01,156	-	1,01,156	5,73,219	6,74,375
5. FURNITURE, FIXTURES	27,92,552	87,283	-	28,79,835	14,51,816	1,34,074	-	15,85,890	12,93,945	13,40,736
6. OFFICE EQUIPMENT	33,40,854	4,45,301	2,21,288	35,64,867	17,03,611	2,45,588	1,41,041	18,08,158	17,56,707	16,37,243
7. COMPUTER/ PERIPHERALS	20,50,520	-		20,50,520	12,98,559	4,51,176	-	17,49,735	3,00,785	7,51,961
8. ELECTRIC INSTALLATIONS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. LIBRARY BOOKS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. SOFTWARE (PMS)	-	3,54,824	-	3,54,824	-	-	-	-	3,54,824	-
11. OTHER FIXED ASSETS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL OF CURRENT YEAR	**88,58,301**	**8,87,408**	**2,21,288**	**95,24,421**	**44,53,986**	**9,31,994**	**1,41,041**	**52,44,939**	**42,79,480**	**44,04,315**
B.CAPITAL WORK-IN-PROGRESS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	**88,58,301**	**8,87,408**	**2,21,288**	**95,24,421**	**44,53,986**	**9,31,994**	**1,41,041**	**52,44,939**	**42,79,480**	**44,04,315**
(Note to be given as to cost of assets on hire purchase basis included above)										
PREVIOUS YEAR	**106,81,570**	**15,83,848**	**34,07,118**	**88,58,300**	**64,20,460**	**5,70,221**	**25,36,694**	**44,53,987**	**44,04,313**	
Note: During the year assets (ACs) which were not usable or non functional with book value of Rs. 2,21,288/- were scrapped.										

TECHNOLOGY DEVELOPMENT BOARD

SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET AS ON 31st March, 2017

(Amount in Rupees)

SCHEDULE 9 - INVESTMENTS FROM EARMARKED/ ENDOWMENT FUNDS	Current Year		Previous Year
1. In Government Securities	-		-
2. Other approved Securities	-		-
3. Shares	-		-
4. Debentures and Bonds	-		-
5. Subsidiaries and Joint Ventures	-		-
6. VCF of IDBI (Assets)	-		-
Investment			
(i) Loan	8,10,04,357		8,32,79,357
Less: Provisions	8,10,04,357		8,32,79,357
(ii) Equity	92,25,000		92,25,000
Less: Diminution in value of	26,26,000	65,99,000	26,26,000
Receivables			
(i) Interest	29,97,69,021		29,97,69,021
(ii) FILD	2,09,06,07,789		2,09,06,07,789
	2,39,03,76,810		2,39,03,76,810
Less: Provisions	2,39,03,76,810	-	2,39,03,76,810
Total		**65,99,000**	**65,99,000**

TECHNOLOGY DEVELOPMENT BOARD

SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET AS ON 31st March, 2017

(Amount in Rupees)

SCHEDULE 10 - INVESTMENTS – OTHERS		Current Year		Previous Year
1. In Government Securities				
2. Other approved Securities				
3. Shares-Equity /Preference participation			28,46,72,726	28,46,72,726
4. Debentures and Bonds				
5. Subsidiaries and Joint Ventures				
6. Venture Funds				
a) UTI Ascent India Fund	29,92,72,098			
Less : Redemption	75,35,816	29,17,36,282		29,92,72,098
b) APIDC Venture Funds		30,00,00,000		30,00,00,000
c) Ventureast TeNet Fund	12,29,31,623			
Less : Redemption	91,69,046	11,37,62,577		12,29,31,623
d) GVFL	15,00,00,000			
Less Redemption	-	15,00,00,000		15,00,00,000
e) RVCF	13,25,92,511			
Less: Redemption	-	13,25,92,511		13,25,92,511
f) SIDBI VCF	12,77,29,711			
Add: Disbursement	1,31,02,303			
Less: Redemption	57,54,569	13,50,77,445		12,77,29,711
g) IvyCap Venture Trust Fund -1		25,00,00,000		25,00,00,000
h) Multi Sector Seed Capital Fund		20,00,00,000		20,00,00,000
i) SEAF India Agribusiness Fund	21,80,28,721			
Add: Disbursement	56,05,910	22,36,34,631		21,80,28,721
j) Indian Fund for Sustainable Energy (CIIE)	4,90,94,950			
Add: Disbursement	2,78,60,449	7,69,55,399	1,87,37,58,845	4,90,94,950
7. GITA				
Add: Disbursement		6,73,51,000		
		46,99,000	7,20,50,000	6,73,51,000
TOTAL			**2,23,04,81,571**	**2,20,16,73,340**

TECHNOLOGY DEVELOPMENT BOARD
SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEETAS ON 31st March, 2017

(Amount in Rupees)

SCHEDULE 11 - CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC.	Current Year		Previous Year
A. CURRENT ASSETS:			
1. Inventories:			
a) Stores and Spares			
b) Loose Tools			
c) Stock-in- trade			
i) Finished Goods			
ii) Work -in-progress			
iii) Raw Material	-	-	-
2. Sundry Debtors			
a) Debts Outstanding for a period exceeding six months			
b) Others			-
3. Cash balance in hand (including cheques/drafts and imprest)	-	69,604	1,23,557
4. Bank Balances:			
a) With Scheduled Banks:			
-On Current Accounts			
- On Savings Accounts – TDB (including EPF A/c)	25,03,27,087		30,63,97,743
- On Savings Accounts-INVENT- DFID	4,28,48,559	29,31,75,646	2,91,67,365
b) Short term Deposits with Scheduled Banks:			
- On Deposit Accounts	6,93,00,000		41,00,00,000
- On Deposit Accounts INVENT – DFID	-	6,93,00,000	2,20,00,000
c) With Non Scheduled Bank			
- On Current Accounts			
- On Savings Accounts			
- On Deposit Accounts			
5. Post Office - Savings Accounts			
TOTAL (A)		**36,25,45,250**	**76,76,88,665**

TECHNOLOGY DEVELOPMENT BOARD
SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEETAS ON 31st March, 2017

(Amount in Rupees)

SCHEDULE 11-CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC. (Contd.)	Current Year		Previous Year
B. LOANS, ADVANCES AND OTHER ASSETS:			
1. Loans:			
a) Staff			
b) Other Entities engaged in activities/objectives similar to that of the entity	-	-	-
c) Loan : Assistance to industrial concerns			
Opening	3,58,06,32,583		3,62,52,49,602
Add: During the year	99,80,00,000		26,98,50,000
Less: Repayment of loan	29,37,47,434		(30,89,14,668)
Less: Written Off	62,80,020		-
Less: Prior Period Adjustment	-	4,27,86,05,129	(55,52,351)
2. Advances and other amounts recoverable in cash or in kind or of value to be received			
a) Advance to staff members	-		-
b) Recovery from other Govt. departments	10,38,686		10,38,686
c) Others - Security Deposit	2,33,000		1,23,000
d) Others	7,680	12,79,366	11,268
3. Income Accrued:			
a) On Investments from Earmarked/Endowment Funds			
b) On Investments – Short Term Deposits	4,46,042		44,41,205
Short Term Deposits – INVENT DFID	-		1,40,457
c) On Loans and Advances	3,29,80,86,305		2,92,00,14,378
Less: Provision for doubtful recovery of interest	14,98,67,154		-
Less: Unrecoverable interest written off	58,93,351	3,14,27,71,842	
TOTAL (B)		**7,42,26,56,337**	**6,50,64,01,577**
TOTAL (A +B)		**7,78,52,01,587**	**7,27,40,90,242**

TECHNOLOGY DEVELOPMENT BOARD

SCHEDULE FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED 31st March, 2017

(Amount in Rupees)

SCHEDULE 12 - INCOME FROM SALES/SERVICES			
	Current Year		**Previous Year**
1. Income from Sales			
a) Sales of Finished Goods			
b) Sale of Raw Material			
c) Sale of Scraps	-	-	-
2. Income from Services			
a) Labour and Processing Charges			
b) Professional/Consultancy Services			
c) Agency Commission and Brokerage			
d) Maintenance Services (Equipment/Property)			
e) Others (Specify)			-
TOTAL	-	-	-

TECHNOLOGY DEVELOPMENT BOARD

SCHEDULE FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED 31st March, 2017

(Amount in Rupees)

SCHEDULE 13–GRANTS/SUBSIDIES (Irrevocable Grants & Subsidies Received)			
	Current Year		**Previous Year**
1) Central Government	30,30,00,000		30,00,00,000
2) State Government (s)			
3) Government Agencies			
4) Institutions / Welfare Bodies			
5) International Organizations			
6) Others (Specify)			
TOTAL	**30,30,00,000**	-	**30,00,00,000**

TECHNOLOGY DEVELOPMENT BOARD

SCHEDULE FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED 31st March, 2017

(Amount in Rupees)

SCHEDULE 14 - FEES/SUBSCRIPTINS

	Current Year		Previous Year
1) Entrance Fees	-	-	-
2) Annual Fees/Subscriptions			
3) Seminar/Program Fees	-	-	-
4) Consultancy Fees	-	-	-
TOTAL	-	-	-

Note: Accounting Policies towards each item are to be disclosed

TECHNOLOGY DEVELOPMENT BOARD

SCHEDULE FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED 31st March, 2017

(Amount in rupees)

SCHEDULE 15- INCOME FROM INVESTMENTS

(Income on Invest. From Earmarked/Endowment Funds transferred to Funds)

	Investment from Earmarked Fund		Investment - Others
	Current Year	Previous Year	Current Year
1) Interest			
a) On Govt. Securities			
b) Other Bonds/Debentures			
2) Dividends			
a) On Shares			
b) On Mutual Fund Securities			
3) Rents	-	-	-
4) Other (Specify)	-	-	-
TOTAL			
TRANSFERRED TO EARMARKED/ ENDOWMENT FUNDS			

TECHNOLOGY DEVELOPMENT BOARD

SCHEDULE FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED 31st March, 2017

(Amount in Rupees)

SCHEDULE 16 – INCOME FROM ROYALTY , PUBLICATION ETC.

	Current Year		Previous Year
1) Income from Royalty		67,73,214	30,10,762
2) Royalty Accrued			-
Less: Royalty written off		-	-
3) Others (Specify)			
TOTAL		**67,73,214**	**30,10,762**

TECHNOLOGY DEVELOPMENT BOARD

SCHEDULE FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED 31st March, 2017

(Amount in rupees)

SCHEDULE 17- INTEREST EARNED

	Current Year		Previous Year
1) On Term Deposits:			
a) With Scheduled Banks (includes DFID)	3,10,26,143		3,60,83,803
b) With Non- Scheduled Banks	-		-
c) With Institutions	-		-
	-	3,10,26,143	-
2) On Savings Accounts:			
a) With Scheduled Banks	39,97,235		35,39,169
b) With Non- Scheduled Banks	-		-
c) Post Office Savings Accounts	-		-
d) Others	-	39,97,235	-
3) On Loans:			
a) Employees/Staff			
b) Loans assistance to industrial concerns		50,29,04,680	49,31,88,629
4) Interest on royalty		1,92,459	1,12,916
5) Interest on grants		6,39,152	1,60,588
TOTAL		**53,87,59,669**	**53,30,85,105**
Note - Tax Deducted at Source to be indicated			

TECHNOLOGY DEVELOPMENT BOARD

SCHEDULE FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED 31st March, 2017

(Amount in Rupees)

SCHEDULE 18–OTHER INCOME

	Current Year		Previous Year
1) Profit on Sale/disposal of Assets:			
a) Owned assets - UTI			
b) Assets acquired out of grants or received free of cost		-	(8,17,702)
2) Profits on redemption of units		-	-
3) Dividend		48,00,853	14,79,656
4) Miscellaneous Income		1,13,877	80,395
5) Fees of Miscellaneous Services			
6) Donations		1,03,000	22,000
7) Income from Venture Fund		-	-
TOTAL		**50,17,730**	**7,64,349**

TECHNOLOGY DEVELOPMENT BOARD

SCHEDULE FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED 31st March, 2017

(Amount in Rupees)

SCHEDULE 19 – INCREASE/(DECREASE) STOCK OF FINISHED GOODS & WORK IN PROGRESS	Current Year		Previous Year
a) Closing Stock:			
- Finished Goods			
- Work – in - progress	-	-	-
b) Less: Opening Stock			
- Finished Goods			
- Work – in - progress	-	-	-
NET INCREASE / (DECREASE) [a-b]	-	-	-

TECHNOLOGY DEVELOPMENT BOARD

SCHEDULE FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED 31st March, 2017

(Amount in Rupees)

SCHEDULE 20–ESTABLISHMENT EXPENSES	Current Year		Previous Year
a) Salaries and Wages	1,89,05,061		1,54,27,064
b) Allowances and Bonus	-		-
c) Contribution to Provident Fund	19,65,154		17,33,511
d) Contribution to Other Fund	-		-
e) Staff Welfare Expenses	99,600		39,600
f) Expenses on Employees' Retir. and terminal Benefits	16,41,175		6,15,981
g) Reimbursement of medical charges	3,04,423		5,85,129
h) Gratuity	76,297		61,081
TOTAL		**2,29,91,710**	**1,84,62,366**

TECHNOLOGY DEVELOPMENT BOARD

SCHEDULE FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED 31st March, 2017

(Amount in Rupees)

SCHEDULE 21–OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES ETC.		Current Year	Previous Year
a) National Award		30,00,000	10,00,000
b) Legal charges		1,11,72,043	96,28,843
c) Assets Management Fees		1,86,66,737	2,29,00,023
d) Bank Charges		-	4,865
e) TDS and Interest		179	-
f) Loss on sale of assets		59,247	-
g) Repairs and maintenance		5,59,344	4,44,139
h) Postage & stamps		1,48,074	1,53,318
i) Technology Day Expenditure		29,93,330	16,92,864
j) Vehicles Running and Maintenance		76,410	83,766
k) Telephone and Communication Charges		24,65,020	8,27,821
l) Printing, Stationary & Consumables		9,10,915	11,67,441
m) Travelling and Conveyance Expenses			
a) Domestic	25,88,957	-	-
b) Abroad	4,18,165	-	
c) Experts	25,11,072	55,18,194	26,37,086
n) Library books and periodical		2,160	2,975
o) TA / DA / fee to Board members		1,80,401	1,100
p) Auditors Remuneration		80,000	80,000
q) Hospitality Expenses		1,53,841	2,21,907
r) Meeting Expenses		9,97,836	9,35,498
s) Professional Charges		23,57,667	11,80,500
t) – Provision for Bad and Doubtful Debts / Advances (Ref. Note 25 (11))		14,98,67,154	-
- Irrecoverable balance w/off – Interest on loans not recoverable (Ref Note 25 (10))		58,93,351	-
u) Devaluation of Equity		6,70,096	-
v) Misc. Expenses		8,69,107	9,84,222
w) Newspaper & Magazine		42,163	14,821
x) Advertisement and Publicity		89,13,954	43,75,502
y) Board Expenses & fees		1,46,455	1,12,722
z) Rent		55,000	-
TOTAL		**21,57,98,678**	**4,84,49,413**

TECHNOLOGY DEVELOPMENT BOARD

SCHEDULE FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED 31st March, 2017

(Amount in Rupees)

SCHEDULE 22 – EXPENDITURE ON GRANTS	Current Year	Previous Year
1) Grants given to Institutions / Organizations		
(i) Incubators	5,94,00,000	11,09,89,391
(ii) Other agencies	-	-
2) Subsidies given to Institutions / Organizations		
TOTAL	**5,94,00,000**	**11,09,89,391**
Note: Name of the Entities, their Activities along with the amount of Grants/Subsidies are to be disclosed		

TECHNOLOGY DEVELOPMENT BOARD

SCHEDULE FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED 31st March, 2017

(Amount in Rupees)

SCHEDULE 23 – INTEREST	Current Year	Previous Year
a) On Fixed Loans		
b) On Other Loans (including Bank Charges)		
c) Others (Specify)		
TOTAL	- -	

Schedule – 24

Significant Accounting Policies and Notes on Accounts-2016-17

A. Significant Accounting Policies

1. Receipts and Payments Accounts is prepared from the cash receipt journal and is a summary of cash transactions under various heads. It records receipts and payments of both capital and revenue nature.

2. Income and Expenditure Account is the summary of incomes and expenditures of the year. It is prepared both on cash and on accrual basis. It records income and expenditure of revenue nature only. The accrued interest earned on the loan amount disbursed is accounted for in the year in which the loan installment is released; however, the interest is actually receivable after the projects have been completed in accordance with the terms and conditions of the respective loan agreements. Provision of expenses due but not paid are not make in the accounts for the year except for Staff Dues and Audit Fess.

3. Depreciation on fixed assets is provided on the basis and rates prescribed under the Income Tax Act, 1961, on diminishing balance method. No depreciation is provided on the fixed Assets acquired/sold/transferred/discarded during the financial year. Addition in fixed assets are accounted at the cost of acquisition.

4. Royalty payments are taken on receipt basis in Receipts and Payments Account and Balance Sheet.

5. Government grants are recognized on receipt basis. Unspent balances are not to be refunded to the Government of India as the grants released by the Government are credited to the Fund for Technology Development and Application in terms of section 9(1)(a) of the Technology Development Board Act, 1995 and thus there is no such requirement of refund. No amount is, therefore, due for refund to the Government of India.

6. In terms of section 9(1) of the Technology Development Board Act, 1995, recoveries made of the amounts granted from the Fund for Technology Development and Application, receipt of interest on loans, royalty, donations and sums received from any other source are credited to the Fund. Keeping this provision in view, the Balance Sheet has been prepared.

7. The balance sheet of Earmarked/ Endowment funds (Venture Capital Funds) maintained by IDBI has indicated the following:-

a) The balance sheet is prepared on accrual basis except for income/expenditure in respect royalty, management fee and penal interest thereon, which are recognized on actual receipt/ payment.

b) The valuation of assets/ loans/ investments have been carried at the assessment value by IDBI (Fund manager) and the provision for reducing the book value of the assets is recorded as per the notes provided in the financial statements.

c) As per the Notes to Balance Sheet, there is no change in the customer outstanding / recovery i.e.: the amount recoverable from the customer would include the amount as per accord interest/ additional interest in Memorandum Books. Further write off of bad loans including accrued interest outstanding shall be done where the recovery process has reached a closure and no further repayments are expected from the loan accounts and the same have been approved for write off by the Board.

d) The financial statements of IDBI (VCF) are to be read with other notes and explanations attached with the Balance Sheet provided by them. The financial statements and notes to accounts have been taken on record as independently certified by IDBI and the audit report thereon.

8. Fund balances are kept in short term deposits in nationalized banks. Interest on short term deposits is reflected in the Receipts and Payments Account and Balance Sheet.

9. The investments in companies are stated at cost price. As per the mandate of TDB, the investments are not held for capital appreciation in the strict sense or for any other benefit to TDB, the shares are held at cost of acquisition till they are finally realized. However any permanent decline in the fair value of the investments so held due to the winding up or dissolution of the respective company or any other reason, the value of decline is charged to the income & expenditure account.

10. In the case of default, rescheduling agreement(s) whatsoever done are set aside in accordance with the terms and conditions of the Loan Agreement and balances in account are restored the original agreement. This may result in increase of outstanding amount of the borrower due to reverting back to the original agreement.

11. In the case where borrower is unable to pay the loan / interest amount as per the terms of loan agreement and when the dispute arising out of noncompliance of the loan agreement and consequently matter is referred to arbitration. In such instance the outstanding amounts of loan and interest is frozen on the date of reference to arbitration. Further provisioning or adjustment in the outstanding interest is made only after the award is passed in accordance with the award conditions.

12. In the case where the borrower has defaulted in repayment of its loan and interest as per loan agreement and has since gone into liquidation, booking of interest has not been restricted to the date of liquidation. Final provision for write off is made for principal and interest after receipt of final payment form the Official Liquidator since the right to claim interest up to the date of recovery is maintained by TDB.

13. In case of default by a borrower and the subsequent passing of an Arbitration Award, the restatement of loan and interest and also the charging of interest is done as per the award. This may result in decrease/ increase of outstanding amount of interest due from the borrower.

14. In the case of start of Arbitration proceedings, the charge of Interest is discontinued from the date of the start of the proceedings till the award is passed. After the award, other conditions remaining constant, the loan and interest thereon is accounted as per award.

15. In case funds have not been released for the full agreed amount and the time bound repayment schedule is active, interest is calculated on the basis of the amount released at the rate applicable as per agreement.

16. Investments with Venture Funds other Seed funds, are carried at cost. Since the Funds are continuously evolving in terms its activities and is an ongoing concern, no permanent change in the value of the investment is envisaged or provided. Income / Loss is recognized in the Venture Fund Investments either on closure of the funds or disbursement of income during the tenure of the fund.

17. Unless otherwise agreed to by TDB, the payment received from a borrower shall be accounted towards such dues in the following order,viz., Interest including additional interest; further interest and liquidated damages on defaulted amount; repayment instalments of principal due and payable or in the manner as decided and approved by the Board.

18. Stock verification is done on annual basis.

19. Figures are rounded off to the nearest rupee.

Notes on Accounts

1. TDB received Rs. 3030 lakhs (P.Y. Rs. 3000 lakhs) as grant during the financial year 2016-17.

2. Technology Development Board has an overdue loan repayment (amount due but not received) amounting to Rs. 233.59 crore (P.Y. Rs. 242.59 crore) as on 31st March, 2017. In addition, simple interest of Rs. 94.02 crore (P.Y. Rs. 92.62 crore), additional interest on loan amounting to Rs. 170.60 crore (P.Y. Rs.133.53 crore) and Rs. 49.04 crore (P.Y. Rs. 35.77 crore) as additional interest on simple interest, were also due.

3. With the change in the Government policy on Non-Performing Assets (NPA) and Insolvency & Bankruptcy Policy 2016, TDB is hopeful to recover substantial percentage of overdue accounts. Therefore, no provision for doubtful debts in such cases has been made or any impairment recognized.

4. Investment and valuation in Venture capital funds (VCF):

		Amount Invested								NAV	
Particulars	Par Value of Unit	Outstanding Amount as on 31.03.2016		Addition during the year		Redemption during the year		Closing Amount as on 31.03.2017		NAV as on 31.03.16	NAV as on 31.03.17
		Amount (Rs.)	Number of Units	Amount (Rs.)	Number of Units	Amount (Rs.)	Number of Units	Amount (Rs.)	Number of Units		
APIDC Venture capital fund pvt ltd	100,000	300,000,000	3,000	-	-	-	-	300,000,000	3,000	65,425.00	57,327.00
GVFL Limited, Ahmedabad	100,000	150,000,000	1,500	-	-	-	-	150,000,000	1,500	87,835.00	79,354.00
Ivy Cap venture Trust Fund	100,000	250,000,000	2,500		-	-	-	250,000,000	2,500	141,969.51	159,280.95
Fund/multi sector seed capital fund	10,000	200,000,000	20,000	-	-	-	-	200,000,000	20,000	20,755.00	18,551.00
SME Tech Fund- RVCF Trust II	100	132,592,511	1,325,925		-		-	132,592,511	1,325,925	191.62	120.21
SEAF India Agri business fund	500,000	218,028,721	436	5,605,910	11	-	-	223,634,631	447	419,171.00	394,294.00
SIDBI Venture capital Ltd - India Opportunities fund	1,000	127,729,711	127,730	13,102,303	13,102	5,754,569	5,754.57	135,077,445	135,077	881.63	800.35
Ascent India Fund	100	299,272,098	2,992,721	-	-	7,535,816	75,358.16	291,736,282	2,917,363	51.87	40.51
Venture East TeNet fund II	758	122,931,623	150,000		-	9,169,046	-	113,762,577	150,000	1,271.00	1,207.00
CIIE- Indian Fund for Sustainable Energy (GETrust)	100	49,094,950	490,950	27,860,449	278,604	-	-	76,955,399	769,554	98.71	99.22
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			

	NAV Value (in Rs)
Current Year	1,879,676,166.70
Previous Year	2,070,681,480.06

Note: The redemption from the Venture Funds during the year have been to the account of the capital contribution made by TDB. No Income on redemption has been received during the year. The income is recognized on the basis of the distribution by the fund in accordance with para 16 of Schedule 24 referred above.

5. TDB has signed agreement with M/s Global Innovation Technology Alliance (GITA), in joint venture with CII, in equity contribution of 51:49 respectively with a mandate to cover all key elements of innovation ecosystem that benefit industry and technology start-ups, with DST and other organizations. The equity participation of TDB in GITA is Rs. 7.35 crore. TDB release Rs. 7.21 crore up to 31st March 2017.

6. The following grant-in-aid distributed during the financial year.

S. No	Company's Name	Purpose	Amount (Rs. in lakhs)
1	M/s Amrita Technology Business incubator	Seed Support	30.00
2	M/s TIETS/TBI, IIT Kharagpur	Seed Support	30.00
3	M/s Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI),	Grant	500.00
4	M/s NIT -Calicut	Seed Support	20.00
5	M/s Indian Institute of Corporate Affairs	Grant	9.00
6	Indo French Centre for Promotion of Advanced Research (CEFIPRA)	Programme Management	5.00
	Total		**594.00**

7. The transfer of money receipts and liabilities outstanding in the books of the Industrial Development Bank of India (IDBI) on account of Venture Capital Fund (VCF) transactions pertaining to grants released by Government of India are required to be transferred to the Board as on 1st September 1996 in terms of section 10 of the Technology Development Board Act, 1995. The Balance Sheet of Venture Capital Fund of IDBI, vested with the Board, for the year ended 31st March 2017 has been incorporated in this year's Balance Sheet. The Balance Sheet also reflects previous year's figures relating to VCF of IDBI.

8. In accordance with the Agreement between Government of India through Department of Economic Affairs (DEA) and Department For International Development (DFID), Government of united Kingdom of Great Britain together with TDB bide Memorandum of Understanding dated 29.8.2013, it was agreed that the incubation component of "Innovative Ventures and Technologies for Development (INVENT)" programme will be Implemented and monitored with TDB, Department of Science & Technology, and government of India. The responsibility of TDB is to ensure that funds will be spent on approved activities required to deliver the overall outputs and outcomes of the project. TDB received funds amounting GBP 500000/- equivalent to Rs. 4, 17, 79,461/- under the agreement during the year for disbursement. TDB is obliged to hold this fund in a separate bank account and the interest accrued on the bank deposit are to be credited to the fund as part of additional funds available for the program and as fund manager to be released as per project guideline from time and submit progress report and audited accounts to DFID.

9. Devaluation in value of preference shares held in NICCO Corporation amounting to Rs. 1846.00 lakhs has occurred due to closure of the operations of the company based on the report of the asset managers. A loan amounting to Rs. 691.04 lakhs (including interest) is also outstanding from the company. However the investments have not been written off as the same are in the process of recovery. (Refer to Note 3, above)

10. The following amount has been written off during the year.

Companies Name	Written off	
		(Rs. in lakhs)
	Principal	Interest +Additional interest
M/s Midas	12.80	16.99
M/s Value pitch	50.00	21.20
M/ Angel Health	-	20.73
Total	**62.80**	**58.92**

11. Provision on amount of interest and additional interest of loan has been made against the following six companies, which have agreed to settled their outstanding/ dues as per proposal recommended by DRC and approved by the Sub Committee of the Board.

Companies Name	Provision of Interest & additional interest
	(Rs. in lakhs)
M/s Medirad	705.39
M/s Sudershan	152.04
M/s Logic Eastern	393.88
M/s Ind Swift Lab	129.35
M/s Coral Telecom	100.04
M/s Vizzitech	17.94
Total	**1498.67**

Previous year figures have regrouped and reclassified to make them comparable with current year figures.

-sd-

(DR. BINDU DEY)
SECRETARY
TECHNOLOGY DEVELOPMENT BOARD

-sd-

(PROF. ASHUTOSH SHARMA)
CHAIRPERSON
TECHNOLOGY DEVELOPMENT BOARD

SEPARATE AUDIT REPORT FOR THE YEAR 2016-17

Separate Audit Report of C&AG on the account of Technology Development Board, New Delhi for the year 2016-17

We have audited the attached Balance Sheet of the Technology Development Board (TDB) New Delhi as per 31st March, 2017 and the Income & Expenditure Account / Receipts & Payment Account for the year ended on that date under Section 19(2) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Power and Condition of Service) Act, 1971 read with Section 13(2) of the Technology Development Board Act, 1995 (No. 44 of 1995). These financial statements are the responsibility of the Board's management. Our responsibility is to express opinion on these financial statements based on our audit.

2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller and Auditor General of India on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc, Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules & Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency – cum-performance aspects, etc. , if any, are reported through Inspection Reports/Comptroller and Auditor General's Audit Report separately.

3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material mis-statements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the accounting and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the Management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4. Based on our audit, we report that:

i) We have obtained all the information's and explanations, which to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purpose of our audit;

ii) The Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account dealt with by this report have been drawn up in the Common format of Accounts approved by the Government of India, Ministry of Finance.

iii) In our opinion, proper books of Accounts and other relevant records have been maintained by the TDB, New Delhi except those stated in this audit report, in so far as it appears from the examination of such books.

(A) **Balance Sheet**

Current Assets, Loans, Advance etc-Schedule 11.

(i) TDB has shown a balance of –Nil- against Current Assets-Inventories- Stores and Spare whereas the scrutiny of Consumable Register for the year 2016-17 revealed that inventories worth ₹ 0 .43 lakh were available in stock register as on 31st March 2017. This resulted into understatement of current assets and overstatement of expenditure each by ₹ 0.43 lakhs.

(ii) TDB has shown an expenditure of ₹ 24.65 lakh on Telephone and Communication charges. This included ₹ 9.32 lakh as Advance payments for Internet Connection for the period 1.4.2017 to 31.3.2018 which needed to be shown under Current Assets as Advance Payments. This resulted into understatement of current assets and overstatement of expenditure each by ₹ 9.32 lakh.

(B) Income & Expenditure Account

1. Expenditure

(a) Other Administrative Expenses etc. – Schedule 21

(i) The Unpaid Expenditure of ₹ 0.22 lakh on account of payment of Telephone Expenses for 2016-17 was neither accounted for as 'Outstanding Expenses' nor shown in liabilities in Schedule-7 "Current Liabilities and Provision". This resulted in understatement of expenditure as well as liabilities by ₹ 0.22 lakh

(ii) Expenditure incurred towards payment of Assets Management Fees of ₹ 23.61 lakh for 2015-16 was erroneously booked as current year expenditure leading to overstatement of Expenditure and understatement of Prior period expenditure by ₹ 23.61 lakh.

(iii) TDB has shown ₹ 0.32 lakh as payment of Telephone charges for the period 2015-16 under Current year expenditure. This resulted in overstatement of current year expenditure and understatement of prior period expenditure by ₹ 0.32 lakh.

(iv) TDB has booked an amount of ₹ 16.33 lakh as payment of legal charges for the year 2015-16 under the current year expenditure. This has resulted in overstatement of current year expenditure and understatement of prior period expenditure each by ₹ 16.33 lakh.

(b) Establishment Expenses – Schedule 20

The establishment expenditure of ₹ 14.97 lakh pertaining to previous year was included in current year expenditure. Similarly, the unpaid expenses of ₹ 17.27 lakh on account of March 2017 salary paid in April 2017 was not accounted for. The above transaction had resulted in understatement of expenditure and Prior Period expenditure by ₹ 2.31 lakh and ₹ 14.97 lakh respectively, besides under-statement of liabilities to the extent of ₹ 17.27 lakh.

(c) Grant- in –aid:

TDB receives grants from the Department of Science and Technology (DST) out of the R&D Cess levied and collected by the Government at the rate of five percent on payments made towards import of technology. TDB had received a grant of ₹ 3030.00 lakh from the DST during 2016-17.

In addition to opening balance of Cash/Bank of ₹ 7676.89 lakh, an amount of ₹ 7901.49 lakh was received/accrued to the TDB as interest on short term deposits/loans/royalty/grants, repayment of loans, royalty, income from venture funds, dividend, guarantee etc. during the year 2016-17. After making a total payment of ₹ 11952.93 lakh from investments, establishment/office expenses and disbursement of loans/grants etc., ₹ 3625.45 lakh was shown as unspent balance as on 31st March 2017.

(C) General

1. Investments-Others

(i) **(Schedule 10- ₹ 22304.82 lakh) and investments from Earmarked/Endowment Funds (schedule 9-₹ 65.99 lakh)**

The above included investments of ₹ 28.47 lakh in shares-Equity/Preference participation and ₹ 65.99 lakh on Investments from Earmarked/ endowment Funds through Venture Capital Fund of IDBI. TDB had adopted two different routes/policies for treatment of Investment in shares and Earmarked/Endowment Fund as the value of Equity and Loan was evaluated as ₹ 65.99 lakh after diminution in the value of investment by ₹ 26.26 lakh in case of redemption of investment. However, the policy of diminution of redemption value was not adopted for investments.

(ii) **Non-conversion of investment in Equity**

As per Schedule-10 "Investments" annexed to the Balance Sheet, an amount of ₹ 28.47 crore was shown under the head 'Shares-Equity participation' which included investment of ₹ 156.18 lakh in 107798 equity shares of M/s Reva Electric Car Company Pvt. Ltd. @ ₹ 144.88 per share acquired in March 2007. Since, the company was acquired by Mahindra Group in May 2010 and converted into a public limited company namely, M/s Mahindra Reva Electric Vehicles Ltd. in December 2015, the shares held by TDB were needed to be exchanged with the equity shares of newly formed/converted public limited company.

TDB in September 2017 in its 59th Board's meeting decided to wait for some more time as M/s Mahindra & Mahindra Limited offeredto buy back equity shares of REVA at a price of ₹ 25.90 per sharewhich was on a very lower side.

(iii) Non-provisioning for doubtful Loans to various companies.

As per the annual accounts, Principal amount of ₹ 427.86 crore was outstanding against 100 companies. Out of this, 61 such concerns, with aggregated overdue loans amounting to ₹ 233.59 crore, have defaulted in repayment of their loans liabilities towards TDB.

Besides above, an amount of ₹ 329.81 crore was shown in the accounts as interest accrued till 31st March 2017 which included an amount of ₹ 313.66 crore as overdue for recovery from these companies.

The above position revealed that the overdue and unrecoverable assets have inflated the loan portfolio of the TDB as shown under Current Assets.TDB has now made interest provision of six companies amounting to ₹ 14.99 crore.

While analyzing the status of loans becoming due for repayment from the companies, it was revealed that almost every company/ firm defaulted in the repayment of loan and interest where loans became due w.e.f. 1998-99 onwards.Out of 100 companies, 61companies defaulted in repayment of interest amounting to ₹ 313.66 crores.

The above position revealed that the overdue and irrecoverable assets has inflated the loan portfolio of the TDB shown under Current Assets for which a suitable provision needed be made in the annual accounts for depiction of the correct picture of these doubtful and unrecoverable loans and huge amount of interest accrued thereon. In view of the above, the correctness of outstanding loans and advances could not be verified in audit.

(D) **Management Letter :** NIL

(i) Subject to our observations in the preceding paragraph, we report that the Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Accounts dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.

(ii) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts, and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure to this Audit Report give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India.

a. In so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of Affairs of the TDB as at 31 March, 2017; and

b. In so far as it relates to Income & Expenditure Account of the surplus for the year ended on that date.

For and on behalf of C&AG of India

Manish Kumar

Principal Director of Audit
(Scientific Departments)

Place: New Delhi
Date:

Annexure – I to Audit Report

1. Adequacy of Internal Audit System

Internal Audit of the Board was required to be conducted by the internal audit wing of Principal Pay & Accounts Office of the Department of Science & Technology, New Delhi which was completed upto March 2016. A total number of 17 paras (two pertained to the period 2008-10 to 2011-13 and 15 pertained to the period 2013-16) were outstanding till date (September 2017).

2. Adequacy of Internal Control System

Following deficiencies in relation to internal control system were observed in audit: -

(i) Non-maintenance of record of assets created out of Grants for creation of Capital Assets

Assets created out of Grants-in-aid for creation of capital assets are required to be returned to the Board after completion of the project, unless approval of the Board was obtained by the grantee institution for keeping the same. Even the disposal of such assets by the grantee institutes requires prior approval of the Board when they become obsolete or unserviceable. ***However, the board did not maintain any record of these assets created out of grants provided for creation of capital assets to various grantee institutions.***

(ii) Non-maintenance of the register of grants released by the board

As per rule 234 of the GFRs 2017, a Register of Grants needs to be prepared by the sanctioning authority as per Form GFR–21, however the same was not being maintained despite release of grants-in-aid amounting to ₹ 2951.93 crore during the period from 2011-12 to 2016-17 by the Board.

(iii) The provisional Utilisation Certificate(s) for the financial year 2016-17 in respect of the grants-in-aid received by the Board from DST were sent to DST as per Form 12-A (under Rule 238) of GFRs 2017.

(iv) Monitoring of Utilisation Certificates

Rule 238 of GFRs 2017 provided that a certificate of actual utilization of the grant received for the purpose for which it was sanction in form GFR 12-A should be insisted upon which

should be submitted within twelve months of the closure of the financial year by the institution/organization concurred. However due to weak monitoring of the UCs, 17 number of UCs related to pending grants-in-aid of ₹ 5.78 crore pertaining from 2014-15 were outstanding till March 2017.

(v) Bank Reconciliation Statement

TDB furnished the bank reconciliation statement for the month of March 2017 which revealed only one cheque amounting to ₹ 2500/- was outstanding prior to March 2017 and two cheques amounting to ₹ 13,133/- pertaining to the period March 2017 were pending as of August 2017 which have become time barred.

3. System of Physical Verification of Assets/inventories

The Physical verification of Assets as well as Consumable items and Materials has been carried out for the period upto 2016-17 and no discrepancy was reported.

4. Regularity in payment of statutory dues:

TDB was regular in payment of Statutory Dues.

Dy. Director (Insp.)